3 राजधानी
दिल्ली में महंगा होगा पार्किंग शुल्क

6 अभिमत
कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव

10 राष्ट्रीय
सदस्यों ने कई प्रावधानों पर उठाए सवाल

11 विदेश
अमेरिका में हनुमान की विशाल मूर्ति स्थापित

RNI NO.DELHI/2012/48369
वर्ष 12 अंक 282
नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

कभी कभार आपको थोड़े से भाग्य की जरूरत होती है
स्पोर्ट्स-12

एफआईआर में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

कोलकाता में डॉक्टर रेप और हत्या मामला

राजेश कुमार। नई दिल्ली

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की अप्राकृतिक मौत दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की देरी को 'बेहद परेशान करने वाला' करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को '14 घंटे की देरी' के बारे में कड़ी फटकार लगाई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में देरी और पुलिस द्वारा आयोजित कानूनी औपचारिकताओं के अनुक्रम और समय पर सवाल उठाते हुए स्थिति रिपोर्ट में विसंगतियों को चिह्नित किया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा की तीन पीठ के न्यायाधीशों का हिस्सा हैं, ने कहा कि उन्होंने अपने 30 वर्षों के जीवन में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली इस तरह की प्रक्रिया नहीं देखी है। .

इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि अप्राकृतिक मौत के रूप में मामला दर्ज करने से पहले 9 अगस्त को शाम 6.10 बजे से 7.10 बजे के बीच पीड़िता का पोस्टमॉर्टम किया गया था, शीर्ष अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की 'अस्पष्ट' देरी पर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की। पीठ ने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि पोस्टमार्टम 9 अगस्त को शाम 6.10 बजे किया गया और फिर भी अप्राकृतिक मौत की सूचना ताला पुलिस स्टेशन को 9 अगस्त को रात 11.30 बजे पोस्टमॉर्टम के बाद भेजी गई और रात 11.45 बजे एफआईआर दर्ज की गई। यह बेहद परेशान करने वाली बात है। पुलिस द्वारा की जाने वाली कानूनी औपचारिकताओं के अनुक्रम और समय पर सवाल उठाते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, आपके राज्य (पश्चिम बंगाल) द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी है जो मैंने अपने जीवन के 30 वर्षों में नहीं देखी है। पहली बात यह है कि क्या यह सच है कि यूडी (अप्राकृतिक मृत्यु) सुबह 10.30 बजे (सुबह 10.30 बजे) दर्ज की गई थी? दूसरा, यह सहायक अधीक्षक नॉन मेडिकल (व्यक्ति) कौन है, इसका आचरण भी बेहद संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया?

इसने कोलकाता पुलिस अधिकारी को, जिन्होंने देश को झकझोर देने वाली घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज की थी, अगली सुनवाई में पेश होने और प्रविष्टि के समय का खुलासा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई है। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि अपराध स्थल को बदल दिया गया और छेड़छाड़ की गई, जिससे मामले में आगे की जांच में बाधा उत्पन्न हुई। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि प्रशिक्षु डॉक्टर के दाह संस्कार के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि कोलकाता के अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ-साथ पीड़िता के सहकर्मियों ने भी वीडियोग्राफी की मांग की थी, जिसका मतलब है कि उन्हें भी लगा कि कोई ढका हुआ है- जिस पर पश्चिम बंगाल के वकील ने जवाब दिया, 'हर चीज़ की वीडियोग्राफी की गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है।' मेहता ने कहा (पीड़िता के) पिता एफआईआर दर्ज करने पर जोर देते हैं। अस्पताल एफआईआर दर्ज नहीं कराता है। पिता ने जिद की और एफआईआर दर्ज हुई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। यह कवर करने का एक प्रयास है। हम अंदर गए पांचवें दिन जांच के लिए, (शेष पृष्ठ 9)

नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आंदोलनरत डॉक्टर। हालांकि उच्चतम न्यायालय के अनुरोध के बाद डॉक्टरों ने जारी हड़ताल वापस ले ली। फोटोः रंजन डिमरी

सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौटे डॉक्टर

राजेश कुमार। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कोलकाता बलात्कार और हत्या की घटना पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके दोबारा काम पर लौटने के बाद कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि न्यायाधीश और डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते क्योंकि वे जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों से निपटते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, 'न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। क्या हम (न्यायाधीश) अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद, एम्स, दिल्ली आरएमएल अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रेजीडेंट डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे अपनी 11 दिवसीय हड़ताल वापस ले रहे हैं। रेजी़डेंट डॉक्टर्स, ऐसोसिएशन, एम्स नई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम सुप्रीम कोर्ट की अपील और आरजी कार घटना में हस्तक्षेप और डॉक्टरों की सुरक्षा के आश्वासन के बाद ड्यूटी को फिर से शुरू कर रहे हैं। हम अदालत की कार्रवाई की सराहना (शेष पृष्ठ 9)

लोहरदगा जिले में अल कायदा से जुड़े एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी।

अल कायदा का माड्यूल ध्वस्त तीन राज्यों से 14 पकड़े गए

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बृहस्पतिवार को झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार करने और तीन अन्य को हिरासत में लेने के बाद अल कायदा से प्रेरित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राजस्थान के भिवाड़ी से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जब वे हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। उनकी पहचान झारखंड के मूल निवासी हसन अंसारी, इनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारूक और शाहबाज अंसारी के रूप में की गई है। अधिकारी ने कहा, वे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में रह रहे थे। उनके पकड़े जाने के बाद, झारखंड के रांची से पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान डॉ. इशितयाक अहमद, मोतिउर, रिजवान, मुफ्ती रहमतुल्लाह और फैजान के रूप में की गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऑपरेशन चलाया था। दिल्ली पुलिस के एक बयान में कहा गया, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस बलों के सहयोग से दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा चलाए गए एक समन्वित, खुफिया आधारित ऑपरेशन में, अल कायदा (एक्यू) से प्रेरित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। आतंकी मॉड्यूल का लक्ष्य देश में 'खिलाफत' घोषित करना था और वह पूरे भारत में आतंकवादी (शेष पृष्ठ 9)

दिल्ली में ऑटो और टैक्सी हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

ऑटो-टैक्सी चालकों की दो दिवसीय हड़ताल से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के आह्वान पर दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार को चक्का जाम था। शुक्रवार को भी इसका असर देखा जा सकता है। आज हड़ताल की वजह से लोगों को ऑटो-टैक्सी बहुत कम मिली। काफी देर तक प्रयास करने के बाद ऑटो-टैक्सी मिलने के बाद उसके चालकों ने मनमाने किराया वसूला जो यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। अगर आपको को एनसीआर में किसी जरूरी काम से शुक्रवार को जाना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलें अन्यथा ऑटो-टैक्सी चालकों की हड़ताल परेशान कर सकती है। कुछ स्थानों पर टैक्सी चालकों और ऑटोरिक्शा चालकों को धमकाया गया और यात्रियों को उतारने के लिए कहा गया। टैक्सी और ऑटो यूनियनों ने कहा कि अपर्याप्त भुगतान के साथ-साथ एग्रीगेटर्स द्वारा मोटरसाइकिल टैक्सी सेवाएं शुरू किए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन (डीएटीटीसीयू) के अध्यक्ष किशन वर्मा ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 80 प्रतिशत ऑटोरिक्शा और टैक्सियां सड़कों से नदारद हैं। उन्होंने घोषणा की कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

वहीं, एक कैब चालक आदर्श तिवारी ने कहा, कंपनियां हमें हमारी सेवाओं के लिए बहुत कम भुगतान करती हैं। इसके कारण हम अपने वाहनों की किस्त भरने और अन्य खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपने परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कैब मिलने में देरी और बुकिंग रद्द होने के बारे में शिकायत की। सोशल मीडिया एक्स पर उपयोगकर्ता प्रशुष ने पोस्ट किया, पिछले 35 मिनट नोएडा में दिल्ली के लिए कैब लेने की कोशिश में गुजार दिए। ओला कैब, उबर इंडिया, रैपिडो बाइक ऐप में क्या समस्या है। मानसी पांडे ने कहा कि हड़ताल में भाग नहीं लेने वाले ऑटोरिक्शा चालकों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं अपने घर से अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी और ईस्ट ऑफ कैलाश के पास एक ऑटो लिया। पहले तो ऑटो मिलना मुश्किल था, लेकिन जब मुझे एक ऑटो मिला, तो चालक ने अधिक किराया मांगा। देरी के कारण मैं अधिक भुगतान करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन कुछ मीटर आगे पहुंचने पर लगभग पांच से 10 लोगों ने ऑटो रोक दिया और हड़ताल का हवाला देकर मुझे बाहर निकलने के लिए कहा। (शेष पृष्ठ 9)

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेकां में गठबंधन

मोहित कंधारी। जम्मू

पूर्व गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव पूर्व गठबंधन बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव 'एकजुट होकर' लड़ने का फैसला किया। अंततः समझौते पर हस्ताक्षर करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर स्थित मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टी द्वारा नई दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकार के साथ चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना के बारे में हवा में चल रही सभी अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव पूर्व गठबंधन के नियमों और शर्तों के अनुसार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। श्रीनगर में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के आवास पर दोनों पक्षों के बीच डील हुई। इस अहम बैठक में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद डॉ. अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास का दौरा किया, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की और चुनाव पूर्व गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक के तुरंत बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन अंतिम है, और आज शाम तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी। गठबंधन सही रास्ते पर है और भगवान की कृपा से यह अच्छा चलेगा। यह अंतिम है और आज शाम तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी।

नेकां अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस, नेकां और सीपीआई (एम) एकमत हैं और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि गठबंधन के सामूहिक प्रयासों से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल होने और देश की संस्थाओं और इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वालों को करारा जवाब देने के लिए सभी के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पार्टियों के नेताओं को यह तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एनसी घाटी में कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ने को तैयार है और जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी सीटें छोड़ने को तैयार है।

इस बीच, श्रीनगर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की उम्मीद कर रही थी लेकिन चुनावों की घोषणा कर दी गई जो एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बहाल होगा। उन्होंने दोहराया कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि किसी राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।राहुल ने कहा, मैंने केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यों में परिवर्तित होते हुए सुना और देखा है लेकिन जम्मू-कश्मीर एक अपवाद है। हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में स्पष्ट कर (शेष पृष्ठ 9)

श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के घर पर बैठक करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

परंपरागत स्वागत

वारसॉ में पोलैंड के अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए

असम ने मुस्लिम विवाह, तलाक कानून पर बिल पेश किया

पायनियर समाचार सेवा। गुवाहाटी

असम सरकार ने बृहस्पतिवार को मुसलमानों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि इसमें समुदाय के नाबालिगों के विवाह की अनुमति देने की गुंजाइश है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम निरसन अध्यादेश 2024 को खत्म करने के लिए विधानसभा में असम निरसन विधेयक, 2024 पेश किया। उन्होंने निरसन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा, 21 वर्ष (पुरुष के मामले में) और 18 वर्ष (महिला के मामले में) से कम उम्र के इच्छित व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इसमें शायद ही कोई प्रावधान था और इसने अदालत में भारी मात्रा में मुकदमेबाजी को आकर्षित किया।

मोहन ने कहा, कम उम्र/नाबालिग विवाह के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी (मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा दुरुपयोग की गुंजाइश है और पार्टियों की सहमति के बिना जबरन विवाह आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था और पंजीकरण तंत्र अनौपचारिक था जिससे मानदंडों के गैर-अनुपालन की काफी गुंजाइश थी। मंत्री ने कहा, यह मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए तत्कालीन असम प्रांत के लिए ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अपनाया गया एक स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियम है। बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा (शेष पृष्ठ 9)

त्रिपुरा के बांध से बांग्लादेश में बाढ़ आने की खबर को भारत ने खारिज किया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में आई उन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने बांध को खोलने के कारण हुई है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि दोनों देशों के बीच आम नदियों में बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों पक्षों के लोगों को परेशानी हो रही है और इसे हल करने के लिए करीबी आपसी सहयोग की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा, हमने बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त होते देखी है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर स्थित जिलों में बाढ़ की वर्तमान स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित डंबूर बांध के फाटक खोलने के कारण उत्पन्न हुई है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उसने कहा, हम यह बताना चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में इस वर्ष की सबसे भारी बारिश हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ मुख्य रूप से बांध के नीचे की ओर इन बड़े जलग्रहण क्षेत्रों के पानी के कारण आई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डंबूर बांध (बांग्लादेश की)सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह कम ऊंचाई (करीब 30 मीटर) का बांध है, जो बिजली पैदा करता है और वह बिजली ग्रिड में जाती है जिससे बंग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलती है।

अगरतला के बाहरी इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करते त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा।

मंत्रालय ने कहा, करीब 120 किलोमीटर लंबे नदी के रास्ते में अमरपुर, सोनामुरा और सोनामुरा 2 में तीन जल-स्तर निगरानी स्थल हैं। पूरे त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के जिलों में 21 अगस्त से भारी बारिश जारी है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अधिक प्रवाह होने पर पानी स्वतः तरीके से छोड़ा जाता है। उसने कहा कि अमरपुर स्टेशन द्विपक्षीय प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत की ओर से वास्तविक समय में बाढ़ के आंकड़े भेजे जाते हैं। उसने कहा, 21 अगस्त को अपराह्न तीन बजे तक बांग्लादेश को बाढ़ के बढ़ते रुझान को दर्शाने वाले आंकड़े भेजे गए। शाम 6 बजे बाढ़ के कारण बिजली गुल हो गई, जिससे संचार में समस्या आई। मंत्रालय ने कहा, फिर भी, हमने डेटा के तत्काल प्रसारण के लिए बनाए गए अन्य माध्यमों से संचार बनाए रखने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश 54 आम सीमा पार नदियों को साझा करते हैं और नदी-जल सहयोग द्विपक्षीय जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने कहा, हम द्विपक्षीय परामर्श और तकनीकी चर्चाओं के माध्यम से जल संसाधनों और नदी जल प्रबंधन में मुद्दों और आपसी चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लाशों के बीच महिला से अश्लीलता

● पोस्टमॉर्टम हाउस में हुई घटना, लोग बोले- यहां शवों के साथ भी हैवानियत हो सकती है

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा में लाशों के बीच अश्लीलता का एक वीडियो सामने आया है। सेक्टर-94 में पोस्टमॉर्टम हाउस में रखे शवों के बीच एक युवक महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहा है।

अचानक पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में दिख रहा कि महिला विरोध कर रही है, लेकिन युवक उससे गलत हरकत कर रहा है।

आरोपी युवक पोस्टमॉर्टम हाउस का सफाई कर्मी बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसी हैवानियत देखकर आशंका है कि यहां शव भी सुरक्षित नहीं होंगे। जब पोस्टमॉर्टम हाउस में ही ऐसे लोग हैं तो वे लाशों के साथ हैवानियत कर सबूत मिटा सकते हैं। दो मिनट 22 सेकेंड के वीडियो में दिख रहा कि एक व्यक्ति चाय की दुकान से कैमरा ऑन कर पोस्टमॉर्टम हाउस के अंदर पहुंचता है। डीप फ्रीजर वाले रूम में एक सफाई कर्मी, महिला के साथ मिलता है। सफाई कर्मी वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से जमीन पर कुछ बिछाने के लिए मांगता है।

फिर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दूसरे कमरे से चादर लाकर सफाई कर्मी को देकर बाहर चला आता है। कुछ देर बाद जब वह दोबारा डीप फ्रीजर वाले रूम में जाता तो सफाई कर्मी महिला के साथ अश्लील हरकत करते मिला।

बताया जा रहा कि आरोपी सफाईकर्मी पहले दनकौर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात था। इस साल जून में पोस्टमॉर्टम हाउस में ड्यूटी लगाई गई थी। इन दिनों वह छुट्टी पर अपने घर गया है।

"वीडियो में दिखने वाले शख्स की पहचान कराई जा रही है। इस मामले में थाना सेक्टर-126 में शिकायत की गई है। अभी शिकायत अज्ञात व्यक्ति के नाम की गई है। नोडल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। गार्ड की संख्या बढ़ने और कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।"

-सुनील कुमार शर्मा (सीएमओ)

"मेरे पास अभी वीडियो और कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमॉर्टम हाउस में महिला कर्मचारी काम नहीं करती है। जाहिर है ये महिला बाहर से यहां आई थी। यहां रोजाना पांच से सात शवों के पोस्टमॉर्टम किए जाते है। इनमें हत्या, लूट, डकैती, रेप के बाद हत्या, आत्महत्या आदि करने वालों का शव होता है। अभी पोस्टमॉर्टम हाउस में दो शिफ्ट में दो गार्ड तैनात होते हैं।"

-जैसलाल (डिप्टी सीएमओ)

अवैध निर्माण पर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर

● मुक्त जमीन की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण हटाने का अभियान निरंतर जारी है। इस क्रम में गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक की अगुआई में सेक्टर-42 में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

अवैध निर्माण सेक्टर-42 के पांच प्रतिशत प्लाट पर किया गया था। यहां करीब 1 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया था। जिनका कॉमर्शियल प्रयोग किया जाने वाला था। इस जमीन की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये जमीन नोएडा की अधिग्रहीत जमीन है। ये जमीन आवासीय पर्पज के लिए है। इसका प्रयोग अवैध रूप से कॉमर्शियल किया जा रहा था। नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया। ऐसे में प्राधिकरण ने सुबह ड्राइव चलाकर यहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

इस दौरान प्राधिकरण के 50 कर्मचारियों के साथ दो जेसीबी रही। वहीं स्थानीय पुलिस मौजूद रही। लोगों ने हल्का विरोध किया। वहां मौजूद पुलिस ने बातचीत कर उनको समझा दिया। प्राधिकरण लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। अब तक करीब 6 लाख वर्गमीटर जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। जिसकी कीमत करीब 2 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। सीईओ ने स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो लोग भी निवेश कर रहे है वह पहले प्राधिकरण से लैंड की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले।

संक्षिप्त समाचार

जनसुनवाई के दौरान शिकायत सुनते अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश पी।

माल से भरे कंटेनर के साथ तीन लुटेरे गिरफ्तार

गाजियाबाद। मुरादनगर थाने के एसओ मुकेश सोलंकी की टीम ने डीसीपी रूरल सुरेंद्रनाथ तिवारी की स्वॉट टीम के सहयोग से 20 अगस्त की रात के ढ़ाई बजे के आस-पास हिंडन् नदी के पास से लूटे गये करोड़ों के माल, उपकरण व मशीनों से भरे कंटेनर को न केवल 16 घंटे के अंदर बरामद कर लिया बल्कि दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों के हाईवेज पर वाहनों को लूटने वाले गैंग के तीन लुटेरों को गिरफ्तार करके उक्त सनसनीखेज लूट का खुलासा भी कर दिया। सूत्रों के अनुसार एसओ मुकेश सोलंकी की टीम ने जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनके नाम इमाम उर्फ करीबा व शकील पहलवान निवासीगण बदरखा बागपत व ताज मौहम्मद उर्फ ताजू निवासी जोहड़ी बिनौली हैं। जबकि इनके फरार साथी का नाम शहजाद निवासी बदरखा है।

घर जा रही युवती से छेड़छाड़ और मारपीट

गाजियाबाद। गाजियाबाद के मोदीनगर में भोजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में घर आ रही युवती से दूसरे समुदाय के तीन युवकों ने अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवती को मारपीट कर घायल भी कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर की एक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति परिवार सहित रहते हैं। उनकी 21 वर्षीय भतीजी ने इसी साल बीए पास किया है। बताया जा रहा है कि देर शाम को युवती घर में काम करके अपने घर जा रही थी। जब वह बीच रास्ते में पहुंची, तो वहां पहले ही खड़े शाहनवाज, बिलाल, कैफ ने युवती पर अश्लील टिप्पणी कर दी। पहले तो युवती ने युवकों की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई, जब एक युवक ने हाथ पक? लिया और अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवकों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। युवती के चाचा ने इस बारे में भोजपुर थाने में तहरीर दी है। एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर शाहनावाज, कैफ, बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

मानसिक तनाव के चलते युवक ने की आत्महत्या

नोएडा। थाना सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि अखिलेश 29 वर्ष पुत्र राजकुमार मूल निवासी जनपद एटा हाल निवासी छीजारसी कॉलोनी ने बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों और मृतक के परिजनों से आत्महत्या के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं थाना बिसरख क्षेत्र में रहने वाले वीरू सक्सेना पुत्र सुरेश चंद्र सक्सेना उम्र 25 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मृतक गांव रोजा जलालपुर में रहता था। वह मूल रूप से जनपद बरेली का रहने वाला था। उन्होंने बताया की मौत के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है।

निर्माणाधीन सोसाइटी के ऑफिस में लगी आग

नोएडा। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक नार्थ आई सोसायटी के भूतल पर बने कार्यालय में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गयी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह नौ बजकर 25 मिनट पर नोएडा के सेक्टर-74 स्थित नॉर्थ आई निर्माणाधीन आवासीय भवन के भूतल पर बने रिसेप्शन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कारवाई करते हुऐ फायर सर्विस यूनिट को घटना स्थल पर रवाना किया गया। पांच गाड़ियों की मदद से आग को बुझा दिया गया।

सीबीआई जांच में घिरे थे आत्महत्या करने वाले ईडी अफसर आलोक

● ट्रेन से कटकर दी थी जान, ज्वैलर्स से 50 लाख मांगने में आया था नाम

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में ट्रेन से कटकर जान देने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आलोक रंजन सीबीआई जांच में घिरे हुए थे। मुंबई के छ्ज्वैलर्स से 50 लाख रुपए मांगने के मामले में उनका भी नाम सामने आ रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई दो बार आलोक रंजन से पूछताछ भी कर चुकी थी। संभवत- इसी वजह से वो तनाव में थे और अपना सिर रेल पटरी पर रखकर खुदकुशी कर ली।

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में गौशाला रेलवे फाटक है। यहां रेलवे ट्रैक पर 18 अगस्त की शाम 51 वर्षीय व्यक्ति की सिर कटी लाश बरामद हुई। जेब में ड्राइविंग लाइसेंस रखा मिला। इस पर काली बाड़ी दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि वे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ग्रांड सोसाइटी में रहते हैं। परिजनों ने आकर शव की पहचान कर ली। 19 अगस्त को शव का पोस्टमार्टम हुआ और वे शव को लेकर चले गए।

उन्होंने आलोक रंजन प्रोफाइल पुलिस को नहीं बताई। 21 अगस्त की शाम पता चला कि मरने वाले आलोक रंजन ईडी में अधिकारी थे। आलोक रंजन मूलत: बिहार में भागलपुर जिले के कस्बा कहलगांव के रहने वाले थे।

वो ईडी में प्रतिनियुक्ति पर आए थे और दिल्ली में तैनात थे। परिजनों ने पुलिस को बताया- आलोक रंजन 18 अगस्त की सुबह घर से बिना बताए निकल गए थे। उनके लापता होने पर बेटे अपूर्वम झा गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पहुंचे। पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी कर रही थी कि इसी बीच एक डेडबॉडी गौशाला रेलवे फाटक पर मिलने की खबर आ गई। परिजन जब सीधे पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे तो शव की पहचान आलोक रंजन के रूप में हुई।

नोएडा से बांदा जेल भेजा गया माफिया रवि काना

नोएडा। बदमाशों के बीच चलने वाले आपसी गैंगवार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 अपराधियों की जेल में बदलाव किया है। जिसमें नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना व गैंगस्टर सुंदर भाटी के भतीजे अनिल भाटी की भी जेल बदली गई है। अनिल भाटी को नोएडा की जेल से अंबेडकरनगर जिला जेल भेजा गया है। इसके अलावा शासन ने स्क्रैप माफिया रवि काना को नोएडा जेल से बांदा जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। जबकि नोएडा जेल में बंद जुगला को बहराइच की जेल में भेजा गया है। कुल 11 अपराधियों को इधर से उधर किया गया है।

जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश शासन ने यह बदलाव किए हैं। आशंका है कि भविष्य में कई और अपराधियों की जेल बदली जा सकती है। गौरतलब है कि गैंगस्टर रणदीप भाटी, सुंदर भाटी और रवि काना के बीच रंजिश चल रही है। अभी तक ग्रेटर नोएडा की लुकसर जेल में सुंदर भाटी का भतीजा अनिल भाटी बंद था। जबकि रणदीप भाटी गैंग का जुगला रणदीप गैंग का सक्रिय बदमाश है। जोकि इसी जेल में बंद था। वहीं रवि काना भी इसी जेल में बंद है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारियों को लेकर डीएम मनीष और पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों संग बैठक की।

शक के चलते तकिये से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या

● पांच साल के बेटे ने खोला हत्याकांड का राज

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक व्यक्ति ने तकिये से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे गांव और रिश्तेदारों को बताया कि बीमारी से मौत हुई है। लेकिन 3 दिन बाद मृतका के 5 साल के बेटे ने रिश्तेदारों को आंखों देखा घटनाक्रम बता दिया।

फिलहाल पुलिस ने पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका के भाई के अनुसार- हत्यारोपी पति उसके चरित्र पर शक करता था। अब मजिस्ट्रेट की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हापुड़ जिले में पिलखुवा के रहने वाले इमरान ने 8 साल पहले छोटी बहन रुखसार का निकाह गांव सलाई के रहने वाले शाहनवाज से किया था। परिवार में दो बच्चे अलीसा (7 साल) और उजैर उर्फ बबलू (5 साल) हैं। 19 अगस्त की रात रुखसार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति शाहनवाज ने ससुरालवालों को फोन पर सूचना दी कि रुखसार की बीमारी से मौत हो गई है। ससुरालवाले मसूरी में आए और शव को लेकर चले गए। हापुड़ में उन्होंने शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। मृतका के भाई इमरान ने बताया कि बहन की मौत के 5 दिन बाद 21 अगस्त को भांजे उजैर उर्फ बबलू ने बताया कि मेरे पापा ने रात को मारपीट करके अम्मी के मुंह पर तकिया रख दिया था।फिर उनके ऊपर बैठ गए थे। जिससे मेरी अम्मी की मृत्यु हो गई। शाहनवाज पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

बच्चों को पीटते महिला टीचर का वीडियो आया सामने

नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के डेरीन गुजरान गांव में एक प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर द्वारा बच्चों को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो सामने आया है। 52 सेकंड के इस वीडियो में महिला टीचर तीन बच्चों को डंडे और थप्पड़ से पीटते हुए साफ-साफ दिखाई दे रही हैं।

बच्चे दर्द और डर के मारे रो रहे हैं, जबकि टीचर उनकी पिटाई करती जा रही हैं। घटना 2 दिन पुरानी है। वीडियो को किसी अनजान व्यक्ति ने पोस्ट किया है।

जिसने आरोप लगाया है कि महिला टीचर रोजाना इसी तरह बच्चों को पीटती है। दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मंदिर की घंटी बजाने पर प्रदूषण का नोटिस

● पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सोशल मीडिया पर हुआ विरोध

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मंदिर की घंटी बजाने को लेकर ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी को नोटिस भेजा। जांच में घंटी की आवाज मानकों से अधिक मिली। बोर्ड ने अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन से घंटी की आवाज कम करने को कहा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस के बाद अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन ने सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप और नोटिस बोर्ड पर एक सूचना जारी की। इसमें कहा गया कि लोग घंटी धीरे बजाएं और ज्यादा देर तक न बजाएं। मामला सामने आने के बाद सोसाइटी के लोग नाराज हो गए। उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जमकर विरोध किया। सोशल मीडिया पर इसके विरोध में अभियान चलाया। मामले को तूल पकड़ता देख पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार देर रात घंटी धीमी बजाने का आदेश वापस ले लिया। मामला ग्रेटर नोएडा के गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी का है। गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी के 2 टावरों के बीच कॉमन एरिया में %हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर बना है। यहां सोसाइटी के लोग पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर में एक ब ?ी घंटी लगी है। पूजा करने आने वाले लोग घंटी बजाते हैं। घंटी की तेज आवाज से सोसाइटी के किसी सदस्य को परेशानी हो रही थी। इसकी शिकायत मुदित बंसल नाम की मेल आईडी से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को की गई। 30 जुलाई को शिकायत मिली। 5 अगस्त को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जांच की तो घंटी की आवाज मानकों से अधिक मिली। आवाज 72 डेसिबल थी, जबकि 55 डेसिबल से कम होनी चाहिए। जांच अफसरों ने बताया कि कई बार निगरानी करने के बाद अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर आवाज कम करने का आग्रह किया गया। इसके बाद भी वैसी ही स्थिति बनी रही। फिर नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर की घंटी की आवाज दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक हो रही है।

बकाया जमा नहीं करने वाले लीज डीड होगी रद्द

● नोएडा में 8 बिल्डरों पर 1171 करोड़ बकाया, अमिताभ कांत की सिफारिश का फायदा नहीं लिया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

अमिताभ कांत की सिफारिश का लाभ नहीं लेने वाले बिल्डर की लीज डीड रद्द की जाएगी। इनमें वे बिल्डर है, जिनको कई बार नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी बिल्डरों ने न तो कोई सहमति दी और न ही वे बैठक में शामिल हुए।

ऐसे करीब 8 बिल्डर है। जिनके प्रोजेक्ट में बायर्स रह भी रहे है। हालांकि बायर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा प्राधिकरण की ओर से आश्वस्त किया गया है। नोएडा में 57 बिल्डर परियोजना है।

इन पर 28 हजार करोड़ का बकाया था। बकाया वापस लाने और बायर्स की रजिस्ट्री के लिए कैबिनेट ने अमिताभ कांत की सिफारिश लागू की। 22 बिल्डर ने सिफारिश के तहत कुल बकाया का 25 प्रतिशत यानी 302.32 करोड़ जमा करा दिया। इससे 1148 बायर्स की रजिस्ट्री हो गई। 14 ऐसे है जिन्होंने सहमति दी लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया। वहीं, 15 बिल्डर वो जिन्होंने कुछ पैसा जमा किया। जबकि 8 वो है,

जिन्होंने न तो सहमति दी और न ही वो सामने आ रहे है। ऐसे 8 बिल्डरों के खिलाफ प्राधिकरण एक्शन लेने जा रहा है। इन सभी बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की ओर से नियुक्त सलाहकार कंपनी इन बिल्डर की अनसोल्ड इन्वेंट्री और संपत्ति खंगाल रही है। जिनको सीज किया जाएगा। इसके बाद नीलाम करके बकाया वसूला जाएगा। इन आठ बिल्डर पर 1171.94 करो? रुपए बकाया है। इन बिल्डरों को पहले फेज में इस बकाया का महज 25 प्रतिशत यानी 251.40 करो? रुपए जमा करना है। ये पैसा जमा होने से 533 बायर्स की रजिस्ट्री हो सकेगी। अगर ये बिल्डर पूरा 1171.94 करोड़ जमा करते है तो करीब 2123 बायर्स की रजिस्ट्री हो सकेगी।

आकड़ों को देखे तो इन 8 बिल्डरों 10328 यूनिट सेंक्शन है। जिसमें 9348 यूनिट बन चुकी है। 4850 यूनिट का ओसी जारी हो चुका है। इसमें 3839 की रजिस्ट्री हो चुकी है। बाकी काम अधूरा है। इन बिल्डरों की साइट पर प्राधिकरण पहले ही बोर्ड लगा चुका है। ऐसे में अब इन पर कार्रवाई होने जा रही है।

PUBLIC NOTICE

My Clients Sh. Gulshan Arora S/o Sant Lal & Smt. Manju Devi W/o Gulshan Arora both R/o D-57, Upper 2nd Floor, Syam Nagar, Vishnu Garden, P.O. Tilak Nagar, Distt: West Delhi, Delhi-110018, have severed/terminated all relations from their son KUSHAL ARORA and disinherited/disowned him from their all movable & immovable properties due to his behaviour, cruelty, and non-compliance. In future if any person deals with the aforesaid debarred person, that shall be his/her own risks and costs and my clients will not be responsible for the same in any manner.

SANTOSH KUMAR (ADVOCATE)
WZ-64A Mukherjee Park, Tilak Nagar, New Delhi-18

PUBLIC NOTICE

Be it known to the Public at large that my client Sh. Udal Singh S/o late Sh. Arjun Singh R/o House No.D-130, DCM Colony, Ibrahimpur Extn., Burari, Delhi-110036 has debarred his son namely Inderjeet and his wife Smt. Pooja from his relationship, moveable and immoveable properties with immediate effect due to their anti-social activities and mis-behaviour activities, not follow the advice of my client and also have not in his control. If any person deals with. them shall be responsible at his/her own risk and responsibility in future. My client is not responsible in any manner.

R.P. SINGH (Advocate) Ch. No.V-26,
Opp. SBI, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Sh. Yash Pal Mongia S/o Late Sh. Tehal Ram Mongia R/o AA-76, Shalimar Bagh, Delhi-110088 has disowned & disinherited his daughters (1) Mrs. Vandana Sachdeva W/o Sh. Bhavnesh Sachdeva & (2) Mrs. Puja Rajpal W/o Sh. Manish Rajpal from all his moveable & immovable properties & also severed all his relations with them owing to their rude, indifferent & unruly Behaviour. Whosoever deals with Vandana Sachdeva & Puja Rajpal in any manner, shall do so at his/her own risk & consequences. My client Sh. Yash Pal Mongia will not be responsible for any deal or action done by Vandana Sachdeva and Puja Rajpal in any manner whatsoever.

VIJAY MONGA (Advocate)
E-29/A, Vijay Nagar, Delhi-110009

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my clients Sh. Ashok Kumar Gupta, S/o: Sh. B.L. Gupta, and Smt. Beena Gupta, W/o: Sh. Ashok Kumar Gupta, both R/o. H. No. 149, 3rd Floor, Pocket-6, Sector-22, Rohini, Delhi-110086., has severed all their connections and relations and had debarred, disowned, disinherit their son Namely Aman Gupta and his wife namely Khushboo Gupta D/o: Ashok Anand, R/o: F-127, 3rd Floor, Block-C, Sudershan Park, Delhi. From all their Moveable and Immoveable properties due to his disobedience and misconduct, misbehaviour, adamant attitude, quarrelsome nature and being out of control. If anyone deals with them, he/she/they will do so at his/her/their own risk, cost and consequences. My clients shall not be responsible in any manner whatsoever for the same and shall have no liability and responsibilities.

Himanshu Sharma (Advocate) Ch.No. 88,
Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mr. Kaif Akram had acquired First and Second floor without, roof rights built on Property/Plot bearing No. 41, area measuring 30 sq. yrds., Khasra No. 249, situated at Village-Bindapur, Delhi, area abadi known as Colony, Janki Puri, Block-B, Uttam Nagar, New Delhi vide GPA dt. 01.10.2023 executed by Mohammad Akram Khan along with ATS & Will. Now Mr. Kaif Akram is the undisputed owner of the above said property.

OR

Any person/firm/institution/company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client

Ajay Kumar Giri (Advocate), H No. 26/161, Basement,
Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024.

सार्वजनिक सूचना

आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि श्री मनीष कुमार मनोचा, निर्मित द्वितीय मंजिल, बिना छत के अधिकारों के साथ, जिसका क्षेत्रफल 85 वर्ग गज है, जो कि सम्पूर्ण निर्मित संपत्ति प्रॉपर्टी नंबर 27/108/4-बी, खसरा नंबर 4044/3204/746, जो गांव चंदवाली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित है, को श्री हर नारायण लूथरा और श्री राघव लूथरा से खरीदने का इरादा रखते हैं। यह संपत्ति श्री जगदीश कुमार ने श्री कृष्ण लाल छात्रा से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री समझौता और वसीयत के माध्यम से दिनांक 16.04.1985, के माध्यम से खरीदी थी। इसके बाद, श्री जगदीश कुमार ने पूरी संपत्ति को (1) श्री हर नारायण लूथरा (अखंड 70% हिस्सेदारी) और (2) श्री राघव लूथरा (अखंड 30% हिस्सेदारी) को दिनांक 13.03.2023 बिक्री दस्तावेज के माध्यम से बेच दी। उक्त संपत्ति को आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है, जो एएफ 19, 20, 21 एफएफ आदित्य मॉल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद यूपी में स्थित है। यदि किसी व्यक्ति को संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो कृपया नोटिस की तिथि से 07 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत करें। उक्त आपत्ति को पंजीकृत डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर और ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उपर्युक्त के अनुसार दावा को संबंधित संपत्ति के संबंध में शून्य और अमान्य माना जाएगा।

अश्विनी कुमार (अधिवक्ता) चैबंर. नं. 122, तहसील कंपाउंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सी-21, ब्लॉक-सी, तीसरी मंजिल, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095.

LOST & FOUND

The property bearing number 101A Ground floor Pocket C Mayur Vihar Phase-2 New Delhi-110092 in the name of Late Janak Kamboj the original conveyance deed of said property bearing reg. no.duly registered as doc no.8083 addl. book 1, vol. 1242 pages 71-72 dated 29.09.2004 has been lost on 03/08/2024 while shopping in the market. Sharda Mehta 9811187770.

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients Sh. Surender Chauhan and his wife Savitri Devi Both R/o H.No. 1030, Gali No.18 Sahid Bagat Singh Colony, Karawal Nagar Delhi-110094, have severed all their relationship with his son Sh. Rahul Chauhan and his wife Suman Chauhan and another son Sh. Rohit Chauhan and his wife Anju Chauhan as they are no longer in their control. Any one dealing with them shall do so at his own risk and my clients shall not be held liable in any of their dealings with any third party in any transaction whatsoever.

Gajendra Kumar Chauhan (Advocate) Off:164-a Opp.
Gole Canteen Civil Wing,Tis Hazari Courts Delhi-110054.

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **वासुदेव गावडी प्रोपराइटर मेसर्स गोविंदा करियाना स्टोर, गोविंदा गावडी उर्फ गोविंदा, वर्षा गावडी उर्फ वर्षा और राजेश कुमार शर्मा (गारंटर)** को **10.12.2018** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLART00244701** की राशि **रू. 19,45,865/- (रूपये उन्नीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र)** और **10.12.2018** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **21.08.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 19,45,865/- (रूपये उन्नीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) 10.12.2018** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

बारहवीं मंजिल पर, आवासीय परिसर अपार्टमेंट नं.1204, सुपर एरिया माप 1450 स्क्वे. फीट, जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी पर इम्पीरिया मिराज में टॉवर-03 में, एक कार पार्किंग की जगह के साथ, प्लॉट नंबर जीएच-एफ 3, सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा-201301, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।

सही/-
दिनांक: 21.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गौतमबुद्ध नगर सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अंबरीश पांडे और अनुभा पांडे** को **30.11.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00300258** की राशि **रू. 7,25,849.32 (रूपये सात लाख पच्चीस हजार आठ सौ उनचास और बत्तीस पैसे मात्र)** और **16.11.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **21.08.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 7,25,849.32 (रूपये सात लाख पच्चीस हजार आठ सौ उनचास और बत्तीस पैसे मात्र) 16.11.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

स्काईटेक कलर्स एवेन्यू नामक परियोजना में टावर-ए की सत्रहवीं मंजिल पर, फ्लैट न. ए 1706 जिसका सुपर एरिया 870 स्क्वे. फीट, प्लॉट नं. जीएच-01/सी पर निर्मित, सेक्टर 10 में स्थित, ग्रेटर नोएडा - 201307, उत्तर प्रदेश।

सही/-
दिनांक: 21.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : ग्रेटर नोएडा सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

उपराज्यपाल ने 24 अस्पतालों के निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी

कहा, इन परियोजनाओं का टेंडर 3906.70 करोड़ रुपये का किया गया था

- इनकी लागत में लगभग 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

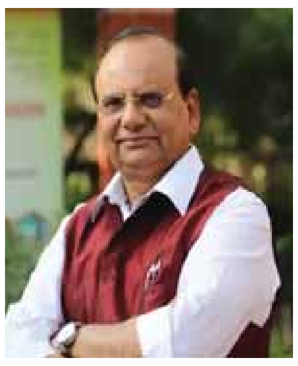

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 24 अस्पताल परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों पर हुई देरी और इन अस्पतालों के संचालन के लिए आवश्यक लगभग 38000 पदों से संबंधित औचित्य विहीन उपेक्षा पर नाराजगी आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री ने इन अस्पतालों का निर्माण तो शुरू करा दिया, परंतु उनके द्वारा इन पदों को भरना तो दूर, पिछले 5 वर्षों में इन पदों को सृजित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई प्रजेंटेशन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्लानिंग की कमी और वित्तीय कुप्रबंधन से संबंधित चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, अस्पताल परियोजनाओं का सिविल कंस्ट्रक्शन बिना किसी योजना, इक्यूपमेंट्स, मशीनरी और इसके लिए जरूरी मैनपावर की व्यवस्था किए बिना ही शुरू कर दिया गया।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह बिना सोचे-समझे शुरू की गई परियोजना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आपराधिक उपेक्षा के समान है। इन अस्पतालों के लिए न तो मैनपावर को मंजूरी दी गई, न ही बिस्तर, मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया।

उन्हें बताया गया कि इनके लिए कोई बजटीय प्रावधान भी नहीं किया गया। अस्पतालों के नाम पर, दिल्ली वाले कंक्रीट के जिन ढांचों को देखगें, वह 8000 करोड़ की लागत से बने, बिना इक्यूपमेंट्स, बिस्तरों, ऑपरेशन थियेटर्स, डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ के खोखे होंगे। आम आदमी पार्टी सरकार ने परियोजनाओं के लिए जरूरी स्टाफ, एचआर, मशीनरी और उपकरणों की आवश्यकता और आवश्यक वित्तीय आवंटन को ध्यान में रखे बिना ही, ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के तहत मौजूदा 13 अस्पतालों को पुनर्विकसित करने, 4 नए अस्पतालों को ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के तहत बनाने और आईसीयू अस्पताल के रूप में 7 मौजूदा अस्पतालों का फिर से पुन: विकसित करने की कवायद की थी।

कुल मिलाकर, निर्धारित समय से 6 से 7 वर्ष पीछे चल रहे इन निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए विभिन्न श्रेणियों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ के कुल 37,691 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी। ये पद अभी तक सृजित भी नहीं हुए हैं।

इन 24 परियोजनाओं का टेंडर 2019-2021 के दौरान 3906.70 करोड़ रुपये का किया गया था। इन अस्पतालों के निर्माण में प्रीफैब मटेरियल का मुख्य रूप से उपयोग होना था और 6 महीने से 1 वर्ष के अंदर इन सभी का निर्माण कार्य पूरा किया जाना था।

हालांकि, न केवल इन परियोजनाओं में देरी हुई है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए अब अतिरिक्त 3800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इससे इन परियोजनाओं की लागत में लगभग 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर इनके लिए जरूरी फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण आदि के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 4800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उपराज्यपाल को यह देखकर हैरान हुआ कि लगातार एक के बाद एक कई बजट पेश करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन अतिरिक्त लागतों का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया।

एलजी को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट मात्र 400 करोड़ रुपये है, जबकि बजट में, ठेकेदारों के पक्ष में मध्यस्थता से निपटाने के लिए आवंटित राशि 600 करोड़ रुपये थी। यह न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के एक और घोटाले की ओर इशारा कर रहा है, बल्कि ठेकेदारों के लाभ के लिए, पूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को ही दांव पर लगा दिया गया है।

भाजपा विधायकों ने एसीबी में दर्ज कराई शिकायत

- अस्पतालों के निर्माण में पर्याप्त धनराशि आवंटित होने के बावजूद, परियोजनाओं में देरी से लागत में वृद्धि हुई : विजेंद्र गुप्ता

नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में भाजपा विधायक एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा को शिकायती पत्र देते हुए।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के 24 अस्पतालों के निर्माण में देरी से लागत में हुई वृद्धि का मामला गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने एंटी करप्शन ब्रांच के प्रमुख मधुर वर्मा से मुलाकात की दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहन जांच की मांग करते हुए औपचारिक रूप से उन्हें शिकायत दी। प्रतिनिधिमंडल में विधायक अभय वर्मा, अजय महावर, अनिल बाजपेयी, ओ.पी. शर्मा और जितेंद्र महाजन शामिल थे।

गुप्ता ने बताया कि शिकायत में मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार का लेवल चौंकाने वाला है, स्वास्थ्य विभाग में कई परियोजनाओं में देरी हो रही है, बजट बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और जानबूझकर और संगठित तरीके से करदाताओं के पैसे की हेराफेरी की जा रही है। शिकायत में वित्तिय हेराफेरी, जानबूझकर देरी और बजट में हेरफेर करने का चिंताजनक पैटर्न सामने आया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आवंटित सार्वजनिक धन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी करना है।

वर्ष 2018-19 के बीच, केजरीवाल सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल थीं, जिनके लिए कुल 5,590 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। हालांकि, इतनी बड़ी राशि आवंटित होने के बावजूद, इन परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब हुआ और इनकी लागत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है।

गुप्ता ने बताया कि इनमें से, 6,800 बिस्तरों की क्षमता वाले 7 आईसीयू अस्पतालों के निर्माण में हुई देरी विशेष रूप से चिंता का विषय है। सितंबर 2021 से आरम्भ होकर अगले 6 महीने के भीतर इन अस्पतालों को तेजी से पूरा करने के लिए 1,125 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गए थे, लेकिन तीन साल बाद भी इनका निर्माण कार्य केवल 50 फीसदी ही पूरा हुआ है।

चौंकाने वाली बात यह है कि 800 करोड़ रुपये सरकार की खराब योजना और जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण बर्बाद होने के कगार पर है। इस वर्ष के बजट आवंटन में इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए धनराशि को बिना किसी कारण के छोड़ दिया गया है, जिससे यह परियोजना ठप हो गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि एक और चिंताजनक उदाहरण एलएनजेपी अस्पताल परियोजना का है, जहां लागत चार वर्षों में 465.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,125 करोड़ रुपये हो गई, और इस वृद्धि के लिए कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया गया है। इस परियोजना की लागत में जान बूझकर की गई वृद्धि से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का स्पष्ट संकेत मिलता है। विभाग के मंत्रियों ने बजट आवंटनों में हेरफेर कर भ्रष्टाचार के मौके पैदा किए हैं।

पॉली क्लिनिकों के निर्माण की योजना, जिसे मूल रूप से दिल्ली में हर किसी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 94 पोलीक्लीनिक्स में से केवल 52 का निर्माण किया गया है, फिर भी इस परियोजना की लागत 168.58 करोड़ रुपये से बढ़कर 220 करोड़ रुपये हो गई है। इनमें से अधिकांश पॉलीक्लिनिक अब खाली पड़े हैं, जो यह दर्शाता है कि यह परियोजना केवल सार्वजनिक धन की हेराफेरी के उद्देश्य से ही बनाई गई थी।

इसी तरह अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में दस वर्षों की देरी भी स्वास्थ्य विभाग में छाए भ्रष्टाचार का एक अन्य बड़ा उदाहरण है। 2016 में, इस महत्वपूर्ण योजना को अस्पतालों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए डिजाइन किया गया था, इसे जानबूझकर ठप रखा गया है।

छात्रों की हड़ताल 12वें दिन भी रही जारी, कक्षाओं का किया बहिष्कार

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल 12वें दिन भी जारी रखी और कक्षाओं का बहिष्कार किया।

हड़ताल का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। कुछ विद्यालयों, विशेषकर संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्यालय के केवल कुछ ही विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित हुए, जबकि अन्य सभी कक्षाएं स्थगित रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जेएनयू इकाई के अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे के अनुसार संगठन ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया। हड़ताल को शुक्रवार तक जारी रखने का आह्वान किया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 11 अगस्त को साबरमती टी प्वाइंट के पास शुरू हुई थी। यह भूख हड़ताल छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों के प्रति के खिलाफ शुरू हुई थी।

आप ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी

- केजरीवाल आएंगे नारे को आम आदमी पार्टी ने किया लांच
- दिल्ली में जगह-जगह लगे केजरीवाल आएंगे के होर्डिंग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 2025 विधान सभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आप विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखकर लड़ेंगी।

इसके लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल आएंगे अभियान को लांच कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल आएंगे की कई होर्डिंग भी लगा दी गई है। इस कैंपेन के सहारे आम आदमी पार्टी दो संदेश देने में कामयाब हुई है। पहला दिल्ली

विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से सीएम को झूठे केस में जेल भेजने की साजिश भी सफल नहीं हुई।

इस साजिश को हराकर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएं हैं और अब केजरीवाल भी आएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं सांसद डॉ. संदीप पाठक के अनुसार अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली और देश की जनता में बहुत संवेदनशील है।

दिल्ली वाले आप संयोजक को जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जनता को भरोसा है कि उनके बाहर आने के बाद दिल्ली के के रुके सारे काम तेजी से पूरे होंगे और कई लंबित समस्याओं का भी त्वरित समाधान हो सकेगा। सबको भरोसा है कि जैसे मनीष सिसोदिया जनता के आशीर्वाद और संविधान की ताकत की बदौलत जेल की दीवारों को तोड़कर बाहर आए, वैसे ही बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। पाठक ने कहा कि लोग यह बात समझ रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार ने केवल दिल्ली का काम रोकने के लिए एक झूठे केस में सीएम को जेल में डाला हुआ है, ताकि जनता परेशान हो जाए।

एलजी के अधीन अधिकारी चाहकर भी जनता के काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।

भाजपा ने केजरीवाल की छवि खराब करने में भले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई है। लोग भाजपा की साजिशों को समझ गए हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा जवाब देंगे।

होर्डिंग अभियान छेड़ना न्यायालय की अवमानना है : सचदेवा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगाये गये केजरीवाल आयेंगे होर्डिंग देख कर स्थापित हो गया है कि यह पार्टी पूरी तरह आराजक है। जो व्यक्ति जेल में है और जिसे रिहा करना ना करना न्यायालय के विवेक पर है ऐसे में उस व्यक्ति को लेकर होर्डिंग प्रचार अभियान छेड़ना ना सिर्फ न्यायालय की अवमानना है बल्कि लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाना है। आप सरकार की विफलताओं से निराश लोग कह रहे हैं जायेगा।

अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1 के तहत 25 चुनौतियां लॉन्च की

25 चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1 को लॉन्च के मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव।

- कहा-योग, खान-पान, समृद्ध संस्कृति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने वाले क्रिएटर्स को सरकार का समर्थन है

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) से पहले 25 चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1 को लॉन्च किया।

नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार आयोजित होने जा रहा है वेव्स और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1 के लॉन्च कार्यक्रम में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के लिए काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसे देखते हुए हम इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। निकट भविष्य में वेव्स एक महत्वपूर्ण घटना बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें ये 25 चैलेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज, 25 चैलेंज लॉन्च की गई हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाती हैं। मीडिया और मनोरंजन उद्योग भी विकसित हुआ है, जिससे निर्माता अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला है।

क्रिएटर्स इकोनमी को प्रधानमंत्री ने पहचाना और उन्हें सम्मानित किया। क्रिएटर्स एक बड़ी इकॉनमी है। हमारा योग, खान-पान, समृद्ध संस्कृति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने वाले क्रिएटर्स को सरकार का समर्थन है। क्रिएटर्स के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। क्रिएटर्स और मीडिया इंटरटेंनमेंट के लोगों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। भारत में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फिल्म निर्माण में नई तकनीक और उपकरणों को विकसित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम को आगे ले जाया जाए तो इस क्षेत्र में 2-3 लाख से ज्यादा रोजगार अवसर मिल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस यात्रा में हमारे समाज को नुकसान न पहुंचे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज, उद्योग और हम सभी की है।

15 करोड़ के नशीले पदार्थ के साथ विदेशी धरा

- 3.5 किलोग्राम साइकोट्रेपिक पदार्थ मेस्कलाइन बरामद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

स्पेशल सेल और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त ऑपरेशन में अंतराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। टीम ने इस सिंडिकेट की एक विदेशी ड्रग ट्रैफिकर को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 3.8 किलोग्राम मेस्कलीन नामक ड्रग्स बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।

आरोपी मेस्कलीन की कुछ इस तरह से तस्करी करते थे कि उनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी पुलिस और एनसीबी की टीमें इन पर भारी पड़ीं।

पुलिस के मुताबिक, मेस्कलीन एक पार्टी ड्रग है जिसका उपयोग युवाओं में बढ़ रहा है। क्सर इस ड्रग्स का इस्तेमाल पार्टियों में किया जा रहा है। यह नशीला पदार्थ विदेश से तस्करी किया जा रहा था और दिल्ली में इसे बेचा जाना था। तस्करी करने वाले लोग इसे ब्रांडेड टॉफी और मछली के खाने के पैकेट में छिपाकर ला रहे थे ताकि पुलिस और अन्य एजेंसियों को चकमा दे सके। इस केस में गिरफ्तार की गई महिला का नाम फेथ रेचल है, जो नाइजीरिया की रहने वाली है। वह दिल्ली में रहती थी और ड्रग सिंडिकेट के लिए काम करती थी।

पुलिस ने बताया कि ये सिंडिकेट दिल्ली और आसपास के इलाकों में ड्रग्स की तस्करी करता था। उसने बताया कि ये ऑपरेशन कई महीनों की जांच और निगरानी के बाद किया गया है। पुलिस ने कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है और इससे ड्रग सिंडिकेट को काफी बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तार की गई विदेशी महिला से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वह कब से इस ड्रग सिंडिकेट के साथ जुड़ी थी। दिल्ली किसके लिए काम कर रही थी इसकी जानकारी मिलने में इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

मरीज के पति पर चिकित्सकों को पीटने का आरोप, गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में चिकित्सकों पर हमला करने और नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

कल-पुर्जों की दुकान चलाने वाला इसरार बुधवार रात अपनी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल ले गया था, जहां उसने चिकित्सकों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। आरोपी के चिकित्सकों को धमकाने और उनसे दुर्व्यवहार करते समय अस्पताल के कर्मचारियों ने घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने आरोपी की पत्नी को उसकी स्वास्थ्य संबंधित शिकायत के आधार पर दवा दी थी, लेकिन उसके पति ने दवा लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने तरीके से इलाज बताने लगा। अस्पताल के जूनियर रेजीडेंट डॉ. रजनीश ने बताया कि जब उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज किया तो वह हिंसक हो गया और चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। चिकित्सक ने कहा, हमने उसे शांत कराने की कोशिश की लेकिन उसने हमारे साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

दिव्य ज्योति जाग्रति में मनेगी जन्माष्टमी

नई दिल्ली। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान (डीजेजेएस) कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम 25 एवं 26 अगस्त डीडीए ग्राउंड, द्वारका सेक्टर 10 में शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम-दर्शन 'इतिहास का, परिवर्तन आज' का रखी गई है ताकि वर्तमान समय की सामाजिक समस्याओं के समाधानों को श्रीकृष्ण लीलाओं व भगवद्गीता के परिप्रेक्ष्य से समझा जा सके। कार्यक्रम में मीराबाई मुख्य प्रस्तुति होगी। डीजेजेस की प्रवक्ता साध्वी तपेश्वरी भारती ने कोलकाता डॉक्टर केस का उल्लेख करते हुए कहा- नारियों के प्रति ऐसे निंदनीय बर्ताव, धर्म के नाम पर वैमनस्य व पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए डीजेजेएस अपने सैंकड़ों वेद पाठियों द्वारा समाज में शांति एवं सौहार्द की भावना को स्पंदित करने हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ वेदमंत्र उच्चारण से करेगा।कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं 2024 ओलंपिक शूटिंग में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर भी उपस्थित रहेंगे। इनके साथ ही गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, अजय टम्टा , कमलेश पासवान, हर्ष मल्होत्रा, रवि किशन, बी.एल. संतोष, आलोक एवं अन्य जानी-मानी हस्तियां भी शिरकत करेंगी।

बहन की हत्या के आरोप में दो भाई गिरफ्तार

नई दिल्ली। दो भाइयों ने अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उसका किसी से प्रेम-प्रसंग है। पुलिस उपायुक्त एम. हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस ने मामले के सिलसिले में अब्दुल्ला और आरिब का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की है। उन्होंने यह भी बताया कि यौन उत्पीड़न के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को संदेह था कि तलाक के बाद उनकी बहन का किसी से प्रेम-प्रसंग है। उपायुक्त ने कहा, वे उसकी गतिविधियों पर संदेह कर रहे थे और खुद अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन की हत्या करने की साजिश रची। शुरुआती जांच के अनुसार उसकी गला दबाकर हत्या की गई है।

भलस्वा पर 30 लाख टन कचरे का होगा निस्तारण : शैली

- कहा-सदन की बैठक में लोगों को सुविधाएं देने वाले प्रस्ताव पारित किए गए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

महापौर शैली ओबरॉय ने कल सदन की बैठक में पारित हुए विभिन्न जनहितैषी प्रस्तावों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम की आप सरकार शहर में स्थित कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

सदन की बैठक में भलस्वा लैंडफिल साइट पर लेगेसी कचरे के निस्तारण के दूसरे चरण में 30 लाख टन कचरे के निस्तारण संबंधी मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर डबास गांव में एक और सैनिटरी लैंडफिल साइट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा जिसके अंतर्गत आईजीएल निगम के अधिकार क्षेत्र में कंप्रेसड बायो गैस संयंत्र स्थापित करेगा एवं इसके साथ ही एकीकृत सीबीजी-सीएनजी फ्यूल स्टेशन भी स्थापित करेगा। ओबरॉय ने कहा कि गाजीपुर स्थित बूचड़खाने पर इंजेस्ता, पौंच वेस्ट, गोबर सुखाने का संयंत्र स्थापित करेगा। इस संयंत्र को स्थापित करने से जानवरों के अपशिष्ट को लैंडफिल साइट पर जाने से रोकने में मदद मिलेगी। निगम के पार्कों के रखरखाव के लिए उद्यान विभाग द्वारा अतिरिक्त कर्मियों को लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

मेयर डॉ शैली ओबेरॉय ने पश्चिमी ज़ोन में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया।

बिल्डर ने एक ही फ्लैट चार लोगों को बेचा, अपना धन पाने के लिए भटक रहे पीड़ित

सेक्टर 15 में मैक्सवर्थ प्रीमियर अर्बन की 13वीं मंजिल पर खरीदा था फ्लैट

- दंपत्ति पर बैंक लोन चुकाने का दबाव, सारा पैसा बिल्डर ने हड़पा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

प्रतीकात्मक फोटो

गुरुग्राम में एक ही फ्लैट को चार बार बेचकर खुद को कंपनी के निदेशक कहने वाले दो लोगों ने करोड़ों रुपये की ठगी कर ली। करीब 7 साल पुराने इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी का शिकार हुए पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि इस केस में पुलिस विभाग से रिटायर देवेंद्र का भाई कृष्ण लोहचब भी उनका साथ देता आ रहा है।

गाजियाबाद स्थित महागुन मस्कट क्रोसिंग रिपब्लिक सोसायटी निवासी सौरभ पंडोह ने पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम को शिकायत देकर कहा कि उसने अपनी पत्नी नसीम सना ने गुरुग्राम के सेक्टर-15 में एक हाउसिंग सोसायटी मैसर्ज टिपटॉप एस्टेट प्रा. लि. सेक्टर-15 पार्ट-2 की ओर से विकसित की जा रही सोसायटी मैक्सवर्थ प्रीमियर अर्बन टावर-बी में 13वीं मंजिल पर वर्ष 2017 में 2 करोड़ 30 लाख रुपये में फ्लैट नंबर-1302 खरीदा था। बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत उन्होंने शुरू में करीब 55 लाख रुपये कंपनी को दिए थे। बाकी रकम 1 करोड़ 78 लाख 27 हजार 39 रुपये का एचडीएफसी बैंक से लोन कराया था। जिसकी एक मुश्त राशि 1 करोड़ 63 लाख 83 हजार 100 रुपये का भुगतान कर दिया था।

पीड़ित का कहना है कि कंपनी द्वारा उन्हें वर्ष 2021 तक फ्लैट देना था। वर्ष 2017 से वे बैंक लोन की किश्तें देते आ रहे थे। बाद में पता चला कि जो फ्लैट बिल्डर ने उन्हें बेचा था, वह फ्लैट पहले तीन अन्य लोगों को भी बेचकर ठगी की गई है। वे बिल्डर कार्यालय में पहुंचे और खुद को कंपनी के निदेशक बता रहे वहां मौजूद अमरजीत ढिल्लो व देवेंद्र सिंह लोहचब से मिले। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि जब कंपनी के निदेशकों से इस संबंध में बात की गई तो जवाब मिला कि उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने इस तरह से फ्लैट बेचा। वे 20 लाख रुपये काटकर बाकी के पैसे वापिस दे सकते हैं। पीड़ित दंपत्ति 20 लाख का नुकसान उठाकर बाकी के पैसे लेने पर राजी हुई। लोन के पैसे आरोपियों ने बैंक को वापस करने को कहा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया।

पीड़ित दंपत्ति ने शिकायत में कहा है कि वर्ष 2020 में एचडीएफसी बैंक की ओर से उन्हें एक डिमांड मिला, जिसमें उनसे 32 लाख 7 हजार 568 रुपये की मांग की गई। उन्होंने इस संबंध में बिल्डर अमरजीत व देवेंद्र से संपर्क किया। पीड़ित दंपत्ति ने यह भी कहा कि आरोपी उन्हें कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने दंपत्ति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की।

पीड़ित दंपत्ति के मुताबिक, आरोपियों ने यह एक ही फ्लैट उनके अलावा तीन अन्य लोगों विजय खरब, संदीप कोडान, विशाल धर नामक व्यक्ति को भी बेचकर उनसे रुपये हड़प रखे हैं। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज सतीश कुमार ने गुरुवार को बताया कि देवेंद्र सिंह लोहचब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक हथियार रखने पर प्रतिबंध : विक्रम सिंह

फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि यह आदेश विभिन्न बैंकों/निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डों के या विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डों तथा जिला फरीदाबाद में एटीएम में नकदी भरने और सुरक्षित परिवहन के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्डों जिनके पास हथियार रखने के लाइसेंस हैं और सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकृत कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। ऐसे सभी व्यक्ति अपने आग्नेयास्त्र और हथियार तुरंत अपने संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत शस्त्र डीलरों के पास उचित रसीद के साथ जमा कराएं।

संबंधित एस.एच.ओ./ शस्त्र डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे। संबंधित व्यक्ति अपना हथियार शस्त्र डीलर या संबंधित पुलिस स्टेशन से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत करके वापिस ले सकता है। वहीं इस प्रतिबंध से से पुलिस विभाग व बैंक सेवा के अधिकृत सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं किया जाएगा।

पंफलेट, हैंडबिल, पोस्टर पर प्रकाशक, प्रेस का नाम छापना अनिवार्य : निशांत यादव

- प्रेस संचालक आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें
- प्रकाशित सामग्री पर प्रतियों की संख्या लिखी होनी चाहिए

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव।

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रिंटिंग प्रेस संचालक निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही आचार संहिता की पालना करते हुए चुनाव प्रचार की सामग्री का प्रकाशन करें। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान बैनर, होर्डिंग, पंफलेट, हैंडबिल व पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम छापना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए की पालना करते हुए प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पंफलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब-किताब रहे। प्रेस संचालक एनेक्सचर फार्म वन और बी भरकर यह स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रेस से छपवाई गई है और इसको छपवाने वाला कौन है। साथ ही कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई हैं, इसका विवरण भी देना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पंफलेट व पोस्टर आदि को छापने से पहले सामग्री छपवाने वाले व्यक्ति का हलफनामा और साथ में दो गवाहों के हस्ताक्षर करवा ले। ऐसे पोस्टर व पंपलेट आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। उनको यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर, बैनर अथवा पंफलेट छपवाएं हैं और उनके खर्च का विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रेस संचालक इस बात की जांच कर लें कि प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु में कोई आपत्तिजनक शब्द ना हो। किसी भी उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टी, धर्म, जाति के प्रति अपमानजनक भाषा नहीं होनी चाहिए। डीसी ने कहा कि चुनाव प्रचार की सामग्री विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किए गए स्थानों पर ही लगाई जाएगी।

वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

- सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव को करवाने में सहयोग करें नागरिक

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को एक अक्तूबर, 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। चुनाव में मतदान करने का मौका पांच साल के बाद मिलता है। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कही।

उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त पहचान पत्र होना मतदान करने का अधिकार नहीं देता। मतदान के लिए व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे वोटर आईडी के अलावा अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 12 प्रकार के आईडी दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुंच उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी फोन पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम जिला के युवा लोकतांत्रिक व्यवस्था में को बुलंद रखने के लिए वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

'गुरूग्राम-फरीदाबाद व बल्लभगढ़-सोहना टोल शुरू करें'

फरीदाबाद। उपायुक्त विक्रम सिंह ने निर्देश दिए कि गुरूग्राम-फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़-सोहना सड़क मार्गों पर फास्टटैग की सुविधा शुरू करवाने का कार्य 31 अगस्त तक पूर्ण कर 1 सितम्बर, 2024 से इन सड़क मार्गों पर टोल प्रारंभ करें। साथ ही उन्होंने मार्गों पर गड्ढों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। कैंप कार्यालय में गुरूवार को विभिन्न विभागों की इंजीनियरिंग विंग के अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त विक्रम सिंह कर रहे थे। बैठक में विशेष रूप से गुरूग्राम-फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़-सोहना रोड पर फास्ट टैग सुविधा प्रारंभ करवाने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि फास्टटैग की सुविधा की शुरुआत के लिए ट्रायल का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार होगा बदलाव: सुखबीर तंवर

गुरुग्राम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पटौदी विधानसभा से भावी प्रत्याशी सुखबीर तंवर ने फर्रुखनगर खंड के गांव खुर्रमपुर, खेड़ा, डूमा, मुशेदपुर, सिवाड़ी, जराऊ सुंदरपुर, माजरी, बिरहेड़ा, गुगाना, राजूपुर, कारोला, फरीदपुर, महचाना, पालड़ी और अलीमुद्दीनपुर में प्रचार किया।

ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन टूट चुका है। विधानसभा चुनाव से मात्र 6 महीने पहले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री को सत्ताच्युत करके सरकार से बेदखल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हजारों स्कूल मर्जर के नाम पर बंद करना शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा है। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचागत विकास नहीं होना, जिला गुड़गांव के सिविल अस्पताल में विगत 10 वर्षों में एक भी ईंट नहीं लगाकर पार्किंग स्थल बना देना घटिया बानगी है। अभियान में खेमचंद सरपंच, राम निवास सरपंच, राजपाल सरपंच, बिशम्बर थानेदार, जगदेव यादव, प्रकाश, सुखबीर यादव, सुल्तान, दलीप, श्रीचंद, सुल्तान, अर्जुन, लाल सिंह, विनोद, राकेश, भोला राम, नरेंद्र यादव कारोला, अनिल फरीदपुर, रत्न सिंह, पंकज तंवर आदि मौजूद थे।

लंबे संघर्ष के बाद किसानों को मिला हक : नयनपाल

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

आईएमटी किसान संघर्ष समिति ने विधायक नयनपाल रावत का आभार व्यक्त किया।

लम्बे संघर्ष के बाद आईएमटी के किसानों को उनका हक मिल गया और एचएसएसआईडीसी द्वारा आवंटित प्लाट अब उन डिफाल्टर किसानों को भी मिलेंगे, जो किसी कारण से पैसा जमा नहीं करा पाए थे। एचएसआईआईडीसी ने बड़ी राहत देते हुए आईएमटी फरीदाबाद के पूर्व भूमि मालिकों, जो बढ़े हुई लागत के चलते भुगतान भुगतान नहीं कर पाए थे एक और मौका दिया है।

एचएसएसआईडीसी की 382वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे किसान 2012 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे जमा करा सकते हैं। इस फैसले के बाद लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिली और आईएमटी किसान संघर्ष समिति ने वीरवार को विधायक पृथला नयनपाल रावत के चंदावली स्थित कार्यालय पर पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नयनपाल रावत ने कहा कि किसानों के हक में इस फैसले का स्वागत करते हैं जिन किसानों को प्लाट आवंटित हुए हैं वो 31 अगस्त तक 8 फीसदी वार्षिक दर के साधारण ब्याज के साथ पैसा जमा कर सकते हैं। पूर्व में भूमि विस्थापित भी बकाया को 30 नवम्बर तक जमा करा सकते हैं।

पृथला विधानसभा क्षेत्र के किसी भी परिवार पर जब कोई आंच आती है, विधायक तुरंत राहत पहुंचाने का काम करते हैं। सामाजिक-धार्मिक कार्यों में सबसे आगे खड़े मिलते हैं और कभी किसी प्रकार के सहयोग से पीछे नहीं हटते। इस मौके पर रामनिवास नागर, रचना शर्मा, महावीर, विजय सिंह, लीलू, आशाराम, धर्मवीर, तेजपाल, नवीन, श्यामबीर, देवेन्द्र, जीतराम एवं रामसिंह आदि उपस्थित रहे।

सेक्टर-15 पावर हाउस 66 केवी से 220 केवी में होगा अपग्रेड

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता पूर्वक बिजली आपूर्ति करने के लिए और संसाधनों को ओर मजबूत करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों के साथ स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई।

बैठक में मंडलायुक्त हिसार एवं प्रबंध निदेशक डीएचबीवीएन पीसी मीणा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने में बेहतर सुधार जारी रखे जाएं। उन्होंने ओवरलोडेड पावर हाउस की क्षमता का आंकलन क्षमता में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है वहां पर संसाधनों में वृद्धि की जाए और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए। एचवीपीएन अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021 से 220 केवी सब-स्टेशन सेक्टर 15 पार्ट 2 निर्माणाधीन है जोकि 400 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-72 गुरुग्राम (पीजीसीआईएल) और 220 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-72 गुरुग्राम (एचवीपीएनएल) से कनेक्ट होगा।

संक्षिप्त समाचार

उमेश मलिक बनें गुरुग्राम भाजपा युवा मोर्चा प्रभारी

गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य उमेश मलिक को अब गुरुग्राम भाजपा युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी ने युवाओं को जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। इस नियुक्ति के लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उमेश का कहना है कि उनकी चुनावी ड्यूटी जहां पर लगाई जाती है, वे पार्टी उम्मीदवार के लिए पूरी मेहनत करते हुए उनकी जीत में भागीदारी होते हैं। उमेश मलिक ने कहा कि प्रदेश में 10 साल भाजपा की सरकार ने जनहित में बिना भेदभाव के जो काम किया है, यह बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में पहले जो भी सरकारें रही, उनमें विकास कार्य क्षेत्र देखकर किया जाता था। नौकरियों में भी भेदभाव होता था। भाजपा सरकार में एक गरीब किसान, श्रमिक का बेटा, बेटी भी अधिकारी लगने का सपना साकार कर पाया। मलिक ने कहा युवा कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता है कि भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाकर तीसरी बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनानी है।

महिला आईटीआई में दाखिले का आज अंतिम दिन

गुरुग्राम। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए जिन उम्मीदवारों द्वारा पहले ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा नहीं कराए गए हैं, ऐसे सभी इच्छुक उम्मीदवारों के आईटीआई में दाखिले के लिए ऑनलाइन दाखिला फार्म भरने के लिए दाखिला पोर्टल लिंक 23 अगस्त तक खुला रहेगा। जो उम्मीदवार दाखिले के लिए पूर्व में फार्म भर चुके हैं। उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई (महिला) गुरुग्राम के प्राचार्य जगमिन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य की सभी राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑन दा स्पॉट दाखिले के लिए इस दाखिला सत्र 2024-25 के लिए पहले ही दाखिला आवेदन फार्म भरे जा चुके हैं। संस्थान द्वारा उम्मीदवारों का संयुक्त रूप से विचार करते हुए 23 अगस्त तक मैरिट के आधार पर ऑन दा स्पॉट दाखिले किए जाएंगें। प्रार्थी को दाखिला पोर्टल से जारी अपना रैंक अथवा मैरिट कार्ड सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसमें वह दाखिला लेना चाहता है में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन भरे जाने वाले दाखिला आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलत जानकारी भरे जाने के कारण प्रार्थी दखिले से वंचित रह सकता है।

गुरुग्राम में 14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

गुरुग्राम। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी उपरोक्त अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है।

गला घोटकर हत्या करने का 20 हजार का इनामी गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने के 20 हजार रुपये के आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि कहासुनी में रंजिश रखते हुए हत्याकांड को अंजाम दिया था।

पुलिस के अनुसार 20 मई को थाना डीएलएफ फेज-1 गुरुग्राम से पुलिस चौकी चकरपुर की पुलिस टीम को एक सूचना थाना डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम क्षेत्र से लापता के परिजनों ने पहचान मिथिलेश सदाय (28) निवासी गांव सहसपुर जिला मधुबनी, बिहार के रूप में की। 28 मई को मृतक मिथिलेश सदाय की पोस्टमार्टम में मौत गला दबाकर होने पर हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20 हजार ईनाम भी घोषित किया। निरीक्षक संदीप कुमार इन्चार्ज अपराध शाखा फेस-4 इस केस में आरोपी की पहचान के लिए सूचनाएं एकत्रित की गई।

बीमा खरीदने का सही मौका, चूकें नहीं : नीता खट्टर

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एलआईसी समारोह में उपस्थित अभिकर्ता एवं एलआइसी अधिकारी।

भारतीय जीवन बीमा निगम के बल्लभगढ़ शाखा की वरिष्ठ शाखा प्रबंधक नीता खट्टर ने कहा कि देश की 140 करोड़ की आबादी में से 30 करोड़ लोगों का ही बीमा है, इसलिए इस क्षेत्र में व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। एस्कार्ट्स मुजेसर मेट्रो स्टेशन के समीप अभिकर्ता सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए नीता खट्टर ने कहा, अभिकर्ताओं को चाहिए कि वे वे घर घर बीमा पहुंचाकर सभी के जीवन को सुरक्षित और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएं।

सम्मान समारोह का आयोजन वरिष्ठ विकास अधिकारी नमीश खट्टर की ओर से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगीतमयी भजन के साथ हुआ। इस मौके पर सहायक शाखा प्रबंधक कपिल भारद्वाज व राम चंद्र प्रसाद के अलावा काफी संख्या में 12 जे शाखा के अभिकर्तागण मौजूद रहे।

शाखा प्रबंधक ने शाखा के वरिष्ठ अभिकर्ता एवं बेहतर कार्य के आधार पर अभिकर्ताओं समारोह में बेहतर कार्य करने वाले अभिकर्ताओं राम सकल, शिव शंकर, संजीव कुमार झा, शंकर, सत्यपाल सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आयोजक नमीश खट्टर ने सभी अभिकर्ताओं को गिफ्ट दिया।

लाभ से कराया अवगत

सहायक शाखा प्रबंधक कपिल भारद्वाज, राम चंद्र प्रसाद नेजीवन शान्ति, जीवन उत्सव, निवेश प्लस एवं इंडेक्स प्लस के लाभ से अभिकर्ताओं को अवगत कराया।

सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने वाले 288 लोगों का निगम ने काटा चालान

- सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालकर गंदगी फैलाने वालों के किए जा रहे चालान
- नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीमों ने अगस्त माह में अब तक काटे यह चालान

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

निगमायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़।

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालकर गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। ऐसा करने वालों पर कड़ी निगरानी रखते हुए मौके पर ही उनके चालान करके चालान राशि का भुगतान भी साथ-साथ ही करवाया जा रहा है। अगस्त माह में अब तक स्वच्छता टीमों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी के दौरान 288 उल्लंघनकर्ताओं के 166500 रुपये के चालान करके राशि का भुगतान करवाया गया है।

इनमें अधिकतर ऐसे मार्केट क्षेत्रों के दुकानदार या रेहड़ी-पटरी विक्रेता हैं जो अपना कचरा बाहर डाल देते हैं। स्वच्छता टीमें ऐसे व्यक्तियों पर लगातार निगरानी कर रही हैं। चालान करने के साथ ही उन्हें दोबारा से ऐसा नहीं करने के लिए आगाह भी किया जा रहा है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार नगर निगम की स्वच्छता टीमें क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं।

टीमों द्वारा विभिन्न सड़कों, गलियों, मार्केट क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं कि स्वच्छता टीमों द्वारा सफाई कार्य पूरा करने उपरान्त कुछ लोग अपने यहां से निकलने वाले कचरे को सड़क या गली में फिर से फैंक देते हैं। इससे एक ओर जहां सफाई व्यवस्था दुबारा से खराब होती है, वहीं दूसरी ओर यह कचरा हवा के साथ उड़कर पूरे क्षेत्र को गंदा कर देता है।

नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नागरिकों से बार-बार अपील की जा रही है कि वे कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही रखें तथा कचरा एकत्रित करने वाले कर्मचारी को सौंपें। इसके अलावा, आसपास निर्धारित स्थान या गार्बेज ट्रॉली में ही कचरा डालें। सड़क पर कचरा फेंकना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सभी का सहयोग अपेक्षित है।

नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमांइड का हांगकांग से प्रत्यर्पण

पंजाब पुलिस छह साल से भारत लाने का कर रही थी प्रयास

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

पंजाब पुलिस ने करीब आठ साल पहले हुए नाभा जेल ब्रेक केस में कार्रवाई करते हुए मास्टरमांइड रमनजीत सिंह रोमी को हांगकांग से प्रत्यर्पण करवाया है। पंजाब को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की विशेष टीमें रोमी को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचेंगी।

27 नवंबर 2016 को पटियाला की नाभा जेल से 6 कैदी फरार हुए थे। इनमें 2 आतंकी और 4 कुख्यात गैंगस्टर शामिल थे। जेल ब्रेक में फरार खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। रोमी जून 2016 में नाभा जेल गया और फिर जमानत पर बाहर आया। इसके बाद वह हांगकांग भाग गया। वहां से उसने नाभा जेल में बंद गुरप्रीत सिंह सेखों की मदद से जेल ब्रेक की इस वारदात को अंजाम दिया। रोमी ने पैसे भेजने के अलावा जेल से भागने वाले अपराधियों को सुरक्षित पनाह भी दी और हांगकांग में संपर्क करने के लिए नंबर भी दिया।

पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम रमनजीत सिंह रोमी को लाते हुए।

पंजाब पुलिस प्रत्यर्पण को बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि रोमी नाभा जेल से फरार हुए लोगों का सबसे बड़ा मददगार था। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि छह पुलिस अधिकारियों की टीम उसे लेने के लिए गई है। पंजाब में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। गौरव यादव ने बताया कि रोमी को आज लाया जा रहा है। वह आईएसआई, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हरमिंदर सिंह मिंटू और कश्मीर सिंह गलवाड़ी सहित अन्य फरार कैदियों के संपर्क में था।आरोपी का पहले लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। हांगकांग सरकार के साथ 2018 में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की गई।

जेजेपी के दो विधायकों के इस्तीफे को स्पीकर ने अभी तक नहीं किया मंजूर

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

जेजेपी के चार विधायकों के भाजपा में शामिल होने के कयास

जननायक जनता पार्टी के दो विधायकों ने बृहस्पतिवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग तथा नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा ने गुरुवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों विधायक लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और जेजेपी की तरफ से इन दोनों के विरुद्ध दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के याचिका दायर की हुई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ही जननायक जनता पार्टी लगातार बिखराव की तरफ बढ़ रही है।

चुनावों के ऐलान के बाद पूर्व मंत्री अनूप धानक ने सबसे पहले दुष्यंत चौटाला को झटका दिया। इसके बाद शाहाबाद के विधायक रामकरण काला तथा टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने जेजेपी को अलविदा बोल दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग तथा रामनिवास सुरजा खेड़ा खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए थे। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जेजेपी द्वारा इन विधायकों के खिलाफ स्पीकर की अदालत में दल बदल कानून के तहत बकायदा याचिका दायर की जा चुकी है।

हरियाणा पुलिस ने पंचकूला में बनाया चुनाव सेल, मतदान तक 24 घंटे रहेगा सक्रिय

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

हरियाणा पुलिस ने चुनावों के मद्देनजर पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में चुनाव सेल स्थापित किया है। इस सेल के माध्यम से प्रदेश स्तर पर चुनाव का प्रबंधन किया जाएगा ताकि लोग भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव सेल द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के साथ साथ चुनाव संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। इस सेल के ओवरऑल इंचार्ज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार को लगाया गया है जबकि सुपरविजन के लिए स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर के रूप में पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा सौरभ सिंह को तैनात किया गया है। चुनावी खर्च की निगरानी तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट के लिए नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था हरदीप दून को लगाया गया है। इसके अलावा, प्रदेश के सभी जिलों में डीएसपी तथा एसपी स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो पुलिस मुख्यालय में स्थापित किए गए चुनाव सेल में निर्धारित बिंदुओं बारे में रोजाना अपने जिलो की रिपोर्ट भेजेंगे। कपूर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में बनाए गए चुनाव सेल के माध्यम से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। इलेक्शन सेल द्वारा पुलिस बल की उपलब्धता तथा उसकी तैनाती तथा इससे संबंधित मुद्दो को लेकर जिलों से तालमेल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रदेश में अलग-2 विधानसभा क्षेत्रों में क्रिटिकल (जटिल) बूथों की पहचान करते हुए वहां पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती का निर्णय भी लिया जाएगा। जिलों द्वारा रोजाना सीजर रिपोर्ट, चुनाव संबंधी शिकायतें, आदर्श आचार संहिता की पालना संबंधी रिपोर्ट भी चुनाव सेल को भेजी जाएगी। इलेक्शन सेल 24 घंटे संचालित रहेगा।

सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद रिलीज होगा आठवां गीत

चंडीगढ़। पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद उनका आठवां गीत 30 अगस्त को रीलीज होने जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की टीम की तरफ से उनके सोशल मीडिया अकांउट पर गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस गाने का पोस्टर पोस्ट किया गया है। जिससे साफ है कि इस गाने का नाम अटैच है। इस गाने को स्टील बैंगलेज और फरैडो के सहयोग से पूरा किया गया है। सिद्धू मूसेवाला का यह इस साल का तीसरा गाना है जो रिलीज होने जा रहा है। ये गीत सिद्धू मूसेवाला के यू-ट्यूब चैनल पर रिलीज होगा या स्टील बैंगलेज के चैनल पर, इसकी जानकारी अभी सिद्धू मूसेवाला टीम की तरफ से साझा नहीं की गई है।

मतदाता 2 तक सूची में दर्ज करवा सकते है नाम

कुरुक्षेत्र। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने सभी पात्र नागरिकों एवं मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चैक कर लें। ऐसा ना हो कि मतदाता का के पास वोटर कार्ड तो है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इस स्थिति में मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा। इसलिए सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चेक जरूर करें ताकि वो वोट डालने से वंचित ना रहे।

वीएलडीए की शैक्षणिक योग्यता बदलने पर जताई नाराजगी

चंडीगढ़। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद वीएलडीए कोर्स की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करने पर डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। पशुपालन विभाग द्वारा वीएलडीए के कार्स में शैक्षणिक बदलाव करते हुए मेडिकल स्ट्रीम से आर्ट स्ट्रीम किया है। विभाग के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी।

डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन से उपप्रधान अरविंद भालोटिया, महासचिव राजेश लोहान, मंजीत फोगाट व सचिन यादव ने बताया की यह बदलाव अधिकारियों ने वीएलडीए का कोर्स करवाने वाले प्राइवेट कालेजों के दबाव में लिया है। डिप्लोमा वेटरनरी 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, जिसमें एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि वीएलडीए का पद तकनीकी पद है व उनका मुख्य कार्य पशु चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। इसलिए वीएलडीए कोर्स की शैक्षणिक योग्यता केवल मेडिकल स्ट्रीम से होनी चाहिए। सरकार ने एसोसिएशन की मांग जायज मानते हुए कोर्स की शैक्षणिक योग्यता मेडिकल स्ट्रीम कर दी थी। एसोसिएशन ने बताया कि यह बदलाव आचार संहिता के दौरान किया गया है, वह शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ है।

भाजपा छोड़ 8 पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए

कुरुक्षेत्र। विधायक एवं राज्यमंत्री सुभाष सुधा को बृहस्पतिवार को झटका लगा जब भाजपा के 8 पूर्व पार्षदों ने पार्टी को अलविदा कहकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व पार्षद राधेश्याम वधवा के निवास पर कांग्रेस में शामिल होने वाले इन पूर्व पार्षदों में राधेश्याम वधवा के अलावा गुरदयाल काजल, पवन वधवा, सुभाष वधवा, नीरू वधवा, कमलेश वधवा, किरण काजल और राधा रानी पोपली शामिल हैं। पूर्व पार्षदों ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

कुवि के 17 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने शोध समिति और परीक्षकों के बोर्ड की अनुशंसा पर 17 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि के लिए पात्र घोषित किया है। लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि पात्र घोषित शोधार्थियों में अंग्रेजी से कृष्ण लाल, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से नवीन मैहला, एजुकेशन से अनादि, ललित कला से विदिशा व राहुल, संस्कृत से निशा, लॉ से नरेन्द्र सिंह, आयना, कीर्ति यादव व प्रिया चौधरी, माईक्रो बॉयोलॉजी से महक मित्तल, केमिस्ट्री से पिंकी, कम्प्यूटर साइंस से आशा सोहल, अप्लाईड जियोलॉजी से तराशा चितकारा, अप्लाईड जियोफिजिक्स से मयंक दीक्षित, फिजिक्स से विकास व सांख्यिकी से श्रवण कुमार शामिल हैं।

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Gurpreet Singh Chawla S/o Late Sh. Gurbaksh Chawla R/o 9, Gali no -21, A-2 Block, Sant Nagar West, Burari, Delhi Change my name To Gurpreet Singh for all future purposes.
PD(699)A

I, Tina Gambhir D/o Sh. Surinder Gambhir and Smt. Shashi Gambhir R/o T-346/A, First Floor, Baljeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi-110008, have changed my name from Teena to Tina Gambhir. And declare that Tina Gambhir and Teena both is the same and one person.
PD(700)C

I, Munni Devi W/o Sanjay R/o 327 Nithari Sector-31 Noida., Distt. Gautam Budh Nagar U.P., declare that my name mentioned in Aadhar Card written as Saroj and Voter Id card my name mentioned as Munni Devi. But Saroj and Munni Devi both are the same and one person.
PD(701)C

Public Notice

This is to inform the general public that **Mrs. Sheela Devi Jain** is the GPA holder of Entire Ground Floor without Roof Rights, property bearing no. C- 285- E, area measuring 83.61 Sq. Mtrs., out of Khasra no. 417, situated at Village Ghonda Gurjan, Gali no. 10, Block C, Bhajanpura Illaqa Shahdara Delhi 110053. She is in Possession of Said floor through GPA, ATS dated 05.09.2011 executed by Mrs. Meenakshi Jain in favour of Mrs. Sheela Devi Jain.
Mrs. Sheela Devi Jain intends to transfer the ownership by way of Sale Deed of aforementioned floor to **Mr. Raj Kumar Sharma.** Subsequently, **Mr. Raj Kumar Sharma** is in the process of mortgaging the said is in the process of mortgaging **Aditya Birla Housing Finance Limited.** Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 7 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 7-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.
If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 7-day period by contacting **Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in**

सार्वजनिक सूचना

यह आम जनता को सूचित करने के लिए है कि श्री सुखपाल पुत्र टेक चंद प्लॉट नं. 3 आउट ऑफ खसरा नं. 504 क्षेत्र जिसका माप 100 वर्ग मीटर है। yds. गांव सिकदरपुर के क्षेत्र में, मुख्य सड़क की आबादी में, नाथू कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110093 वह जीपीए, एटीएस दिनांक 16.03.1976 के माध्यम से श्री जय भगवान और श्री टेक चंद द्वारा श्री सुखपाल के पक्ष में प्लॉट नं। 3 क्षेत्र 200 वर्ग मीटर। yds. खसरा नं. 504. सुखपाल एस/ओ टेक चंद 100 वर्ग मीटर के उपर्युक्त संपत्ति क्षेत्र के बिक्री विलेख के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का इरादा रखते हैं। वाईडीएस। श्रीमती को। सुधा मित्तल और कुमारी रूमा। इसके बाद, श्रीमती. सुधा मित्तल और कुमारी रूमा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड को गिरवी रखने की प्रक्रिया में हैं। इस लेन-देन के संबंध में कोई भी आपत्ति या चिंता इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर उठाई जानी चाहिए। इस 7-दिवसीय अवधि के पूरा होने के बाद प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति को उक्त संपत्ति या हमारे ग्राहक के हितों के संबंध में बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। यदि कोई आपत्ति उठाना चाहता है, तो कृपया निर्धारित 7-दिवसीय अवधि के भीतर कार्यालय संख्या में लॉ वेरिटासः नॉर्थ (एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स) से संपर्क करें। 11, पहली मंजिल, इमारत नं। ए-44/ए, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; लैंडलाइन + 910120-3101683; ई-मेलः account@lvnorth.in

KSOLVES
Emerging Ahead Always

केसोल्व्स इंडिया लिमिटेड
सीआईएनः L72900DL2014PLC269020
पंजीकृत कार्यालयः 317/276, दूसरी मंजिल, लेन नं. 3, महरौली रोड, सैदुलजाब, साकेत, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110030, भारत
कार्प. कार्यालयः स्मार्टवर्क्स, टॉवर डी, सी–28 और 29, सी ब्लॉक, फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
टेलीफोन नं. 0120–4983851, ई–मेलः cs@ksolves.com, वेबसाईटः www.ksolves.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित 10वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि केसोल्व्स इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 10वीं बैठक शनिवार, 14 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होगी, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम), 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई, 2020, 20 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर 2020, 31, जनवरी 2020, 08 दिसंबर, 2021 और दिसंबर 14, 2021, 02/2022, दिनांक 05 मई, 2022 और 19/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित जिसे सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक मई–12–2020, जनवरी–15–2021, मई–13–2022 और जनवरी–05–2023 (सेबी परिपत्र) या एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए इस संबंध में कोई अन्य लागू परिपत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरण के साथ–साथ बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज (सामूहिक रूप से ''वार्षिक रिपोर्ट'' के रूप में संदर्भित) कंपनी के उन सभी सदस्यों को केवल ई–मेल द्वारा भेजे जाएंगे, जिनका ई–मेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के पास पंजीकृत है। अन्य दस्तावेजों के साथ नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 23 अगस्त, 2024 को पूरा हो जाएगा और यह कंपनी की वेबसाइट www.ksolves.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की वेबसाइट www.nseindia.com और BSE लिमिटेड (BSE) की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 44 और आम बैठक (एसएस–2) पर सचिवीय मानकों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी सभी सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') प्रदान करने में प्रसन्न है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उन सभी सदस्यों को एजीएम (ई–वोटिंग) के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं डाले हैं। एजीएम की सूचना में संबंधित प्रक्रिया/निर्देश दिए गए हैं।

कट–ऑफ तारीख 7 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और एजीएम में वोट डालने के पात्र होंगे। वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तारीख को उनके चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 11 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे होगी और 13 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ/रिकॉर्ड तारीख अर्थात 7 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह cs@ksolves.com या investor@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स तथा वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए दिए गए निर्देशों, वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग ध वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट्स में दी गई है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने ''ज्वाइन मीटिंग'' मेनू के अंतर्गत ''वीसी/ओएवीएम लिंक'' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन मीटिंग मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।
3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरा की अनुमति देनी होगी तथा अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
6. एजीएम से पहले/उसके दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022–48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
7. जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई–मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर cs@ksolves.com पर 07 सितंबर, 2024 (शाम 5.00 बजे IST) तक अनुरोध भेजकर स्वयं को पहले से पंजीकृत कर सकते हैं। केवल वे सदस्य जिन्होंने खुद को वक्ता के रूप में पहले से पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
8. वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।

बोर्ड के आदेश द्वारा
केसॉल्व्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
मनीषा किडे
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
दिनांकः 23.08.2024
स्थानः नोएडा

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला सीता देवी पत्नी स्व0 सुंदर लाल निवासी- ई-59/ए-150, कलंदर कालोनी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95 ने अपने पुत्र वरूण को उसके दुर्व्यवहार व अनैतिक कृत्यो के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखलकर अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है, भविष्य में उसके किसी भी कृत्य हेतु मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होंगी।

MANOHAR CHANDRA (Advocate), Ch. No. F-427, 1 Floor, Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032, Mob.:9818109492.

PUBLIC NOTICE

My clients (1) Smt. Mithlesh W/o Shri. Satyendra Kumar Singh, (2) Satyendra Kumar Singh S/o Late. Raksh Pal Singh Both are R/o J-41/4, Street No.7, Kartar Nagar, Delhi-53, have severed all their relations from their Son respectively and they will not be responsible for any acts, deeds and transaction made by Sumit Kumar in future due to his misconduct, misbehaviour & etc. and Shri Sumit Kumar will not be entitled of any movable or immovable property, which are in the name of my clients.

Rajesh Gautam (Advocate)
Ch. No. 654-A, WESTERN WING.

PUBLIC NOTICE

It is to informed to the public at large that one M/s Shubhampress Automation Pvt. Ltd.(PAN AATCS2098E) who is owner of Leasehold Industrial Plot No. 73 measuring 210.37 sq. mtrs. situated in Block-E, Sector-7, Noida, Phase-I, U.P., hereinafter referred to as "said property" having acquired the same by virtue of Transfer Deed dated 22.08.2024 executed by Zaheer Ahmed which is duly registered at the office of Sub Registrar Noida-III. Some Property papers of said Property i.e. Transfer Deed dated 06.12.1996 executed by KeshavLal (Prop. of Hari Plastics) in favour of Hari Fibreglass Pvt. Ltd. in respect of the said property (Doc. No. 4151/4152), has been lost by the previous owner and are not traceable. If anybody found the same, Plz return at the address mentioned below. The said Property has been mortgaged by the owner with HDFC Bank Limited (our client). Further, It is hereby declared that title of the said Property, is absolutely valid, clear and marketable and there is no dispute / Litigation pending in any court of law, in respect of said Property. Whosoever, is having any objection to said mortgage OR any Person having any type of claim/ right/title/interest over the said property may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien etc.

S.C. VARSHNEY (Sr. Advocate)
R-14/178, Raj Nagar, Ghaziabad-201002,
Mobile: 8882600727

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **निशेष रंजन और वंदना श्रीवास्तव** को **08.12.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOI00461428** की राशि **रू.29,02,671.21 (रूपये उनतीस लाख दो हजार छह सौ इकहत्तर और इक्कीस पैसे मात्र)** और **16.11.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **21.08.2024**. को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.29,02,671.21 (रूपये उनतीस लाख दो हजार छह सौ इकहत्तर और इक्कीस पैसे मात्र) 16.11.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

टावर ए 1 में, आठवीं मंजिल पर, फ्लैट नं. 0802 के सभी भाग और खंड, मापित कारपेट क्षेत्र 83.26 स्क्वे. मीटर्स, विशिष्ट क्षेत्र 18.70 स्क्वे. मीटर्स, कुल क्षेत्र 101.96 स्क्वे.मीटर्स, "गोदरेज नेस्ट" नामक कॉम्प्लेक्स में, एससी-02/एच और एससी-02/1 पर स्थित, फेज 1 में, सेक्टर 150, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
दिनांक : 21.08.2024
स्थान : नोएडा

दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058,
फोन नं. 011-25611042, 25611043, 25611044
ईमेलः legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com,
वेबसाईटः www.kangrabank.com

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल संपति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत "दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि.", मुख्य कार्यालय, सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनक पुरी, नई दिल्ली - 110058, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली - 110055 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम(3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **उधारकर्ता और बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी श्री गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जग मोहन सिंह निवासी मकान नं. बी-17, खानपुर एक्सटेंशन, देवली रोड, नई दिल्ली-110062 और बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी सुश्री नवनीत कौर पुत्री श्री गुरमीत सिंह निवासी मकान नं. बी-17, खानपुर एक्सटेंशन, देवली रोड, नई दिल्ली-110062 और बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी श्री अर्शदीप सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह निवासी मकान नं. बी-17, खानपुर एक्सटेंशन, देवली रोड, नई दिल्ली-110062 को एक मांग सूचना दिनांक 10.04.2024 को जारी किया गया था जिसमें** सूचना में उल्लिखित राशि रु. **24,50,284/- (रुपये चौबीस लाख पचास हजार दो सौ चौरासी मात्र)** तथा साथ में भविष्य का ब्याज, पीनल ब्याज एवं अन्य प्रभार सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर इस ऋण खाते में प्रयोज्य अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया है।

उपर्युक्त उधारकर्ता, बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी और जमानतदार राशि का पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा उधारकर्ता, बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी और जमानतदार एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि बैंक ने सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर **17 अगस्त, 2024** को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता, बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी और जमानतदार तथा विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा बंधक सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार "दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि.", के प्रभार वास्ते रु. **24,50,284/- और ऋण खाते पर समय-समय पर लागू होने वाले अतिरिक्त ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों, नोटिस की तिथि से वसूली की तिथि तक तथा उक्त राशि की वसूली में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता, बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी और जमानतदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा-13 की उप-धारा-(8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

विचाराधीन संपत्ति क्षेत्रफल 50 वर्ग गज सम्पूर्ण निर्मित संपत्ति है।	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित सम्पत्ति नं. बी17, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (सम्पत्ति नं. बी-16/17 का भाग) खसरा नं. 565 में शामिल, बी-ब्लॉक, खानपुर एक्सटेंशन, गांव खानपुर, तहसील-हौज खास, नई दिल्ली में स्थित, सब-रजिस्ट्रार VA हौज खास, दिल्ली के पंजीकरण के अंतर्गत

(हरीश शर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी
दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
मुख्यालयः सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-58
9013568419, 9013568418
दिनांकः 17.08.2024
स्थान : दिल्ली

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर–23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह–कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	आशीष ढिंगिया/ ओंकार सिंह ढिंगिया/ LBDEL00001101022/ LBDEL00001308180	डीडीए एमआईजी फ्लैट, फ्लैट नंबर 302, द्वितीय तल, जहाँगीरपुरी, दिल्ली– 110033/ अगस्त 21, 2024	नवंबर 29, 2023 रु. 2,59,323/–	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : अगस्त 23, 2024
स्थान : दिल्ली/एनसीआर
भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

SUNLOC
सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 38ई/252–ए, विजय टॉवर, शाहपुरजट, नई दिल्ली–110049
CIN - L24302DL1973PLC189662
ईमेलः info@sunilhealthcare.com/ वेबसाइटः www.sunilhealthcare.com
टेलीफोनः +91–11–49435555/00, फैक्सः 91–11–43850087

नोटिस
(कृपया ध्यान दें: सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारक)

आगामी 50वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस और अन्य पत्राचार भेजने के लिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी, हम सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल पता या बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध पत्र, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को "4E/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055", संपर्क–91–11–42541234 ईमेल आईडीः lalitap@alankit.com, rta@alankit.com, या कंपनी के कंपनी सचिव को cs@sunilhealthcare.com पर अनुरोध करें, फोलियो नंबर और पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति द्वारा।

सामान्य परिपत्र संख्या–14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, अर्थात परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या–10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सबसे नवीनतम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र सं. – SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, दिनांक 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी, कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट और 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना (दूरस्थ ई–वोटिंग/ई–वोटिंग निर्देशों सहित) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया सक्षम की है और सदस्य हमारे ई–वोटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एजेंसी, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी को cs@sunilhealthcare.com पर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ एक ईमेल भेजकर अस्थायी रूप से अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं।

सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड हेतु
हस्ता/–
सत्येंदु पटनायक
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम.नं. एफ7736
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.08.2024

Piramal Capital & Housing Finance
पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय पताः यूनिट नं. 601, 6वीं मंजिल पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070
सीआईएनः L65910MH1984PLC032639, वेबसाइट : www.piramalfinance.com
शाखा का पताः धीरज बाग, बिल्डिंग "ए" भूतल और प्रथम तल, एक्सिस बैंक के साथ में, मोनालिसा बिल्डिंग के समाने, आगरा रोड, हरि निवास सर्कल, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)–400602

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी कर आह्वान किया है निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता") को जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर पीसीएफएल को भुगतान करने का नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई तारीखों से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय, उक्त मांग नोटिस में बताए गए अतिरिक्त ब्याज के साथ, नीचे दर्शाई गई राशियाँ, यदि कोई हो, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता द्वारा पीसीएफएल को गिरवी रखा गया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि साथ में एन पी ए की तिथि	सम्पत्ति का पता
(दिल्ली - द्वारका शाखा का एलसी नं. HLSA00004929) स्वाति लांबा (उधारकर्ता) अमृत पाल सिंह (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.8,44,859/-(रु. आठ लाख चौवालीस हजार आठ सौ उनसठ मात्र) एनपीए (04-07-2024)	ई-4, दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, खं. सं. 850 मिन नीलकंठ अपार्टमेंट्स मेन रोड संत नगर गाँव-बुड़ाडी, नई दिल्ली 110084
(गुरुग्राम - एमजी रोड शाखा का एलसी नं. M0090876) स्वाति लांबा (उधारकर्ता) अमृत पाल सिंह (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.16,04,392/-(रु. सोलह लाख चार हजार तीन सौ बान्वे मात्र) एनपीए (04-07-2024)	ई-4, दूसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के, खं. सं. 850 मिन, नीलकंठ अपार्टमेंट्स मेन रोड संत नगर गाँव-बुड़ाडी, नई दिल्ली 110084
(रोहिणी शाखा का एलसी नं. 09200000882) मोहम्मद जकी (उधारकर्ता) मोहम्मद नक्की खान (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु. 4,12,183/- (रु. चार लाख बारह हजार एक सौ तिरासी मात्र) एनपीए (10-07-2024	फ्लैट नं. डी-302, तीसरी मंजिल, टॉवर-डी जेनेसिस फ्लोरा, अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी, भिवाड़ी अलवर राजस्थान - 301019
(गुड़गांव शाखा का एलसी नं. 13000000483) गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) सुभाष गुप्ता (सह-उधारकर्ता 1) परमोद गर्ग (सह-उधारकर्ता 2 प्रेम लता गुप्ता (गारंटर 1)	25-07-2024/रु. 3,97,44,633/-(रु. तीन करोड़ सत्तानवे लाख चौवालीस हजार छह सौ तैंतीस मात्र) एनपीए (09-02-2023)	मकान नं. 361 बेहरा एन्क्लेव गोल चक्कर पश्चिम विहार के पास नई दिल्ली दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली - 110001
(गुड़गांव - सोहना रोड शाखा का एलसी नं. 19700042226) आरती भाटिया (उधारकर्ता) नीलम भाटिया (सह-उधारकर्ता उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.1,17,432/-(रु. एक लाख सत्रह हजार चार सौ बत्तीस मात्र) एनपीए (10-07-2024)	फ्लैट नं. 1206 12वीं मंजिल ब्लॉक डी टावर पी आर 4 प्राइम रोज/प्रीमियम कृष सिटी फेज 2 अलवर बाईपास भिवाड़ी अलवर राजस्थान - 301019
(बहादुरगढ़ शाखा का एलसी नं. 18900000195) जगदीप भोला (उधारकर्ता) प्रीति भोला (सह उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.39,03,697/-(रु. उनतालीस लाख तीन हजार छह सौ सत्तान्वे मात्र) एनपीए (10-07-2024)	प्लॉट नं. 29, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित और पॉकेट और ब्लॉक ई-4, सेक्टर-11, रोहिणी नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली - 110085
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. 19800042084) राजेश कुमार झा (उधारकर्ता) पूनम झा (सह उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.21,40,918.72 (रु. इक्कीस लाख चालीस हजार नौ सौ अठारह तथा पैसे बहत्तर मात्र) एनपीए (10-07-2024)	प्लॉट नं. 23 यूजीएफ फ्रंट आरएचएस खं. नं. 78/1/3, ओम विहार, फेज-3 उत्तम नगर नई दिल्ली दिल्ली - 110059
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. HLSA0000861A) सुंदर (उधारकर्ता) सविता देवी (सह उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु. 73,66,651/- (रु. तिहत्तर लाख छियासठ हजार छह सौ इक्यावन मात्र) एनपीए (04-07-2024)	संपत्ति संख्या 145, पॉकेट-9, सेक्टर-21, पूर्ण दूसरी और तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, रोहिणी दिल्ली 110086
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. HLSA0000861ATU) सुंदर (उधारकर्ता) सविता देवी (सह उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.23,17,217/-(रु. तेईस लाख सत्रह हजार दो सौ सत्रह मात्र) एनपीए (04-07-2024)	संपत्ति संख्या 145, पॉकेट-9, सेक्टर-21, पूर्ण दूसरी और तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, रोहिणी दिल्ली 110086
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. HLSA000099B7) सुंदर (उधारकर्ता) सविता देवी (सह उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु.63,53,382/-(रु. तिरेसठ लाख तिरेपन हजार तीन सौ ब्यासी मात्र) एनपीए (04-07-2024)	संपत्ति संख्या 145, पॉकेट-9, सेक्टर-21, पूर्ण दूसरी और तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, रोहिणी दिल्ली 110086
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. HLSA000099B7TU) सुंदर (उधारकर्ता) सविता देवी (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/रु. 28,23,537/- (रु. अट्ठाईस लाख तेईस हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) एनपीए (04-07-2024)	संपत्ति संख्या 145, पॉकेट-9, सेक्टर-21, पूर्ण दूसरी और तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, रोहिणी दिल्ली 110086
(एलसी सं. 26600001606 दिल्ली राजौरी गार्डन शाखा) कपिश इन्फोलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों मनोज अग्रवाल और मोहम्मद नईम के माध्यम से) (उधारकर्ता) और मनोज अग्रवाल और योगिता अग्रवाल (सह-उधारकर्ता)	01-08-2024/रु.4,20,71,434/- (चार करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ चौंतीस मात्र) एनपीए (10-07-2024)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित संपत्ति सं. आर जेड-एफ-659/6, गली सं. 24, भूमि क्षेत्रफल 508 वर्ग गज, खसरा सं. 608 में से, सभी भूमि और छत अधिकारों के साथ, गांव नसीरपुर के रेवेन्यू इस्टेट में, कॉलोनी जिसे साध नगर-।। कहते है, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 में स्थित, नीचे की भूमि के सभी फ्री होल्ड अधिकारों के साथ और चौहद्दीः पूरब में - अन्य की भूमि पश्चिम में - गली 15 फीट चौड़ी, उत्तर में - अन्य की भूमि दक्षिण में - गली 16 फीट चौड़ी

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार पीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो पीसीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगा। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को पीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
दिनांकः 23.08.2024, स्थानः दिल्ली

लेटरल इंट्री

वापसी की घोषणा

सरकार ने नौकरशाही में 'लेटरल इंट्री' की वापसी की घोषणा कर दी। सरकार ने सिविल सेवाओं में लेटरल इंट्री की पहल वापस लेने का निर्णय किया है। यह निर्णय उसके कुछ राजनीतिक सहयोगियों की आपत्तियों के कारण हुआ। विपक्षी दलों ने इसे एससी, एसटी व ओबीसी के अधिकारों का हनन कहा था। हालांकि, इस वापसी से सरकार की नौकरशाही में निजी क्षेत्र से नई प्रतिभा को प्रवेश दिलाने की इच्छा को थोड़ा धक्का लग सकता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में विशेष कौशल तथा दृष्टिकोण शामिल करना था। एक अवधारणा के रूप में 'लेटरल इंट्री' की शुरुआत सिविल सेवाओं में आवश्यक समकालीन प्रशासन तथा परंपरागत विशेषज्ञता के बीच खाई पाटने के लिए की गई थी। वित्त, तकनीक तथा सामाजिक विज्ञानों जैसे अनेक क्षेत्रों से पेशेवरों को वरिष्ठ स्तरों पर नौकरशाही में प्रवेश की अनुमति दे कर सरकार सार्वजनिक प्रशासन की प्रभावशीलता और क्षमता बढ़ाना चाहती थी। इस पहल को ऐसी व्यवस्था में नए विचारों और खोजों को प्रवेश कराने की इच्छा के रूप में देखा जा रहा था जिसकी आलोचना अक्सर सुस्त, जड़ तथा समकालीन यथार्थ से कटे रहने के कारण होती है। लेकिन इसे विपक्ष तथा कुछ भाजपा सहयोगियों द्वारा पसंद नहीं किया गया।

आलोचकों का तर्क है कि लेटरल इंट्री से भारतीय सिविल सेवाओं के मूल सिद्धान्तों को नुकसान पहुंच सकता है जिसमें ऐतिहासिक रूप से तटस्थता, निरंतरता तथा देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझना शामिल है। हालांकि, लेटरल इंट्री के माध्यम से भर्तियां कांग्रेस सरकारों में भी होती रही हैं और उनमें आरक्षण का भी

कोई प्राविधान नहीं था, पर संभवत: इस बार इनकी संख्या अधिक थी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने 2005 में लेटरल इंट्री की सिफारिश की थी। इस संस्तुति के पहले भी प्रोफेसर व अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त सचिव बनाया गया था तथा बाद में 'आधार' अवधारणा के जनक नंदन नीलकेणी को नौकरशाही में स्थान मिला था। इसके साथ ही कांग्रेस सरकारों में लेटरल इंट्री के माध्यम से अनेक भर्तियां की गई थीं। कांग्रेस शासनकाल में लेटरल इंट्री का कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि अब राहुल गांधी व विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' इसका विरोध कर रहा था। यह राजनीतिक व चुनावी लाभ के लिए सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के प्रयास के सिवा और कुछ नहीं है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया है कि कांग्रेस शासनकाल में लेटरल इंट्री से भर्तियां मनमाने व अपारदर्शी ढंग से होती थीं, जबकि इस बार सरकार ने इसके लिए खुला विज्ञापन जारी किया था। भाजपा नेताओं ने यह भी याद दिलाया है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति नौकरशाही के निर्णय निर्देशित करती थी, लेकिन इस पर कभी सवाल नहीं उठे। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार ने आरक्षित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना भी शामिल है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 'लेटरल इंट्री' पर निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर वापस लिया गया है जो इसमें एससी, एसटी व ओबीसी को समुचित आरक्षण देना चाहते हैं। इस प्रकार भाजपा ने सही समय पर सही कदम उठा कर विपक्ष के हाथों से एक हथियार छीन लिया है जिसके बहाने वह देश की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने का सपना देख रही थी।

कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी तथा जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर में चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी तथा जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक प्रकार से यह चुनाव जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में विधानसभा चुनाव 90 विधायक चुनने के लिए होंगे। ये चुनाव अगस्त, 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा उसे दो संघशासित क्षेत्रों में बांटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव कराने में विलंब को लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाल में सर्वोच्च न्यायालय का दिशानिर्देश महत्वपूर्ण रहा जिसके चलते अब राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश ने चुनाव का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का बिंदु रहा है। भारत और पाकिस्तान, दोनों पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते रहे हैं, हालांकि दोनों देशों का इसके एक-एक हिस्से पर शासन रहा है। पाकिस्तान ने लंबे समय से कश्मीर मुद्दे के 'अंतरराष्ट्रीयकरण' का प्रयास किया है। कश्मीर मुद्दा लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी उठाया जाता रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा बार-बार उठाया है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य को दो भागों में बांटने पर भी विवाद रहा है। राज्य को विभाजित करने के निर्णय से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा, अपराध संहिता तथा संवैधानिक प्रक्रियायें समाप्त हो गईं। इसके कारण कश्मीरियों को सरकारी नौकरियों के अवसर भी घटे क्योंकि अब कश्मीर के बाहर के लोग भी इनमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य को दो भागों में बांटने के बाद चुनौतियों के बावजूद राज्य में अनेक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए हैं, भले ही कुछ लोगों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहलों ने राज्य में विकास को गति दी है। जम्मू कश्मीर में खाड़ी देशों द्वारा निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ी है जिससे जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। इससे राज्य के निवासियों में आशा की किरण पैदा हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार, राज्य में आतंकवादी व अलगाववादी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ने के कारण हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है।

सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या जहां 2019 में 80 थी, वह 2023 में घट कर 33 रह गई। इसी प्रकार सिविलियन मौतों की संख्या भ्भी 2019 में 44 से घट कर 2023 में 12 रह गई। राज्य में इसके पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्य में बदलते परिवेश के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बहुत बढ़ा और इस सकारात्मक परिघटना ने विधानसभा चुनाव का रास्ता खोल दिया। कश्मीर में हालिया संसदीय चुनाव में 58.46 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जो 2019 में आम चुनाव से 30 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य के दो भागों में विभाजन के बाद 'परिसीमन' भी पूरा किया। 2022 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 87 से बढ़ कर 114 हो गई है, जिसमें पाक-अधिकृत कश्मीर-पीओके की 24 सीटें भी शामिल हैं।

सीटों में इस वृद्धि के कारण शक्ति संतुलन बदला है और यह आगामी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा का दावा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा कश्मीर में इसके बाद लागू की गई उसकी नीतियों के कारण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हालिया लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विजय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस-एनसी व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-पीडीपी भी पुनर्जीवित हुई हैं। इस चुनाव में उनकी सदस्य संख्या बढ़ी है तथा वे लंबे समय से लंबित मुद्दों को सामने लाने में सफल हुई हैं। हालांकि, कांग्रेस को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और एनसी अपने द्वारा लड़ी तीन सीटों में से दो पर विजय प्राप्त करने में सफल रही, पर तीसरी सीट पर भी उसने मजबूत चुनौती पेश की थी।

क्षेत्र में आतंकवाद के इतिहास तथा चुनावों में धांधली के आरोपों के बावजूद हाल में हुए चुनाव मोटेतौर से स्वच्छ एव निष्पक्ष माने जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव केन्द्र सरकार के प्रयासों की परीक्षा होगी जो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संघ के साथ जोड़ना चाहती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अनुच्छेद 370 की वापसी के साथ शुरू हुई है जो इस राज्य को विशेष दर्जा देती थी। यह निर्वाचन आयोग की भी परीक्षा होगी कि वह बिना किसी हिंसा के चुनाव कराने में सफल हो। राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिनमें अभियान की रणनीतियां बनाना, गठबंधन के प्रयास तथा उम्मीदवारों का चयन शामिल हैं। चुनाव की योजना बनाने के लिए पीपुल्स कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कान्फ्रेंस अपनी बैठकें कर चुकी हैं।

राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसमें अभियान की रणनीति बनाने के साथ ही संभावित गठबंधनों पर गौर करना व विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना शामिल हैं। पीपुल्स कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तथा नेशनल कान्फ्रेस लगातार पार्टी के स्तर पर बैठकें कर चुनाव की रणनीति और योजना बना रहीं हैं। यदि विधानसभा चुनाव निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के अनुसार होते हैं तो घाटी में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में ध्रुवीकरण तथा अलगाववादी विमर्श भी देखने को मिला था। आशंका है कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही इन परिघटनाओं को बल मिल सकता है। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी और अन्य ने चुनावी बयानबाजी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की चुनाव कराने की घोषणा का समर्थन करने वाली अन्य पार्टियों ने भी चुनावी प्रचार शुरू करने की पहल कर दी है। इनमें कांग्रेस, भाजपा, माकपा तथा पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी-डीपीएपी भी शामिल हैं।

2014 में जम्मू कश्मीर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री घोषित करने के पहले राज्य में 49 दिन तक राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा था। 2018 में भाजपा ने सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का निर्णय किया जिसके चलते राज्य में एक बार फिर राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा। इसके बाद नवंबर, 2018 में विधानसभा भंग कर दी गई और दिसंबर, 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद से राज्य में राज्यपाल शासन चल रहा है। सरकार को यह तय करना है कि वह कश्मीर घाटी में अलगाववाद की कुछ घटनाओं से निपटने के लिए हस्तक्षेप करना चाहती है अथवा वह चुनाव के पहले राज्य में कोई पुनर्गठन योजना लागू करेगी। हालिया संसदीय चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था। इसके अंतर्गत नेशनल कान्फ्रेंस ने कश्मीर में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि कांग्रेस ने जम्मू और उधमपुर में चुनाव लड़ा।

'इंडिया' गठबंधन की साझीदार होने के बावजूद पीडीपी को इस गठजोड़ में शमिल नहीं किया गया और उसने नेशनल कान्फ्रेंस के खिलाफ कश्मीर में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस और एनसी साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के अनुसार, पीडीपी से गठबंधन कठिन होगा क्योंकि संसदीय चुनाव में वे एक-दूसरे के खिलाफ थे। यदि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करना चाहें तो उनको एकजुट होकर 'इंडिया' से गठजोड़ करना चाहिए। कश्मीर विधानसभा चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है जिनसे एक दशक बाद राज्य में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

> "डिजिटल लर्निंग के साथ-साथ शिक्षा और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का यह बजट आवंटन एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में मदद करेगा।"

रीतू श्रीवास्तव
(लेखिका शिक्षाविद हैं)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2024-25 के बजट को 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, अनुसंधान और नवाचार को पहले की तरह प्राथमिकता देते हुए, सविकसित भारत के लिए बजट भारत की साख को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा उठाए गए ये व्यापक और ठोस उपाय हैं जो सभी हितधारकों-छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के लिए फायदेमंद होंगे। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए बजट आवंटन 30 प्रतिशत बढ़ाकर 1.48 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें स्कूलों में 265 मिलियन छात्र, उच्च शिक्षा में 43 मिलियन और कौशल संस्थानों में 10 मिलियन से अधिक शिक्षार्थी नामांकित हैं। 2024-25 के लिए 73,498 करोड़ रुपये का बजट आवंटन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए अब तक का सबसे अधिक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसे स्वायत्त निकायों को भी अब तक का सबसे अधिक आवंटन मिला है। समग्र शिक्षा, पोषण और पीएम-श्री जैसी प्रमुख योजनाओं को 3,250 करोड़ रुपये मिले हैं। बजट में कौशल और प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं के लिए कौशल विकास और इंटर्नशिप के अवसर, और पूरे क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। सरकार ने 25000 छात्रों को सालाना 1.5 लाख से 7.5 लाख तक की 'मॉडल कौशल ऋण योजना' शुरू की है और उच्च घरेलू शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर साल एक

लाख छात्रों को 3त्न की वार्षिक ब्याज छूट के साथ 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया है। इस कदम से निश्चित रूप से घरेलू संस्थानों में नामांकन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही छात्रों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कौशल विकास क्षेत्र के लिए कई पहलों की रूपरेखा भी बताई।

इनमें उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन शामिल है। सरकार द्वारा 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर एक स्वागत योग्य कदम है, इससे युवाओं को जुड़ाव मिलेगा और रोजगार और व्यावहारिक कौशल में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) योजना में 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में कुल 3525.15 करोड़ रुपये (7.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएससी को भारी आवंटन मिला है, जो पिछले बजट की तुलना में काफी अधिक है। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई-लर्निंग, शोध एवं नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र और कुछ विशिष्ट संस्थानों जैसे क्षेत्रों को अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। डिजिटल ई-लर्निंग के तहत सरकार वर्चुअल लर्निंग की क्षमता का दोहन करने और पोर्टेबिलिटी और लचीले अध्ययन विकल्पों को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ जोड़ने की योजना बना रही है।

'आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन' योजना में 2024-25 में 480 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह 2023-24 के आवंटन से 80 करोड़ रुपये अधिक है। शोध एवं नवाचार के लिए बढ़ा हुआ बजट विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित है। स्कूल स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नए शैक्षणिक ढांचे की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण खंड को इसका उचित हिस्सा मिला है। 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 3 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना' योजना को बजट में 255 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) जिसे पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के नाम से जाना जाता था, के लिए बजट 1814.94 करोड़ रुपये रखा गया है। उत्कृष्ट संस्थानों के लिए 1800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 'बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार ईएपी (मेरिटे)' योजना में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह पिछले साल के बजट से 100त्न अधिक है।

एनईपी 2020 का कहना है कि नीति का उद्देश्य भारत में 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना होना चाहिए जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच हो। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने शिक्षा के लिए एक महत्वाकांक्षी पैकेज तैयार किया है ताकि यह विकासोन्मुख, समावेशी और प्रगतिशील हो। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका कार्यान्वयन है। शिक्षा मंत्री द्वारा बताए गए अनुसार शिक्षा के लिए बजट की विशेषताएँ 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनने की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

आप की बात

हिंदुओं पर अत्याचार

इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के वजूद में आ जाने के बावजूद हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। दास ने दावा किया कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं पर हर दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य बांग्लादेश में काम कर रहे सभी 25 लाख हिंदुओं को उनकी नौकरियों से हटाना है। यह सब कुछ नई सरकार के सपोर्ट और एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। यह सब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत तथा उनके गृह मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से हिंदुओं से माफी मांगने के बाद हो रहा है। स्पष्ट है कि यह बांग्लादेश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और अंतत: देश छोड़ कर जाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से राजनयिक स्तर पर सीधे बात कर इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने का आग्रह करना चाहिए। इसके लिए भारत को आवश्यकता होने पर बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव डालने, भारत में उसकी परिसंपत्तियां जब्त करने, उसके साथ व्यापार व अन्य संबंध तोड़ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में व अन्य मंचों पर मुद्दा उठाने पर विचार करना पड़ सकता है।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

आरक्षण: जटिल समस्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में उप-विभाजन को लेकर दिए फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान एक प्रकार से अपनों का अपनों के उत्थान के विरुद्ध अभियान है। आखिर भारत बंद का आह्वान करने वाली ये कैसी लीडरशिप है जो कहती है कि गरीब, पिछड़े और अक्षम वहीं रहें और जो ऊपर उठ गए हैं या सक्षम बन गए हैं उन्हें ही पीढ़ी दर पीढ़ी शीर्ष पर चढ़ाते जाएं। ऐसे में कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भला क्या करे? बरसों से चल रही स्वार्थ की राजनीति ने आरक्षण नीति को इतना उलझाकर रख दिया है कि उसे सुधारना तो दूर उसमें गरीब व अक्षम लोगों के हित में फैसले लेना भी असंभव सा हो गया है। ऐसे में राजनेता, कानूनविद और समाजसेवी तीनों को मिलकर आरक्षण जैसी जटिल समस्या का दीर्घकालीन समाधान ढूंढें ताकि हर छोटी-छोटी बात पर लोग सड़क पर न आने पाएं। बाबा साहब की फोटो लेकर आंदोलन के नाम पर हिंसक उपद्रव करने वालों को स्वयं अंबेडकर के शब्द याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत में संविधान लागू होने के बाद अब आंदोलन, धरना, हड़ताल, आदि असंवैधानिक गतिविधियों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। क्या आरक्षण समर्थक समाज में संवाद का कोई रास्ता खोजेंगे?

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें एससी-एसटी, यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्ग बना सकती हैं। इसके विरोध में समूचा विपक्ष खड़ा हो गया। सरकार ने भी राजनीतिक मजबूरियों के कारण इसे परोक्ष रूप से यथावत रखने का आश्वासन दे दिया है। गंभीरता से गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई विसंगति नहीं है और यह संविधान की भावना के अनुकूल सर्वाधिक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मगर वोटों की राजनीति और भीडतंत्र ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए भारत बंद का आह्वान कर दिया। क्या आजादी के बाद से आरक्षण का लाभ ले चुकी एससी-एसटी की क्रीमी लेयर यह नहीं चाहती कि उनके अन्य गरीब बंधु-बांधवों को भी उन्हीं की तरह आगे आने का मौका मिले? ऐसे में आरक्षण की सीमा बढ़ाने व जातीय गणना कराने की मांग करने वाले नेताओं की नीयत पर भी सवाल उठता है कि क्या वे देश में एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा कर अपने निहित राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए देश को कमजोर करना चाहते हैं? यह स्थिति निश्चित रूप से चिन्ताजनक है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

एक राष्ट्र एक चुनाव

प्रधानमंत्री मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे से विपक्षी दलों के नेता भी सहमत होने लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे का समर्थन करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है और इस पर अपनी सहमति दी है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के लिए एक राष्ट्र चुनाव का नारा लागू करने की बात दोहराते हुए सभी दलों से इस पर सहमति देने की बात कही थी। हालांकि, शरद पवार ने चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव घोषणा को देखते हुए प्रधानमंत्री का मजाक भी उड़ाया। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सभी राजनीतिक दलों की सहमति और अनेक संविधान संशोधनों के बाद लागू हो सकती है। अत: शरद पवार के व्यंग्य या मजाक का कोई तुक नहीं है। देश की वर्तमान विभाजित राजनीति तथा भाजपा-विरोधी दलों के अधिकांश नेताओं की येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने की लालसा के कारण फिलहाल ऐसी अवधारणा के फलीभूत होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अच्छे विचारों को बार-बार दुहराना भी लाभदायक है।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

अगले दो साल में दो लाख नौजवानों को देंगे सरकारी नौकरी

मुजफ्फरनगर में आयोजित ऋण मेला में शामिल हुए सीएम, 5000 युवाओं को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ मुजफ्फरनगर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगले दो साल में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां निकलती थीं तो पश्चिमी यूपी के युवाओं को उससे वंचित रखा जाता था, मगर आज यहां के युवा और बेटियां नौकरियां प्राप्त कर रही हैं।

सीएम योगी ने कहा कि शुक्रवार से प्रदेश में पुलिसकर्मियों की 60 हजार से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में यहां के युवाओं को बढ़चढ़ कर भाग लेना होगा। कोई माई का लाल युवाओं की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। उन्होंने आगाह किया कि किसी ने भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भेजने के साथ ही उसकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाएगा।

सीएम योगी गुरुवार को यहां बीआईटी कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला में शामिल हुए। इस दौरान 5 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों एवं एमएसएमई उद्यमियों में ?30 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनपदों में हर तीन माह में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर को सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। खासकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर वही स्थान है, जो 10 साल पहले दंगों की आग में झुलसता था। आज ये दंगामुक्त हो चुका है और यहां धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकलती है। सीएम ने कहा कि यहां की नई पहचान विकास, सुरक्षा, नौजवानों को काम, सरकारी नौकरी के रूप में बन रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनके उस बॉन्ड का क्या हुआ, जिसमें एक लाख रूपए देने के लिए भरवाया गया था। मुख्यमंत्री ने सपा मुखिया को लेकर कहा कि उनके लोग प्रदेश की बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और वह दुष्कर्मियों के साथ खड़े रहते हैं। सीएम योगी ने इसे सपा का मॉडल बताया। सीएम ने आश्वस्त किया कि बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करते मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुजफ्फरनगर के 38 मार्गों के लिए यहां के विधायकगणों ने प्रस्ताव दिया है। यहां मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। हमारी सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाने वाली यूपी की बेटी पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है।

प्रदेश के युवाओं की खेल प्रतिभा को आकार देने के लिए मेरठ में प्रदेश का पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा हैं। जब ये बनकर तैयार होगा तो यहां का नौजवान ओलम्पिक में गोल्ड और सिल्वर लेकर आएगा। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश के 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है और जो भी नौजवान देश के लिए मेडल जीतेगा, यूपी में सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में कोई आना नहीं चाहता था। यहां से लोग भागते थे, कैराना से पलायन हो रहा था। आज यहां से उद्योग भागते नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। सहारनपुर और जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। हाईवे का नेटवर्क सुदृढ़ हो रहा है।

आज से प्रांरभ होगी अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा

बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को मिलेगी परीक्षा केंद्र में एंट्री

● **किए गए कड़े सुरक्षा प्रबंध, हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती, सभी 1174 परीक्षा केंद्रों के बाहर लगाए जाएंगे जैमर**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए फूलप्रूफ प्लान बनाया है। इसके तहत योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की 23 अगस्त शुक्रवार से दो पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किये हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जबकि केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरों से गहन निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मालूम हो कि योगी सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है, जिसकी परीक्षाएं 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को प्रदेश के सभी 67 जनपदों के 1174 सेंटर पर आयोजित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) की अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक (मजिस्ट्रेट) के रूप में कार्य करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा केन्द्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गयी हैं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया है जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। इतना ही नहीं नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्ते भी मुस्तैद रहेंगे। वहीं केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। प्रदेश के जिन सेंटर पर एक हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे, वहां पुलिस उपाधीक्षक तैनात रहेंगे। वहीं एक हजार तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर इंस्पेक्टर और पांच सौ तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कर्मियों में से 50 प्रतिशत जिलाधिकारी और शेष 50 प्रतिशत केन्द्र व्यवस्थापक (प्रधानाचार्य) द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इनमें परीक्षा सहायक प्रथम एवं द्वितीय जिलाधिकारी और केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त किये जाएंगे जबकि 12 अभ्यर्थियों पर एक अंतरीक्षक को तैनात किया जाएगा। इसके साथ सहयोगी अंतरीक्षक भी तैनात रहेंगे।

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की चैकिंग, फ्रिस्किंग एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश फिजिकल फ्रिस्किंग, एचएचएमडी द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट एवं फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही दिया जायेगा। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर एफआरआईएस कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन में संशय होने पर अभ्यर्थी का आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा सभी केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिये जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा कक्ष एवं केन्द्र में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जा रही है।

वन्यजीवों को बचाने के लिए राजधानी के 250 विद्यार्थी जनजागरूकता फैलाएंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन विभाग ने ईको टूरिज्म के माध्यम से उप्र की जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक करने की एक अनोखी पहल की है। इस क्रम में लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 बच्चों द्वारा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत अन्य महत्वपूर्ण ईको पर्यटन स्थलों पर आधारित आर्ट एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता कराई जा रही है। यह छात्र आर्ट एण्ड क्राफ्ट के माध्यम से बतायेंगे कि कैसे वन्य जीवों को संरक्षित रखा जा सकता है। इसके तहत ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों को 25 अगस्त, 2024 को आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए अच्छी शुरुआत है। विद्यार्थी आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वन्य जीवों को बचाया जाए और प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। उप्र विविधताओं से भरा राज्य है। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां 16 हजार 582 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र के साथ अनेक अति सुंदर परिदृश्य, नदियां, सुंदर झरने हैं। लुप्तप्राय पक्षियों और वन्य जीवों की उपलब्धता है। जयवीर सिंह ने बताया कि उप्र पर्यटन विभाग का प्रयास है कि, देश-दुनिया से जो भी पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों के साथ नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लें। प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताएं। यहां के सुंदरतम स्थल अवश्य ही पर्यटकों/आगंतुकों के तन-मन को आनंद प्रदान करेगी। पारिस्थितिकी पर्यटन के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है।

अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामला

आरोपी के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या

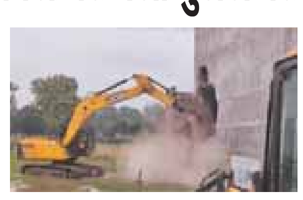

भदरसा कस्बे (अयोध्या) में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े फरमान के बाद जिला प्रशासन ने घटना के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि व तालाब पर बनाए गए मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इससे पहले तहसील प्रशासन की जांच मे आरोपी की बेकरी तालाब की भूमि पर पाए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने बेकरी निर्माण इकाई पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करा दिया था।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध ढंग से तालाब की जमीन पर और चकरोड की जमीन पर कब्जा करके किया गया था। विकास प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस दी जा चुकी थी। उसके बाद उनके द्वारा मानचित्र नहीं दाखिल किया गया। न तो किसी प्रकार की रुचि ही दिखाई गई। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जून में ही पारित कर दिया गया था। इस आदेश का तामीला कराते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को एक्टिवेट कराया गया है। एसडीएम के द्वारा आगे जांच की जा रही है, आगे भी जो अवैध संपत्ति पाई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है।

यूपी में समाजवादी पार्टी ही है भाजपा का एकमात्र विकल्पः अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया अब भविष्य की तैयारी का समय है। देश में भाजपा को रोकने की ताकत समाजवादी पार्टी में ही है। उत्तर प्रदेश में वही एक मात्र विकल्प है। पीडीए ही भाजपा को मात देगा।

अखिलेश यादव गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण संविधान खतरे में है। वह आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। भविष्य में नई पीढ़ी के लिए काम करना ही होगा। यादव ने कहा कि पीडीए से भाजपा घबराई हुई है। इसलिए वह षडयंत्र करने से बाज नहीं आ सकती है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को बदनाम करने और निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भाजपा कर रही है। उत्तर प्रदेश का विकास ठप्प है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सत्ता लोलुप भाजपा नई-नई चालें चलती रहेगी। उससे सावधान रहना है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में जनता त्रस्त है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी से नौजवान परेशान है। भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। उनकी फसलों को एमएसपी नहीं मिल रही है। उनकी आय दुगनी करने का दावा भी धोखा साबित हुआ है। प्रदेश में पूंजी निवेश के नाम पर हवाई दावे किए गए हैं। प्रदेश में एक भी नया उद्योग या बिजली घर नहीं लगा।

यादव ने आह्वान किया कि प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। भाजपा ने प्रदेश को दशकों पीछे धकेल दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही जीवन में बदलाव आएगा और गांव की तस्वीर में भी परिवर्तन आएगा। यादव ने कहा कि भाजपा जनता के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं। करोड़ों का बजट कहां गया पता नहीं चल रहा है। वृक्षारोपण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा ने पूरी व्यवस्था को तहत नहस कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को और भी ज्यादा मेहनत से जुटे रहना हैं। समाजवादी पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का समयबद्ध तरीके किया जा रहा भुगतानः जीएस प्रियदर्शी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कराये गए कार्यों के समयबद्ध मजदूरी भुगतान को लेकर उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में समयबद्ध मजदूरी भुगतान (ज्पउमसल च्ंलउमदज) 96 प्रतिशत पहुंच गया है जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस साल प्रदेश में अब तक मजदूरी भुगतान के लिए 96 प्रतिशत फंड ट्रांसफर आर्डर (एफटीओ) समय-सीमा में जारी किया गये हैं।

उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्यालय स्तर पर मनरेगा की सतत मानीटरिंग की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ने समयबद्ध मजदूरी भुगतान में निरंतर प्रगति हो रही है। आयुक्त, ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि प्रदेश में मांग के अनुसार अधिक से अधिक श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समयबद्ध मजदूरी भुगतान (टाइमली पेमेंट) बीते 5 वर्षों की बात करें, तो मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यो के समयबद्ध मजदूरी भुगतान को लेकर वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक प्रगति देखने को मिली है।

वर्ष 2019-20 में 85 फीसदी समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में 87 फीसदी, वर्ष 2021-22 में 86 फीसदी, वर्ष 202-23 में 80 फीसदी तो, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 92 फीसदी से ज्यादा का समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब 2024 तक 96.51 फीसदी समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया।

अडानी के खिलाफ जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

● **पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक के बाद नाराज प्रदेश अध्यक्ष राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे और अडाणी समूह से जुड़े मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर गुरुवार को राजधानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार राय के नेतृत्व में ईडी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल पूर्वक रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। जिसके बाद नाराज अजय राय कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।अजय राय ने कहा कि यह बात आइने की तरह साफ हो गई कि अडानी का साम्राज्य केन्द्र सरकार के संरक्षण और सरकारी एजेन्सियों की मिलीभगत के दम पर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं तमाम जांच एजेन्सियों का दुरूपयोग कर अड़ानी को कई फायदे पहुंचाये गये। कौड़ियों के भाव बन्दरगाह और एयरपोर्ट दिये गये। अभी हाल ही में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने न सिर्फ एक बार फिर अडानी की काली करतूतों का पर्दा फॉश किया बल्कि सेबी की चेयरमैन और अडानी के मध्य एक भ्रष्ट नेक्सस की पोल भी खोली। दुर्भाग्य यह है कि जिन जांच एजेन्सियों पर अडानी के खिलाफ जांच करने का दारोमदार था वह खुद उस भ्रष्टाचार का हिस्सा थीं। नतीजा अडानी का क्रोनी कैप्टिलिज्म जारी रहा और सरकार उस पर पर्दा डालती रही।

राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के आम जन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार इस अनैतिक गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाती रही। एक बार फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेपीसी के गठन की मांग की है।

एक लाख का ईनामी कुख्यात अपराधी झारखंड से गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने एक लाख के ईनामी कुख्यात अपराधी अंकित यादव निवासी लक्ष्मीकुण्ड, थाना लक्सा, जनपद वाराणसी को झारखंड से गिरफ्तार किया।

एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि जनपद वाराणसी के थाना दशाश्वमेध क्षेत्रान्तर्गत दिन-दहाड़े अंकित यादव द्वारा गैंग के साथियों के साथ मिलकर अपने प्रतिद्वंदी दिनेश यादव के घर पर चढ़कर जान मारने की नियत से अन्धाधुन्ध फायरिंग की गयी थी। जिसमें दिनेश यादव सहित कुल 3 लोग गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गये। मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। इस संबंध में थाना दशाश्वमेध, वाराणसी पर अंकित यादव और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके कई साथियों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुख्य अभियुक्त अंकित यादव घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसपर जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा एक का पुरस्कार घोषित किया गया था। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि अंकित यादव झारखंड के पाकुर जिले में है। इसके बाद एक टीम वहां भेजी गई। जिसने मुहल्ला अन्नपूर्णानगर कॉलोनी के पास से अंकित यादव को गिरफ्तार कर थाना पाकुर जनपद पाकुर(झारखंड) में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ से पाया गया कि वह एक मनबढ किस्म का दबंग अपराधी है। इसका अपने क्षेत्र के कुछ मनबढ़ किस्म के लड़को का एक गैंग बनाया है। यह गैंग आस-पास को लोगों से वसूली आदि का काम करता है। आस-पास के लोगों में इसका इतना भय है कि लोग इसकी शिकायत पुलिस से करने में डरते थे। इसके विरुद्ध मारपीट आदि के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को थाना पाकुर नगर कोतवाली (झारखंड) में दाखिल कर न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

यूपी में और बढ़ेगा अनाजों की रानी मक्के का जलवा

● **अगले तीन साल में उत्पादन दोगुना करने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में मक्के का उत्पादन 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तय अवधि में इसे बढ़ाकर 27.30 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। इसके लिए रकबा बढ़ाने के साथ प्रति हेक्टेयर प्रति कुंतल उत्पादन बढ़ाने पर भी बराबर का जोर होगा।इसके लिए योगी सरकार ने 'त्वरित मक्का विकास योजना' शुरू की है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023/2024 में 27.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अभी प्रदेश में करीब 8.30 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। कुल उत्पादन करीब 21.16 लाख मिट्रिक है। प्रदेश सरकार की मदद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबद्ध भारतीय मक्का संस्थान भी कर रहा है। धान और गेंहू के बाद यह खाद्यान्न की तीसरी प्रमुख फसल है। उपज और रकबा बढाकर 2027 तक इसकी उपज दोगुना करने के लक्ष्य के पीछे मक्के का बहुपयोगी होना है। अब तो एथनॉल के रूप में भविष्य में इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

बात चाहे पोषक तत्वों की हो या उपयोगिता की। बेहतर उपज की बात करें या सहफसली खेती या औद्योगिक प्रयोग की। हर मौसम (रबी, खरीफ एवं जायद) और जलनिकासी के प्रबंधन वाली हर तरह की भूमि में होने वाले मक्के का जवाब नहीं। मालूम हो कि मक्के का प्रयोग ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों,कुक्कुट एवं पशुओं के पोषाहार,दवा, कास्मेटिक, गोद, वस्त्र, पेपर और एल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा मक्के कोआटा, धोकला, बेबी कार्न और पाप कार्न के रूप में तो ये खाया ही जाता है। किसी न किसी रूप में ये हर सूप का अनिवार्य हिस्सा है। ये सभी क्षेत्र संभावनाओं वाले हैं।

आने वाले समय में बहुपयोगी होने की वजह से मक्के की मांग भी बढ़ेगी। इस बढ़ी मांग का अधिक्तम लाभ प्रदेश के किसानों को हो इसके लिए सरकार मक्के की खेती के प्रति किसानों को लगातार जागरूक कर रही है। उनको खेती के उन्नत तौर तरीकों की जानकारी देने के साथ सीड रिप्लेसमेंट (बीज प्रतिस्थापन) की दर को भी बढ़ा रही है। किसानों को मक्के की उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए सरकार पहले ही इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में ला चुकी है। मक्के में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेड, शुगर, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल मिलता है। इस लिहाज से मक्का की खेती कुपोषण के खिलाफ जंग साबित हो सकती है। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्के को अनाजों की रानी कहा गया है। विशेषज्ञों की मानें तो उन्नत खेती के जरिये मक्के की प्रति हेक्टेयर उपज 100 क्विंटल तक भी संभव है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन लेने वाले तमिलनाडु की औसत उपज 59.39 कुंतल है।

देश के उपज का औसत 26 कुंतल एवं उत्तर प्रदेश के उपज का औसत 2021-22 में 21.63 कुंतल प्रति हेक्टेयर था। ऐसे में यहां उपज मक्के की उपज बढाने की भरपूर संभावना है। मक्के की तैयार फसल में करीब 30 फीसद तक नमी होती है। अगर उत्पादक किसान या उत्पादन करने वाले इलाके में इसे सुखाने का उचित बंदोबस्त न हो तो इसमें फंगस लग जाता। सरकार अनुदान पर ड्रायर मशीन उपलब्ध करा रही है। 15 लाख की पर 12 लाख अनुदान दिया जा रहा। कोई भी किसान निजी रूप से या उत्पादक संगठन इस मशीन को खरीद सकता है। इसी तरह पॉप कॉर्न मशीन पर भी 10 हजार का अनुदान देय है।

मक्के की बोआई से लेकर प्रोसेसिंग संबंधित अन्य मशीनों पर भी इसी तरह का अनुदान है। प्रदेश सरकार प्रगतिशील किसानों को उत्पादन की बेहतर टेक्निक जानने के लिए प्रशिक्षण के लिए भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान भी भेजती है। कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार उन्नत प्रजातियों की बोआई करें। डंकल डबल, कंचन 25, डीकेएस 9108, डीएचएम 117, एचआरएम-1, एनके 6240, पिनैवला, 900 एम और गोल्ड आदि प्रजातियों की उत्पादकता ठीकठाक है। वैसे तो मक्का 80-120 दिन में तैयार हो जाता है। पर पापकार्न के लिए यह सिर्फ 60 दिन में ही तैयार हो जाता है।

मलेरिया विभाग में तैनात इंस्पेक्टर को हटाने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नगर विकास मंत्री सहित अन्य विधायकों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मलेरिया विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर को उप्र शासन के उप सचिव अवनींद्र कुमार शुक्ल ने हटाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शिकायती पत्र का हवाला देते हुए तत्काल आरोपित को मुख्यालय से हटाकर दूसरे जनपद ट्रांसफर करने और जांच करने को कहा है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि बिना पद के लंबे समय से राज्य मलेरिया मुख्यालय में इंस्पेक्टर समीउल्ला खान तैनात हैं। गलत तरीके से वेतन आहरित किया जा रहा है। इनके खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोप सिद्ध हो चुके हैं। पूर्व डीजी हेल्थ डॉ. दीपा त्यागी ने भी मलेरिया इंस्पेक्टर को हटाने के लिए शासन को पत्र लिखा था। वहीं अपर निदेशक मलेरिया डॉ. सईद अहमद का कहना है कि अभी मुझे शासन के पत्र की जानकारी नहीं है।

पीएम आवास योजना शहरी के पात्रता की जांच में न करें लापरवाही: जिलाधिकारी

● पात्रों को योजना का अवश्य दिलाएं लाभ, कार्य पर सतत रखें निगरानी

पीएम आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेतीं डीएम सी. इन्दुमती।

फतेहपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में डीएम सी. इंदुमती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतो के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों की पात्रता की जांच एवं जीओ टैगिंग समय से नियमानुसार पारदर्शिता के साथ सर्वेयर करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे।

डीएम ने सभी अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेयर द्वारा की गई जांच की रैंडम जांच करे और उनके कार्य पर सतत निगरानी बनाए रखें। पात्रों को योजना का लाभ अवश्य दिलाएं। एडीएम (न्यायिक) एवं परियोजना निदेशक डूडा को निर्देशित किया कि नपाप एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों/सभासदों के साथ बैठक करा लें और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाए कि नियमानुसार कार्यवाही कर पात्रों को ही लाभ दिया जाए किसी भी सूरत में अपात्रों को लाभ नहीं दिया जाए। पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के जो आवास निर्माण के कार्य अपूर्ण है उसको समय से पूरा कराएं। द्वितीय, तृतीय किस्तों के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्यवाही पूरी कर धनराशि मुहैया कराई जाए। ताकि आवास पूर्ण हो सके और जनपद की रैंकिंग सही रहे। पीएम आवास योजना शहरी में नामित समिति के सदस्य स्क्रूटनी के पश्चात ही पत्रावली प्रस्तुत करें। एडीएम न्यायिक, प्रभारी परियोजना निदेशक डूडा अभिनीत कुमार, अधिशाषी अधिकारियों सहित संबंधित उपस्थित रहे।

कोलकाता मे महिला डाक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में वकीलो ने कैडिल मार्च निकाला

कानपुर देहात। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता के विरोध में गुरुवार को जनपद न्यायालय के वकीलों ने एकीकृत बार एसोसिएशन के तत्वावधान में घटना का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट करते हुए कैंडल मार्च निकालाएऔर जनपद न्यायालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पास इकट्ठा हो श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की।इस अवसर पर एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम कटियार एवं महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया ने कहा कि हम अधिवक्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम पश्चिम बंगाल की घटना का जोरदार विरोध करें और चिकित्सा व्यवसाय रत डाक्टरो अधिवक्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था की मांग सरकार से करें।कानपुर देहात बार एसोसिएशन के संस्थापक महामंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार से संगठित मांग की जाए कि सरकार केंद्रीय कानून लाये और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करे। जितेन्द्र चौहान ने कहा कि अब समय की मांग है कि सरकार तत्काल मेडिकल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे।

इस अवसर पर सरोज दीक्षित नरेश सिंह अश्वनी कुमार बाजपेई कमल सिंह यादव पूर्व महामंत्री महेन्द्र मोहन श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ कटियार पूर्व मंत्री ज्योति सिंह जिला शैलेन्द्र कुमार तिवारी अरविन्द कुशवाह अमर सिंह भदौरिया राजीव दीक्षित विजय लक्ष्मी सैनी के के पाण्डे विनोद चौहान रईस अहमद जय सिंह यादव अशोक सचान विकास गुप्ता विराट बाजपेई अभय प्रताप सिंह योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान प्रमुख रहे।

महर्षि विद्या मंदिर में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री ने बांटे पुरस्कार

● गीत गोविंद प्रकाशन व ममता फाउंडेशन की प्रतियोगिताओं का हुआ समापन

महर्षि विद्या मंदिर में पुरस्कार वितरित करतीं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति।

फतेहपुर। गीत गोविंद प्रकाशन ने ममता फाउंडेशन की विभिन्न विद्यालयों में कराई गई प्रतियोगिता के समापन के पश्चात गुरूवार को शहर के महर्षि विद्या मंदिर, प्लेवे इंग्लिश स्कूल व आरएस एक्सेल इंग्लिश एकेडमी में पुरस्कार वितरण किया गया।

महर्षि विद्या मंदिर के पुरस्कार वितरण में विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, विशेष अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सावन गुप्ता एवं अनुभव शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उन्हे प्रमाण पत्र एवं मेडल से सम्मानित किया। महर्षि विद्या मंदिर में कनिष्ठ में प्रथम शिवांश शुक्ला, द्वितीय कुमार अंश, निशांत सानू तृतीय व वरिष्ठ में महिमा गुप्ता प्रथम, तूलिका द्विवेदी द्वितीय, दीक्षा गुप्ता तृतीय, रुद्रकांत दुबे चतुर्थ, अदिति सिंह ने पंचम स्थान प्राप्त किया।

प्लेवे इंग्लिश स्कूल में प्रथम रहीमा अली, द्वितीय अनन्या, तृतीय सोनल कसुधन, चतुर्थ रिचा सिंह एवं मयंक प्रताप सिंह पंचम स्थान प्राप्त हुआ। इसी तरह आरएस एक्सेल इंग्लिश एकेडमी सिविल लाइंस में कनिष्ठ में प्रथम वानी तिवारी, द्वितीय आशू पटेल, तृतीय आर्मिश सैफी, मरियम शोभी चतुर्थ एवं पंचम स्थान में अरव मेहरा रहे। वरिष्ठ स्तर में प्रथम प्रियांश कुमार गुप्ता, द्वितीय दृष्टि सिंह, तृतीय इशिका अग्रहरि, चतुर्थ अमृता श्रीवास्तव एवं कृतिका तिवारी पंचम में प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में राजेश मिश्रा गीत गोविंद प्रकाशन से हार्दिक अग्रहरि, लैक्मे से मीनाक्षी गुप्ता एवं नीतू शर्मा उपस्थित रहे।

विद्युत विभाग के चेकिंग अभियान से लोगों में मचा हड़कम्प

चेकिंग अभियान की जानकारी देते एसडीओ व विजिलेंस टीम।

● काटे पैंतीस कनेक्शन वसूले साढ़े तीन लाख रुपये

गुरसहायगंज (कन्नौज)। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विद्युत उपखण्ड अधिकारी ने उपनिरीक्षक व अवर अभियंता सहित विजिलेंस टीम के साथ ग्राम रजलामऊ में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। ग्रामीणों में हड़कम्प मच गया। विद्युत विभाग द्वारा करीब तीन दर्जन कनेक्सन काटे और आधा दर्जन पर कार्रवाई करते हुये लाखों रुपयो की राजस्व बसूली की है। गुरूवार को क्षेत्र के ग्राम रजलामऊ में उपखण्ड अधिकारी बृजेश कुमार सिरोही नें उप निरीक्षक टीपी सिंह, अवर अभियंता विकास कुमार एवं विजिलेंस टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाते हुये पैंतीस लोगों के केबल विच्छेदन किये और विद्युत चोरी करते रंगे हाथ पकडे गये छह लोगो पर मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही साढे तीन लाख रुपयों की राजस्व वसूली की।

डीएम व एसीपी ने परीक्षा केन्द्रों का सघन किया निरीक्षण

बाँदा। जिलाधिकारी नगेन्द्र प्रताप एवं अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र के साथ उप्र पुलिस भर्ती परीक्षा को जनपद में सकुशलढंग से नकल विहीन आयोजित कराये जाने हेतु जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्तए 2024 को जनपद बॉदा में चयनित 10 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को नकलविहीनी, शान्तिपूर्ण व सुचितापूर्ण तरीके से सकुशल सम्पन्न कराये जाने की तैयारियों के सम्बन्ध में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि बांदा, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बॉदा, राजकीय इण्टर कॉलेज तिन्दवारा बॉदा, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज बॉदा एवं अन्य परीक्षा केन्द्रों का गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की गयी तैयारियों का निरीक्षण किया।

उन्होंने परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, फर्नीचर, लाइट, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

परीक्षा के समय सभी ड्यूटी में लगे अधिकारीए कक्ष निरीक्षक, कर्मचारी अपने.अपने परिचय पत्र के साथ ही ड्यूटी पर रहेंगेए कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नही करेगा। उन्होंने प्रधानाचार्य को निर्देश दिए की प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी अवश्य लगे हो और निरन्तर संचालित रहेंए इसका कन्ट्रोल रूम भी बनाया जाए। परीक्षा केन्द्र के बाहर एक कक्ष निर्धारित कर सभी का मोबाइल फोन व सामग्री जमा करने हेतु व्यवस्था की जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्र में आवश्यक फर्नीचर एवं समय से सीटिंग प्लान सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण तैयारी के साथ समय से आज सायं काल तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने पाए। सभी परीक्षा केन्द्रों में बायोमैट्रिक उपस्थित भी की जायेगी।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी परीक्षार्थियों की गहनता से चेकिंग परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश से पूर्व अवश्य की जाए तथा कोई भी कर्मचारी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक घड़ी, डिवाइस, कैलकुलेटर आदि सामग्री लेकर नही जायेगा। परीक्षा केन्द्र के आस.पास कोई फोटोकॉपी की दुकान नही होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा के दौरान निर्बाद्ध विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी परीक्षा केदो में आवश्यक पुलिस व्यवस्था एवं सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई हैए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव, क्षेत्राधिकारी पुलिस, सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापक गण उपस्थित रहे।

क्विक न्यूज

सब्ज़ी लेने जा रहे युवकों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर

संडीला (हरदोई)। बाइक से सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे दो युवकों को अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। ग्राम भवानीपुर थाना कछौना निवासी सुधीर पुत्र विशुनदयाल तथा भवानीपुर निवासी गंगाराम पुत्र राम सिंह सब्ज़ी लेने के लिए अपनी कछौना चौराहे पर जा रहे थे। हरदोई की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों ही लोग सड़क पर उछलकर दूर जा गिरे। ट्रक मोटरसाइकिल को काफ़ी दूर तक खींचता हुआ ले गया। दोनों युवकों को इस दुर्घटना में गंभीर चोटें लगीं। दोनों को उठाकर पहले सीएचसी कछौना ले जाया गया जहां से दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ट्रक चालक ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने ट्रक को रोक लिया तथा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रेमिका से बिछड़ने पर खाया जहर, हुई मौत

फर्रूखाबाद। एक साथ जहर खाने वाले दोस्त दीपांशु उर्फसूरज की मौत हो जाने पर परिवार में मातम छा गया। दीपांशु उर्फ सूरज कोतवाली मोहम्मदाबाद के मोहल्ला किदवई नगर निवासी राजपाल शर्मा का 19 वर्षीय पुत्र था। दीपांशु के घर के सामने प्रमोद पाल का घर है प्रमोद पाल का 19 वर्षीय आकाश पाल व दीपांशु में दोस्ती थी। दोनों आज सुबह करीब 7.30 बजे घर से निकले थे। कही बाहर जाकर दोनो दोस्तों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों के बेहोश पड़े होने की जानकारी मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन को दीपांशु व आकाश को लोहिया अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान दीपांशु की मौत हो गयी। गंभीर रूप से बीमार आकाश का उपचार किया जा रहा है। दोनो दोस्त दिल्ली में अलग अलग नौकरी करते है। दीपांशु की मौत पर मां कुंती देवी आदि महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दीपांशु बीते सप्ताह दिल्ली से घर आया था, आते समय दीपांशु दिल्ली से किसी युवती को भगा लाया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया और दीपांशु को पकड़ कर ले गई थी। प्रेमिका के बिछड़ जाने से आहत दीपांशु ने जहर खाकर जान दी है। लेकिन उसके दोस्त के द्वारा जहर खाना अभी रहस्य बना हुआ है।

ग्रह कलह से तनाव में आकर विवाहिता ने डाई पीकर दी जान

फर्रूखाबाद। गृह कलह से तनाव में आयी विवाहिता नें डाई पी ली। जिससे उसकी मौत हो गयी। घटना के बाद ससुरालीजन फरार हो गये। पुलिस नें मामले की तहकीकात की। थाना राजेपुर के ग्राम पुरनपुर जिठौली निवासी 24 वर्षीय उपासना पत्नी अजीत सिंह का एक माह से ससुराल में विवाद चल रहा था। मिली जानकारी में मुताबिक उपासना नें गृहकलह के चलते घर में रखी डाई को पी लिया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार सोलंकी नें मौके पर आकर जाँच की। ग्राम सराह निवासी रामकृपाल की पुत्री उपासना का विवाह 11 जुलाई 2019 अजीत सिंह के साथ हुआ था। उपासना के आत्महत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार बताये गये। घटना के बाद उपासना के पति अजीत सिंह नें साले गोलू सिंह को जानकारी दी। जिसके बाद मृतका के स्वजन मौके पर आ गये। ससुराल पक्ष के मृतका के पति सहित सभी फरार हो गये। थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह सोलंकी नें बताया की शव का पोस्टमार्टम कराया जायेगा। विधिक कार्यवाही भी होगी।

महिला से चेन छीन कर फरार हुए बाइक सवार

फतेहपुर। घर से निकलकर भाई के घर जा रही एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े घटना को अंजाम दिया और मौके से भाग निकले। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सदर कोतवाली के फूलबाग कालोनी निवासी कमलेश सिंह पत्नी प्रेम सिंह गुरूवार दोपहर में अपने घर से निकलकर कुछ दूर रहने वाले अपने बड़े भाई के घर जाने के लिए निकली थीं। जैसे ही वह कुछ ही दूर निकली थीं कि तभी एक युवक उनके पास आया और गले से सोने की चेन छीनने का प्रयास करने लगा। चेन न छीन पाने से युवक ने कटर से चेन काट ली और आगे की ओर भागा। जहां एक बाइक में एक युवक हेलमेट लगाकर खड़ा था। बाइक में बैठकर बदमाश मौके से भाग निकला। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर जांच पड़ताल शुरू कर दी।

पेपर लीक होने से बच्चों का भविष्य होता बर्बाद: नरेश उत्तम

अमौली, फतेहपुर। केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले से ही लीक हो जाता है और इसका खुलासा होने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होने जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की आवाज उठाई थी इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यह बात गुरूवार को अमौली कस्बा स्थित राम सजीवन चंदा देवी महाविद्यालय में सपा के आयोजित छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कही।

छेड़खानी करने वाले को तीन वर्ष की कैद

हमीरपुर। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता ने थाना जरिया 19 मार्च 2016 को तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 16 मार्च 2016 को समय करीब सात बजे सुबह अपने दरवाजे के सामने सफाई कर रही थी। तभी पड़ोस का जीतू पुत्र इंद्रजीत लोधी आया और इशारा करने के बाद बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। जिस पर उसने शोर मचाया तो वह जाति सूचक शब्दों से गालीगलौज करने लगा। शोर सुनकर किशोरी की भाभी आ गई तो जान की धमकी देता हुआ भाग गया। जिस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एससी एसटीए छेड़खानी व पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित जीतू के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कठोर कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बरौर के निलंबित प्रिंसपल प्रकरण में प्र.प. ने की प्रबंध समिति से वार्ता

आपस में विचार विमर्श करते पदाधिकारीगण

पुखरायां। कानपुर देहात। प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों ने गुरुवार को भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के पटेल विद्या पीठ इंटर कॉलेज का दौरा किया। परिषद के पदाधिकारियों ने प्रबंध समिति के सदस्यों से निलंबित प्रधानाचार्य अवधेश कुमार की बहाली करने की सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि प्रबंधक सत्येंद्र कुमार एवं सदस्य अमरनाथ के साथ हुई वार्ता के बाद निलंबित प्रधानाचार्य अवधेश कुमार ने गुरुवार को कार्यभार संभाल लिया है। प्रबंधक सत्येंद्र कुमार और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार ने मिल जुलकर विद्यालय की व्यवस्था देखने को सहमत हुए। प्रबंधक सत्येंद्र कुमार ने प्रधानाचार्य अवधेश कुमार पर आराजकता करने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश प्रभारी कुलदीप दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. इन्द्र भूषण सिंह, डॉ. योगेश मिश्र, मुनि नाथ सचान, रमाकांत सचान, विनोद द्विवेदी एवं प्रधानार्चा वासुदेव तिवारी भी मौजूद रहे।

जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति: डीएम ने ली मासिक समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

लखीमपुर खीरी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की मासिक समीक्षा बैठक लीए संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निर्देश दिया कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान शिक्षा की गुणवत्ताए मिड.डे.मील सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। सभी बीईओ पंजीकृत छात्रों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ.साथ इस बात को भी सुनिश्चित करें कि सभी छात्र प्रापर ड्रेस, जूताए मोज़ा व स्वेटर पहन कर विद्यालयों में आयें।

डीएम ने बीएसए को निर्देशित किया कि शिक्षकों द्वारा शिक्षक संदर्शिका व शिक्षक डायरी का अनिवार्यता से दैनिक प्रयोग किया जाए। न्यून अधिगम स्तर वाले छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराए। समस्त शिक्षक.शिक्षिकाएं शिक्षक सन्दर्शिका के अनुरूप ही शिक्षण कार्य करें, जिससे छात्रों को निपुण बनाने में सहजता और शीघ्रता हो। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को सभी परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक .शिक्षक बैठक आयोजित की जाए। निर्देश दिए कि इन बैठकों में सुपरवाइजरी अफसरो की ड्यूटी भी लगाई जाए। इन बैठकों में अच्छी उपस्थिति वाले बच्चों के अभिवावको को सम्मानित किया जाए। कम अटेंडेंस वाले अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाए। 03 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने पर शिक्षक संबंधित बच्चों के घर पर विजिट करें।

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में माह के प्रथम दिन विद्यालय में नामांकित छात्रों में से उसे माह में जन्मे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाए। जन्मदिन वाले बच्चे के हाथो से अन्य साथी बच्चों को टाफ्यिा का वितरण कराया जाए।

साजिश रचकर पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप

फतेहपुर। एक माह पूर्व ललौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला पूर्वी कृष्णा नगर बहुआ में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भंडारा व कीर्तन के दौरान वाद यंत्र बजाते समय करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत के मामले में परिजनों ने साजिश रचकर उनके पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया तत्पश्चात एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से मुकदमा पंजीकृत करवाए जाने की गुहार लगाई है।

एसपी कार्यालय में ग्रामीणों संग खड़े मृतक के परिजन।

गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लिलरा गांव निवासी रामस्वरूप पुत्र देवीदीन ग्रामीणों संग गुरूवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। जहां उन्होने प्रदर्शन करते हुए एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें बताया कि उनका पुत्र विनय कुमार आरगन वाद यंत्र बजाने का कलाकार था। ललौली थाना क्षेत्र के लदिगवां गांव निवासी दीपू कुशवाहा भी आरगन वाद यंत्र बजाता है। 22 जुलाई को श्रावण मास के प्रथम सोमवार को जय भोले भंडारी कमेटी बहुआ के अध्यक्ष व संचालक मनीष शिवहरे पुत्र कामता शिवहरे ने ललौली थाने के मोहल्ला पूर्वी कृष्णा नगर बहुआ में भंडारे व कीर्तन का आयोजन किया था। जिसमें उनका पुत्र विनय कुमार वाद यंत्र बजाने गया था। वाद यंत्र बजाने वाला दीपू कुशवाहा उनके पुत्र से खुन्नस रखता था। दीपू कुशवाहा का बहनोई राम बाबू कुशवाहा निवासी कोरारी थाना ललौली लाइट व टेंट का काम करता है। भंडारे में रामबाबू कुशवाहा का टेंट व लाइट जनरेटर आदि लगा हुआ था। उनके पुत्र को आरगन वाद यंत्र बजाने के लिए दीपू व रामबाबू कुशवाहा की साजिश से अतुल यादव पुत्र ननकाई निवासी बावन थाना गाजीपुर घर से बुलाकर ले गए। स्टेज पर बैठाकर आरगन बजा रहा था तभी बिजली का कटा हुआ तार साजिशन डाल दिया। जिससे करंट की चपेट में आकर उनके पुत्र की मौत हो गई। सूचना ललौली थाने में भी दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से भगा दिया। वह लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

टीएसआई ने काटे चालीस वाहनों के चालान, मचा हड़कम्प

गुरसहायगंज (कन्नौज)। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी यातायात डा. प्रियंका बाजपेई एवं यातायात प्रभारी आआफाक खॉन के पर्यवेक्षण में टीएसआई अरशद अली द्वारा हाईवे के किनारे खतरनाक ढंग से खड़े ट्रकों के चालान किए गए। गुरूवार को टीएसआई अरशद अली द्वारा हाईवे के किनारे ढाबों के आसपास खड़े ट्रकों सहित रॉन्ग साइड में चलने वाले वाहनों के चालान किये जा रहे हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों एवं स्कूली वाहनों को भी यातायात पुलिस लगातार चेक कर रही है और चालकों को जागरुक भी किया जा रहा है। टीएसआई द्वारा करीब चालीस वाहनों के चालान काटे गए। उधर नगर में टीएसआई द्वारा 01 मोटर साइकिल व 02 थ्री व्हीलर को सीज कर कोतवाली में खडा कराया गया। टीएसआई द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम किया जाएगा क्योंकि रात्रि के समय वाहनों का दिखाई पड़ना बेहद जरूरी है।

वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाईजर मशीन से चेकिंग करते टीएसआई।

● स्कूली वाहनों को चेक कर बताये यातायात के नियम

जिले के नौ परीक्षा केन्द्रों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा

● पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में तैयारी पूरी

● एक शिफ्ट में 2800 के लगभग परीक्षार्थी होंगे शामिल

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा 9 अलग-अलग केंद्रों पर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिले। प्रत्येक दिन एक शिफ्ट में लगभग 2800 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बायोमेट्रिक जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना को खत्म किया जा सके।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए, जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास के सभी साइबर कैफे और फोटोकॉपी की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहेगा, जो केंद्रों पर निगरानी रखेगा और शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

आधार के सत्यापन को लेकर दो घंटे पहले पहुंचे

सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

इन सामग्रियों पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय-पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबिल, इलेक्ट्रानिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, मोबाइल, चाभी, कैमरा, घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैंड प्रतिबंध रहेगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को प्रसिद्ध जीव रसायन वैज्ञानिक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की इस साल शुरुआत की है। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडपम में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, 18 विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और एक विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किए। चंद्रयान-3 मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिशन के परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल ने प्राप्त किया। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया गया।

विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए वैज्ञानिकों में बेंगलुरू स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यमअ तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर्विषई विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आनंदरामकृष्णन सीअ भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में रसायन विज्ञान समूह के निदेशक आवेश कुमार त्यागीअ लखनऊ स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के जीवविज्ञानी उमेश वार्ष्णेय, पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवकर, आईआईटी दिल्ली के एमेरिटस प्रोफेसर भीम सिंह, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक संजय बिहारी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आदिमूर्ति आदि, आईआईएम कोलकाता के राहुल मुखर्जी को भी विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

इनके अलावा साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान के भौतिक विज्ञानी नबा कुमार मंडल और भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली के लक्ष्मणन मुथुस्वामी और प्रो. रोहित श्रीवास्तव

(प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष) को विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया।

विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर विवेक पोलशेट्टीवार और आईआईएसईआर-भोपाल के प्रोफेसर विशाल राय, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के कृष्णमूर्ति एस एल और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के स्वरूप कुमार परिदा को प्रदान किया गया। आईआईएसईआर-भोपाल की प्रोफेसर राधाकृष्णन महालक्ष्मी, सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर के अभिलाषअ आईआईटी-मद्रास के राधा कृष्णअ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूरबी सैकियाअ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के बप्पी पॉल विज्ञान युवा पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल थे। इनके अलावा पुणे स्थित आईसीएमआर- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की प्रज्ञा ध्रुव यादव, चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार साहूअ आईआईएससी, बेंगलुरु के महेश रमेश काकड़े विज्ञान युवा पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल थे। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु की उर्वशी सिन्हा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम के दिगेंद्रनाथ स्वैन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद के प्रशांत कुमार और आईआईटी-मद्रास के प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल को भी विज्ञान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रशिक्षु पायलट व प्रशिक्षक का शव मिला, विमान की तलाश जारी

भाषा। जमशेदपुर

झारखंड के जमशेदपुर स्थित हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हुए दो सीट वाले विमान में सवार प्रशिक्षु पायलट और प्रशिक्षण देने वाले पायलट का शव बृहस्पतिवार को चांडिल बांध में पाया गया जबकि विमान की तलाश जारी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एक निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान अलकेमिस्ट एविएशन का विमान सेसना 152 मंगलवार सुबह सोनारी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था, जिसके बाद बांध के जलाशय सहित आस-पास के इलाकों में इसका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर खोजबीन अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि विमान के चांडिल बांध के आस-पास दुर्घटनाग्रस्त होने का संदेह था।

अधिकारियों ने कहा कि आदित्यपुर निवासी प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव सुबह मिला, जबकि पटना निवासी पायलट कैप्टन जीत शत्रु आनंद का शव बाद में मिला। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम से आई नौसेना की 19 सदस्ईय टीम लापता विमान की तलाश में लगातार जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी), उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय (डीएफटी) और उड़ान योग्यता निदेशालय (डीएडब्ल्यू) के साथ घटना की जांच शुरू कर दी है।

वीटी-टीएजे के रूप में पंजीकृत विमान का स्वामित्व और संचालन करने वाली अल्केमिस्ट एविएशन ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों के बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। इसने कहा, विमान में 80 लीटर ईंधन था और यह साढ़े चार घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम था तथा उड़ान का समय एक घंटा निर्धारित था। बयान में कहा गया कि मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11.10 बजे विमान का संपर्क जमशेदपुर हवाई नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से टूट गया। अल्केमिस्ट एविएशन ने कहा कि विमान डीजीसीए द्वारा जारी उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उड़ान योग्य स्थिति में था और इसमें मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निर्मित इंजन लगाया गया था। बयान में कहा गया कि अमेरिकी कंपनी लाइककिंग इंजन के इंजन से युक्त इस विमान का संचालन काल 30,000 घंटे का होता है, जिसमें से इसने केवल 16,000 घंटे पूरे किए थे। इसमें कहा गया कि बांध में एक जोड़ी जूते तैरते पाए गए जिसके बाद उन्हें बरामद करके पहचान की गई।

कंपनी ने कहा, इससे हमें यह आशंका हुई कि घटनास्थल बांध ही होगा। प्रारंभिक खोज टाटा स्टील के हेलीकॉप्टर और हमारे अपने विमान द्वारा की गई। इसके बाद मौसम खराब हो गया और खोजबीन अभियान जमीन पर वाहनों के जरिए चलाया गया तथा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद स्थानीय सरकारी अधिकारियों को सूचित किया गया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की मदद से बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना को मदद के लिए बुलाया गया और उसने एक सोनिक नेविगेशन एंड रेंजिंग (सोनार) उपकरण तैनात किया जो घटना की सटीक स्थिति को चिह्नित करने में सहायता करेगा।

एकनाथ खडसे ही भाजपा में वापसी के बारे में बता सकतेः मंत्री रक्षा खडसे

मुंबई। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने बृहस्पतिवार को कहा कि केवल उनके ससुर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) एकनाथ खडसे ही भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल होने की अपनी योजना का खुलासा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे एकनाथ खडसे को 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। खडसे ने 2020 में पार्टी छोड़ दी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (अविभाजित) में शामिल हो गए। खडसे ने इस साल अप्रैल में राकांपा के विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था और ऐसी अटकलें थीं कि वह फिर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। अपने ससुर की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने संवाददाताओं से कहा, केवल नाथाभाऊ (एकनाथ खडसे इसी नाम से लोकप्रिय हैं) ही भाजपा में वापसी के समय के बारे में बता सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमुख नेता एकनाथ खडसे को महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है और विधाई प्रक्रियाओं में उनकी कुशलता के लिए अक्सर उनकी सराहना की जाती है।

पायलट बाबा को दी गई भूसमाधि

भाषा। हरिद्वार

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमनाथ गिरि उर्फ पायलट बाबा को बृहस्पतिवार को यहां उनके कनखल आश्रम में भूसमाधि दे दी गई। पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां बड़ी संख्या संतों के अलावा देश-विदेश से उनके अनुयाई आए थे। पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने भी आश्रम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान, साधु-संतों के सभी 13 अखाडों के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर, श्रीमहंत, महंत, विभिन्न दलों के नेता, देश के बड़े उद्योगपति और कारोबारी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि महाराज की देखरेख में पायलट बाबा को अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाह्न 11 बजकर 55 मिनट पर भूसमाधि दी गई। पायलट बाबा की शिष्या महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरि व साध्वी श्रद्धा गिरि ने उन्हें समाधि दी। पायलट बाबा की जापानी शिष्या योगमाता केको आइकवा भी इस दौरान मौजूद रहीं।

श्री महंत हरी गिरि महाराज ने पायलट बाबा को सिद्ध संत बताते हुए कहा कि वह समाज, देश व धर्म की सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने बताया कि संन्यासी बनने से पूर्व पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उन्होंने 1962, 1965 व 1971 के युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि बाद में युद्ध की विभीषिका से आहत पायलट बाबा ने 1974 में संन्यास ले लिया और विधिवत दीक्षा लेकर जूना अखाड़े में शामिल हो गए।

पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के रूप में उन्होंने जहां देश सेवा की मिसाल कायम की, वहीं एक सच्चे व सिद्ध संत के रूप में उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि पायलट बाबा ने जीवित रहते हुए कई बार जल समाधि, एयर टाइट ग्लास रूम में कई दिन तक योग साधना के बल पर दुनिया को सनातन और योग शक्ति से रूबरू कराया था।

अखाडा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने भी पायलट बाबा को उच्च कोटि का योगी बताते हुए कहा कि उनके देहावसान से सनातन की अपूरणीय क्षति हुई है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर पायलट बाबा मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में ब्रहमलीन हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को यहां कनखल स्थित उनके आश्रम लाया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

महाराष्ट्र सरकार बंबई उच्च न्यायालय की इमारत के लिए भूमि सात सितंबर तक उपलब्ध कराए : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सात सितंबर तक एक आदेश जारी करके बंबई उच्च न्यायालय को नई इमारत के निर्माण के लिए बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमि उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक इमारत और उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन शीर्षक वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की भवन परियोजना को महत्वपूर्ण घोषित करने के लिए एक और आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया। इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण परियोजना प्रभावित नहीं हो। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की विशेष पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुंबई की एक इमारत के कुछ हिस्से का कब्जा सौंपने के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा ताकि वहां उच्च न्यायालय की कुछ सुविधाओं को स्थानांतरित किया जा सके। अदालती कार्यवाही की शुरुआत में पीठ ने मामले में अब तक हुई प्रगति के बारे में पूछा। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और राज्य सरकार उच्च न्यायालय को जमीन का कब्जा सौंपने के लिए कदम उठा रही है।

कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमे की अनुमति पर फैसले के लिए राज्यपाल को सलाह देंगेः कर्नाटक मंत्रिमंडल

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने जनता दल (सेक्युलर) नेता एवं केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तथा खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी सहित भाजपा के तीन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सहायता और सलाह देने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। कांग्रेस सरकार ने यह कदम मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले में 16 अगस्त को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर उठाया है। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, लंबित मामलों में जल्द से जल्द निर्णय लेने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दे सकता है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने को अपनी मंजूरी दी है। पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, सलाह राज्यपाल को भेजी जाएगी। जिन चार लंबित मामलों में हमने सहायता और सलाह दी है, इनमें से दो मामलों (जनार्दन रेड्डी और कुमारस्वामी) में आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं...। पाटिल से जब यह पूछा गया कि क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं, उन्होंने कहा, हमारे अनुसार, वह हमारी सलाह मानने को बाध्य हैंअ उनका विवेकाधिकार सीमित है। मुझे यकीन है कि वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। राज्यपाल ने 16 अगस्त को सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधि., 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत एस पी प्रदीप कुमार, टी जे अब्राहम और स्नेहमई कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। पाटिल ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी मांगने वाली कई अर्जी राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाएं भी शामिल हैं इनमें से कुछ मामलों में आरोप-पत्र भी दायर किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि इन अर्जियों में से विशेष अर्जी पूर्व मंत्री शशिकला जोले के विरुद्ध हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने नौ दिसंबर, 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। (भाजपा के पूर्व मंत्री) मुरुगेश निरानी के खिलाफ इसी कानून की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए 26 फरवरी, 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तीसरी अर्जी कुमारस्वामी मामले को लेकर है, जिनके खिलाफ 21 नवंबर 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अर्जी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत मंजूरी मांगी गई है। पाटिल ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है और राज्यपाल ने 29 जुलाई, 2024 को मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसपर इसने (एसआईटी ने) 16 अगस्त, 2024 को आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया है। चौथा मामला रेड्डी से संबंधित है, जिनके खिलाफ 13 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 और बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत मंजूरी मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जांच एजेंसियों ने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्वाई नहीं की गई है। जनता की नजर में राज्यपाल का कार्यालय गलत काम करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमें लगा कि यह सहायता और सलाह देना उचित है। सिद्धरमैया के मामले में एक निजी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि इन चार मामलों में जांच हो चुकी है और दो मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

श्याम रजक ने राजद से इस्तीफा दिया

पटना। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने बृहस्पतिवार को राजद से इस्तीफा देते हुए धोखा दिए जाने का आरोप लगाया। रजक ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को संबोधित एक संक्षिप्त पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ-साथ दल की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहे हैं। रजक ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद को संबोधित अपने पत्र में लिखा है, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।

कांग्रेस ने केरल सरकार से हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने को कहा

तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। कांग्रेस ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर हेमा समिति की रिपोर्ट के संबंध में बृहस्पतिवार को केरल सरकार से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष के. सुधाकरन ने संवाददाताओं से कहा कि अगर 2026 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुधाकरन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि समिति की जिस रिपोर्ट में महिलाओं और यहां तक कि नाबालिग लड़कियों के साथ विभिन्न अत्याचारों के संबंध में गंभीर जानकारी दी गई है उसे वर्षों तक रोक कर रखा गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को इतने लंबे समय तक लटकाए रखने का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सुधाकरन ने कहा, कांग्रेस हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्वाई की मांग करती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने दावा किया कि न्यायमूर्ति हेमा ने राज्य सरकार से रिपोर्ट जारी न करने के लिए कभी नहीं कहा। सतीशन ने उनके द्वारा पहले भी लगाए गए आरोपों को दोहराया और सरकार पर शिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

सतीशन ने कोच्चि में संवाददाताओं से कहा, हेमा समिति ने सरकार से रिपोर्ट जारी न करने को कभी नहीं कहा, बल्कि उसने इसे जारी कर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों के नामों का खुलासा न करने का निर्देश दिया है और उसका निर्देश रिपोर्ट पर कार्वाई करने के खिलाफ नहीं है। सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रुख स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई शिकायत देता है तो मामला दर्ज किया जा सकता है।

सतीशन ने कहा, प्रस्तावित सिनेमा सम्मेलन में आरोपी भी पीड़िताओं के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिनेमा सम्मेलन नारीत्व का अपमान होगा। सतीशन ने राज्य सरकार द्वारा फिल्म उद्योग के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय सिनेमा सम्मेलन का जिक्र करते हुए यह बात कही। विपक्षी कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस दावे को बुधवार को नकार दिया कि न्यायमूर्ति हेमा ने खुद उनसे मलयालम फिल्म उद्योग पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया था। यूडीएफ ने इसे सरासर झूठ और पाखंड बताया। राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि (हेमा) समिति ने बयान दर्ज करने और रिपोर्ट सौंपते समय सभी कानूनी पहलुओं पर गौर किया होगा।

बायजू मामले में सीओसी को बैठक न करने का अंतरिम आदेश देने से न्यायालय का इनकार

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय संकट से घिरी शिक्षा-प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही जारी रखने के लिए कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को कोई बैठक नहीं आयोजित करने का अंतरिम आदेश देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह 27 अगस्त को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक होने वाले घटनाक्रमों को वह नकार सकती है अगर उसे यह लगता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ अमेरिका की कर्जदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी की तरफ से दायर अपील में कोई दम नहीं है।

बायजू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक दिन पहले सीओसी का गठन कर दिया गया है और 98 प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी के पास है।

बायजू का संचालन करने वाली मूल कंपनी थिंक एंड लर्न को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें एड-टेक प्रमुख के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को अलग रखा गया था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ 158.9 करोड़ रुपए के बकाया निपटान को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले दो अगस्त का अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया था क्योंकि इसने प्रभावी रूप से संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रण में ला दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी के फैसले को प्रथम दृष्टया अनुचित करार देते हुए रोक लगा दी थी।

यह मामला बीसीसीआई के साथ एक प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपए के भुगतान में बायजू की चूक से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को निर्देश दिया था कि वह बायजू से समझौते के बाद प्राप्त 158 करोड़ रुपए की राशि को अगले आदेश तक एक अलग एस्क्रो खाते में रखे। बायजू ने 2019 में बीसीसीआई के साथ टीम प्रायोजक समझौता किया था। कंपनी ने 2022 के मध्य तक अपने दायित्वों को पूरा किया, लेकिन 158.9 करोड़ रुपए के बाद के भुगतानों में चूक कर गई।

पेज 1 का शेष

एफआईआर...

तब तक सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने कहा कि घटना में पहली एफआईआर रात 11.45 बजे पीड़िता के दाह संस्कार के बाद ही दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, शुरुआत में, अधिकारियों ने माता-पिता को बताया कि यह आत्महत्या थी, लेकिन बाद में इसे मौत की श्रेणी में रखा गया। पीठ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की भूमिका पर भी पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की, जो इस भयानक अपराध के बाद संदेह के घेरे में आ गए हैं। दोपहर के भोजन के बाद जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अदालत ने पूछा कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के संपर्क में कौन था? उन्होंने देरी क्यों की एफआईआर में उद्देश्य क्या था? पीठ ने टिप्पणी की, प्रक्रिया एक अलग मसला है, लेकिन मुद्दा अभी भी बना हुआ है। शव मिलने के लगभग 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आना चाहिए था और निर्देश देना चाहिए था। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा, जिस क्षण प्रिंसिपल इस्तीफा देता है, उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। सुनवाई के दौरान, रिकॉर्ड देखने के बाद, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा, कुछ बहुत परेशान करने वाला है। अप्राकृतिक मौत के संबंध में जीडी प्रविष्टि सुबह 10.10 बजे दर्ज की गई है। इसलिए पुलिस स्टेशन है सूचित किया गया कि अप्राकृतिक मौत हुई है। इस सब के बावजूद, अपराध स्थल की सुरक्षा, जब्ती आदि रात के 11.30 बजे होती है? सिब्बल ने दावा किया कि यह गलत जानकारी थी और दावा किया कि सभी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई थी। शुरुआत में मेहता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपराध के पांचवें दिन जांच शुरू की। हमने पांचवें दिन जांच शुरू की। इससे पहले, स्थानीय पुलिस ने जो कुछ भी एकत्र किया था वह हमें दे दिया गया था। जांच अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि अपराध स्थल बदल दिया गया था। (पीड़िता के) दाह संस्कार के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी रात 11.45 बजे। मेहता ने कहा, पहले, पीड़िता के माता-पिता को (अस्पताल के) उपाधीक्षक ने सूचित किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वे अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है... सौभाग्य से, उसके सहकर्मी खुश थे मृतक ने वीडियोग्राफी के लिए जोर दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें मामले को छिपाने का संदेह था। सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि हर चीज की वीडियोग्राफी की गई थी और दावा किया कि अपराध स्थल पर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया था। उन्होंने दलील दी कि कोलकाता पुलिस ने प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया और सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट केवल मामला खराब करने का प्रयास करती है।

सुप्रीम कोर्ट...

करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हैं। रोगी की देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के संघ ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और उनकी मांगों को संबोधित करने में हुई प्रगति को देखते हुए, वे शुक्रवार आठ बजे सुबह से अपना काम फिर से शुरू करेंगे।

अलकायदा...

गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस उपायुक्त (पब्लिक रिलेशन ऑफिस) सुमन नलवा ने कहा, संचालन की वर्तमान स्थिति के अनुसार, मॉड्यूल का नेतृत्व रांची (झारखंड) के एक डॉ. इश्तियाक द्वारा किया जा रहा था, और यह खिलाफत घोषित करने और देश के भीतर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इच्छुक था। अल कायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को चरमपंथी विचारधाराओं से प्रेरित किया गया था और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। मॉड्यूल के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर सिद्धांत और हथियार प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। छह लोगों को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया गया, जब वे हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे, और आठ लोगों को पूछताछ के लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के जंगलों सहित विभिन्न स्थानों पर हथियार चलाने सहित प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने कहा कि संदिग्धों को पकड़ने के लिए पहाड़ी के जंगलों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से तीन और लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल विभिन्न स्थानों पर पूछताछ चल रही है और ऑपरेशन जारी रहने के कारण मामले में अतिरिक्त गिरफ्तारियों की भी उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि हथियार, गोला-बारूद और साहित्य बरामद करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। बयान में कहा गया, इसके अलावा, अब तक रांची में 15, राजस्थान में एक और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में एक जगह पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि संदेह है कि मॉड्यूल आगामी त्योहारी सीजन के दौरान भारत के उत्तरी हिस्से में एक आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अल कायदा मॉड्यूल पिछले कुछ महीनों से सक्रिय है और इसके सदस्य सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि स्पेशल सेल ने 15 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था और तब से, आतंकवाद विरोधी इकाई संदिग्धों का विवरण एकत्र कर रही थी।

जम्मू-कश्मीर....

दिया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर बोलते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 'हमारे स्थानीय नेताओं' के फीडबैक के आधार पर गठबंधन बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, हम पूरे विपक्ष को साथ रखना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस राज्य की वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित नहीं कर सकती। एआईसीसी प्रमुख ने कहा, पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर दबाव में चुनाव की घोषणा की। मैं यह रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि भाजपा अब जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाज को दबा नहीं सकती है। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर के बारे में खड़गे ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है।

असम...

सरमा ने कहा कि असम सरकार मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए चल रहे शरद ऋतु सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। यहां कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि सरकार असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश करेगी। पिछले महीने, कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के नियमों को खत्म करने के लिए निरसन विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जो विशिष्ट शर्तों के तहत कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में बाल विवाह के सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी। विपक्षी दलों ने इस फैसले की निंदा की थी और इसे चुनावी वर्ष में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया 'मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण' बताया था।

दिल्ली में...

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि चालकों को धमकाया जा रहा है। उनका संघ हड़ताल का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, कई चालक हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप के बाहर चालकों को धमकाया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि पुलिस इन जगहों के बाहर निगरानी बढ़ाए।

वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक

सदस्यों ने कई प्रावधानों पर उठाए सवाल

भाषा। नई दिल्ली

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून के कई प्रावधानों पर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों के बीच बृहस्पतिवार को पहली मैराथन बैठक की। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से एक प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान कई बार तीखी बहस हुई लेकिन विभिन्न दलों के सदस्यों ने कई घंटे तक बैठकर विधेयक के प्रावधानों पर अपने विचार दर्ज कराए, सुझाव दिए और स्पष्टीकरण मांगा। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के ए. राजा के साथ कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने जिलाधिकारी को और अधिकार देने और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखने सहित कई प्रावधानों की आवश्यकता पर सवाल उठाए।

कुछ सदस्यों ने कहा कि मंत्रालय बैठक में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं दिखा। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इसकी अगली बैठक 30 अगस्त को होगी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि समिति विभिन्न मुस्लिम निकायों सहित सभी हितधारकों से बात करेगी। संसद ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्ईय समिति को विवादास्पद विधेयक की जांच करने का काम सौंपा है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों पर समिति को जानकारी देंगे। पाल ने बैठक से पहले कहा कि समिति विधेयक पर विस्तार से चर्चा करेगी और इससे जुड़ी चिंताओं पर भी विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न हितधारकों की आवाज सुनेगी। उन्होंने कहा, हम सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेंगे और अगले सत्र तक एक अच्छा और व्यापक विधेयक लाएंगे। पाल ने कहा कि समिति विभिन्न पंथों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न मुस्लिम संगठनों को बुलाएगी ताकि उनके विचार सुने जा सकें। यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार की पहली बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना है। यह कई सुधारों का प्रस्ताव करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्डों समेत एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना शामिल है। विधेयक का एक विवादास्पद प्रावधान, जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है कि क्या संपत्ति को वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विधेयक को आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और बहस के बाद संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। सरकार ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित कानून मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखता है जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया कदम और संविधान पर हमला बताया।

पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा- नीतीश और नायडू ने हमें वक्फ विधेयक का विरोध करने का यकीन दिलाया

नई दिल्ली। (भाषा) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है जिसमें दोनों नेताओं ने यकीन दिलाया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। रहमानी ने कुछ शीर्ष मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रमुख घटक हैं। रहमानी ने यह भी कहा कि केंद्र को यह विधेयक वापस लेना चाहिए और अगर यह विधेयक संसद में पारित करने के लिए पेश किया गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा तथा कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्एक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस संवाददाता सम्मेलन में रहमानी के अतिरिक्त जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सआदतुल्ला हुसैनी, मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्रमुख मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी और पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास मौजूद थे। यह पूछे जाने पर कि क्या जद(यू) और तेदेपा के नेताओं से भी मुलाकात हुई है और उनका क्या रुख है, तो रहमानी ने कहा, हम लोगों की मुलाकातें अलग-अलग विपक्षी दलों के नेताओं से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह इस विधेयक का विरोध करेंगे। कल (बुधवार को) नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वह इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव (राजद नेता) से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वह इसका विरोध करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वक्फ पर सरकार को हाथ नहीं रखने दिया जाएगा। उनका कहना था कि कई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और राजग के सहयोगी दलों ने भी विधेयक का विरोध करने का विश्वास दिलाया है। नीतीश और नायडू से मुलाकात के विवरण के बारे में पूछे जाने पर रहमानी ने कहा, हम इस बारे में विस्तार से नहीं बता सकते। हम उनसे मिल चुके हैं। ए कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ए न्याय और अन्याय का मसला है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा के सहयोगियों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दल न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मद्देनजर हमारा समर्थन करें। मुस्लिम संगठनों ने उस दिन संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिस दिन वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई। जमीयत प्रमुख अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि मसला सिर्फ वक्फ का नहीं, बल्कि मसला यह है कि हिंदुस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों को जो आजादी दी गई है, मौजूदा सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है।

लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य : बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई। (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य है।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मानव तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) से भी जवाब मांगा तथा इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) से सुझाव आमंत्रित किए। सांगली निवासी शाहजी जगताप की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य पुलिस को 2019 और 2021 के बीच महाराष्ट्र में लापता हुईं एक लाख से अधिक महिलाओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही निष्क्रियता पर चिंता जताई गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मंजरी पारसनीस ने बृहस्पतिवार को अदालत को सूचित किया कि जगताप की अपनी बेटी लापता है। अधिवक्ता ने बताया कि बेटी की तलाश के दौरान उनके मुवक्किल को 14 मार्च, 2023 को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े मिलेअ जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में लापता बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। मंत्रालय के मुताबिक, 2019, 2020 और 2021 में, लापता बच्चों की संख्या क्रमश: 4,562, 3,356 और 4,129 थी। इसी तरह, इन तीन वर्षों में महाराष्ट्र में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लापता होने के एक लाख से अधिक मामले सामने आए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों और महिलाओं के लापता होने के कई कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा, लेकिन उनका पता लगाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित आश्रय देना राज्य का कर्तव्य है। लापता बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण संभवत: मानव तस्करी का खतरा है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों, पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की है।

खाद्य सुरक्षा नियामक का दूध, दही से ए-वन, ए-टू के दावों को हटाने का आदेश

नई दिल्ली। (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से ए-वन और ए-टू प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया। नियामक ने इस तरह के लेबल को भ्रामक बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि ए दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं। अपने ताजा आदेश में, एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-केसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। हालांकि, मौजूदा एफएसएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। खाद्य व्यवसाय परिचालकों का जिक्र करते हुए नियामक ने कहा, एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है। ई-कॉमर्स मंच को भी उत्पादों और वेबसाइट से इन दावों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया। कंपनियों को पहले से मुद्रित लेबल समाप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, इसके अलावा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ए-1 और ए-2 दूध में बीटा-कैसीन प्रोटीन की संरचना अलग-अलग होती है, जो गाय की नस्ल के आधार पर अलग-अलग होती है। नियामक ने इस निर्देश का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। आदेश का स्वागत करते हुए पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि एफएसएसएआई का आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने एक बयान में कहा, ए-1 और ए-2 विपणन मकसद से विकसित की गई श्रेणी है। ...यह जरूरी है कि हम भ्रामक दावों को खत्म करें जो उपभोक्ताओं को गलत जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ए-1 या ए-2 दूध उत्पाद श्रेणी कभी अस्तित्व में नहीं थी और वैश्विक स्तर पर भी यह प्रवृत्ति खत्म हो रही है और उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई का स्पष्टीकरण इस व्यापक समझ का समर्थन करता है।

बलात्कार के मामलों में 50 दिनों के भीतर सजा दिलाने वाले कानून की जरूरत: अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने यौन उत्पीड़न के मामलों में 50 दिनों के भीतर दोषसिद्धि अनिवार्य करने वाले कानून की वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही देश में ऐसे 900 से अधिक मामले हुए हैं।

बनर्जी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालें, जिससे इन मामलों में त्वरित सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ पिछले 10 दिनों में जब लोग सड़कों पर प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की 900 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा, देश में हर दिन बलात्कार की 90 घटनाएं, प्रति घंटे ऐसी चार तथा प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना सामने आती है इसलिए इन मामलों में निर्णायक कार्वाई की जरुरत है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की जरूरत है जो 50 दिनों के भीतर सुनवाई और दोषसिद्धि कर सकें और उसके बाद कठोर सजा दे सकें, न कि केवल खोखले वादे करें। राज्य सरकारों को कार्वाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए जो त्वरित सुनवाई कर सके और सख्त सजा दे सके।

जनगणना प्रश्नावली में कॉलम जोड़कर ओबीसी का जातिवार आंकड़ा एकत्र करें

नई दिल्ली। (भाषा) कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग एक बार फिर उठाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जनगणना की प्रश्नावली में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा होने से जाति जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मजबूत आधार मिलेगा।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत में हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना होती रही है। पिछली जनगणना 2021 में होनी थी और 2021 की जनगणना न होने का मतलब है कि आर्थिक योजना और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 12 करोड़ से ज़ूयादा भारतीयों को उनका कानूनी हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, अब ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में लंबे समय से लंबित और अस्वीकार्य रूप से विलंबित इस जनगणना को करवा सकती है। रमेश ने कहा, 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बारे में जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जाता रहा है। बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर जनगणना की प्रश्नावली में ओबीसी आबादी के बारे में भी जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से जाति संबंधी जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मजबूत आधार मिलेगा। रमेश ने कहा कि जनगणना संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है और यह केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है जिसका अर्थ है कि जनगणना कराना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

गाय को बचाने के लिए बांध में कूदा किसान, एसडीईआरएफ के दो जवान डूबे

भिंड (मप्र)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गाय को बचाने के लिए बांध में कूदा किसान और बचाव अभियान के लिए तैनात राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) के दो जवानों की डूबने से मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी।पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि बुधवार शाम कुंवारी नदी पर बने बांध के स्लुइस गेट में एक गाय फंस गई, जिसके बाद उसका मालिक विजय सिंह और उनका चचेरा भाई दिनेश भदौरिया जलाशय में कूद गए। यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर हुई। दिनेश सिंह तेज बहाव में बह गया। कचोंगरा गांव के निवासियों ने रस्सियों की मदद से विजय को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, दिनेश को नदी के बीच में झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने उसे बचाने के लिए राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) की मदद मांगी। जीवन रक्षक जैकेट पहने एसडीईआरएफ की तीन सदस्ईय टीम नदी में उतरी, लेकिन उनकी नाव पलट गई, जिससे वे तेज बहाव में गिर गए।उन्होंने कहा कि एसडीईआरएफ के जवान प्रवीण कुशवाह और हरदास चौहान की जीवन रक्षक जैकेट तेज बहाव में फट गई, जबकि तीसरा जवान तैरकर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। अधिकारी ने कहा कि 100 से अधिक जवानों को तैनात करने के बाद आज शाम कुशवाह और चौहान के शव बरामद किए गए। यादव ने एसडीईआरएफ के एक जवान से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि दिनेश और गाय को बुधवार को बचा लिया गया था। बुधवार रात को अंधेरे के कारण लापता दो जवानों को खोजने का अभियान रोक दिया गया था और बृहस्पतिवार सुबह इसे फिर से शुरू किया गया।

भोजपुर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

आरा (बिहार)। बिहार के भोजपुर जिले में आरा-बक्सर राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को एक जीप के डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। भोजपुर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह गजराजगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर बीबीगंज पुल के पास उक्त वाहन डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान भूप नारायण पाठक (56), बिपुल पाठक (26), रेनू देवी (55), अर्पिता पाठक (25) और सिटी कुमार उर्फ हर्ष कुमार (3) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायलों में खुशी कुमारी (22), मधु देवी (27) और बेली कुमारी (पांच) शामिल हैं। पुलिस ने घायलों को भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज जारी है। बयान के अनुसार इस हादसे में हताहत हुए लोग भोजपुर जिले के अजीमाबाद थानाक्षेत्र के कमरिया गांव के निवासी थे और फिलहाल पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र की अर्पण बैंक कॉलोनी में रह रहे थे।

बैंक खाते और आय का ब्योरा नहीं देने पर गुजारा भत्ते के लिए महिला का दावा खारिज

इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय ने 28 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति से गुजारा भत्ता हासिल करने का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उसने अपने बैंक खाते और आय का स्पष्ट ब्योरा अदालत में पेश नहीं किया। बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ अदालत में दावा दायर किया था। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन पी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के एक फैसले की रोशनी में यह दावा खारिज कर दिया। अदालत ने प्रकरण के तथ्यों पर गौर के बाद अपने आदेश में कहा कि चूंकि महिला ने अपने हलफनामे में उसके बैंकिंग लेन-देन से जुड़े किसी खाते का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए लगता है कि वह कोई न कोई काम करके आमदनी हासिल कर रही है। कुटुम्ब न्यायालय ने कहा, प्रार्थी (महिला) आमदनी तो अर्जित कर रही है, लेकिन वह कितनी आमदनी अर्जित कर रही है, उसने इसका खुलासा नहीं किया है। इसलिए यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि दम्पति की नाबालिग संतान की परवरिश के लिए वह और प्रतिप्रार्थी (महिला का पति) कितनी राशि वहन करेंगे।

शरद पवार ने एमपीएससी परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का समर्थन किया

पुणे।(भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर पुणे में आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों का समर्थन किया है। पवार ने चेतावनी भी दी है कि यदि राज्य सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो वह इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 अगस्त को होगी। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी मंगलवार रात से ही परीक्षा की अलग तिथि तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन एक बैंकिंग परीक्षा भी है।राकांपा (एसपी) के विधायक रोहित पवार भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के साथ बैठ गए। राकांपा (एसपी) के प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुधवार रात एक पोस्ट में कहा, एमपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों के हितों पर विचार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है... हालांकि, ऐसा लगता है कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। यदि कल (बृहस्पतिवार) तक सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो मैं आंदोलन स्थल पर जाऊंगा और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा। प्रदर्शनकारियों

की यह भी मांग है कि एमपीएससी परीक्षा के माध्यम से ही कृषि विभाग के 258 पदों पर नियुक्तियां की जाएं। एमपीएससी के एक अभ्यर्थी ने कहा कि वे चाहते हैं कि कृषि विभाग के 258 पदों को एमपीएससी परीक्षा के दायरे में लाया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने कहा, चूंकि 25 अगस्त को निर्धारित एमपीएससी परीक्षा के साथ-साथ उसी दिन लिपिक पदों के लिए भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन (आईबीपीएस) परीक्षा भी है इसलिए एमपीएससी परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए क्योंकि कई छात्रों ने दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है।

अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहा से बात की बाढ़ स्थिति का जायजा लिया

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से फोन पर बात करके राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के दलों के साथ-साथ नौकाएं और हेलीकॉप्टर भी राज्य में भेज रही है।उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया,"त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डा. माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम के अलावा नौका और हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है" मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता का आश्वासन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारे बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। रविवार से त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। भारी बारिश के कारण 32,000 से अधिक लोगों ने 330 राहत शिविरों में शरण ली है।

हमें अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता : प्रह्लाद जोशी

बेंगलुरु।(भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत प्रतिभा, जनशक्ति और क्षमता से भरपूर है, इसलिए हमें आगे बढ़ने तथा देश में और अधिक विनिर्माण करने की आवश्यकता है।

जोशी यहां राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखने के लिए बेंगलुरू में थे।नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जोशी ने कार्यक्रम में कहा, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपनी प्रणाली, अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। इस दिशा में, मेरे गृह राज्य में पहली ईवी बैटरी परीक्षण सुविधा खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रत्एक निर्णय आपस में जुड़ा हुआ है और यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।जोशी ने कहा, उदाहरण के लिए, हमारी योजना 2030 तक भारतीय सड़कों पर 30 प्रतिशत ईवी वाहन लाने की है। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि ईवी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली नवीकरणीय हो, इसलिए हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक करोड़

घरों में नि:शुल्क सौर ऊर्जा इकाई लगाने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच मिल सके। उन्होंने एनटीएच से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके तथा ईवी परीक्षण जैसी अधिक सुविधाएं स्थापित करके अपनी परीक्षण क्षमता में विविधता लाने का भी आग्रह किया। एनटीएच विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में अग्रणी रहा है। यह उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। एनटीएच को पहले ही भारत में सेंट्रल विस्टा और मेट्रो रेल जैसी कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं मिल चुकी हैं।

यूक्रेन में शांति के लिए भारत सहयोग को तैयार : मोदी

पीएम ने जेलेंस्की से वार्ता से पहले कहा

भाषा। वारसॉ

युद्धग्रस्त यूक्रेन की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत का दृढ़ता से मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता और यह (भारत) क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद यह बात कही। बैठक में, दोनों नेताओं ने भारत-पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उन्होंने कौशल प्राप्त श्रमिकों की दोनों देशों के बीच आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौता पर भी हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किए जाने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि सभी देशों को किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या उसे खतरे में डालने से बचना चाहिए। मोदी ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, भारत का दृढ़ता से मानना है कि युद्ध के मैदान में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी संकट में निर्दोष लोगों की जान जाना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा, हम शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल कराने के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है। वारसॉ की अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद, मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा करेंगे और इस यात्रा में उन्हें लगभग 10 घंटे लगेंगे।

प्रधानमंत्री ने वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

वारसॉ। पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी बुधवार को यहां पहुंचे। यह 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार को लगभग सात घंटे यूक्रेन में रहेंगे। पोलिश भाषा में एक्स पर किए गए एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पचक्र अर्पित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें भी साझा कीं। विदेश मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें संलग्न करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की स्मृति को नमन किया।

पूर्वी थाईलैंड में छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी नौ लोगों के मारे जाने की आशंका

भाषा। बैंकॉक

थाईलैंड के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक घरेलू उड़ान का एक छोटा यात्री विमान बृहस्पतिवार दोपहर राजधानी बैंकॉक के मुख्य हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि विमान में सवार सभी नौ लोग मारे गए हैं। बचावकर्मियों को हवाई अड्डे से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) दूर चाचोएंगसाओ प्रांत में मैंग्रोव दलदल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिला, जहां पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। मीडिया के मुताबिक, विमान में सात यात्री और दो पायलट सवार थे। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लगभग एक घंटे की खोज के बाद बचावकर्मियों को दुर्गम दलदली इलाके में बुरी तरह क्षत-विक्षत शव मिले। विमान में सवार लोगों की पहचान तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी। विमान में सवार लोगों में हांगकांग के पांच चीनी पर्यटक, दो थाई महिला चालक दल के सदस्य और थाई पायलट और सह-पायलट शामिल थे। हादसे के कारणों का अबतक पता नहीं चल पाया है। थाईलैंड के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि थाई फ्लाइंग सर्विस कंपनी द्वारा संचालित ट्वीनप्रॉप विमान सेसना कारवां सी208बी ने अपराह्न स्थानीय समयानुसार 2:46 बजे बैंकॉक के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

दक्षिण कोरिया में एक होटल में आग से सात लोगों की मौत, 12 घायल

सियोल। दक्षिण कोरिया के शहर बुकेओन में एक होटल में आग लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुकेओन के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक किम इन-जे ने कहा कि घायल हुए पीड़ितों में से तीन की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि घायलों का इलाज नजदीक के छह अस्पतालों में किया जा रहा है। बुकेओन के अग्निशमन केंद्र के एक अधिकारी ली सांग-डॉन ने कहा कि बृहस्पतिवार शाम को जब आग लगी तो नौ मंजिला होटल में 23 मेहमान ठहरे हुए थे। यह अभी नहीं पता चल सका है कि आग किस वजह से लगी। ली ने कहा कि आठवीं मंजिल से फैली आग को करीब-करीब बुझा दिया गया है, लेकिन घायलों और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है,।

यूक्रेन ने रोम संविधि का अनुमोदन किया

कीव। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) की रोम संविधि का अनुमोदन कर इसकी सदस्यता तथा युद्ध अपराधों के लिए रूसी अधिकारियों के खिलाफ और भी मुकदमे चलाने की संभावना खोलने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। यूक्रेन की संसद, वेरखोव्ना राडा ने बुधवार को आईसीसी संविधि का अनुमोदन करने के लिए मतदान किया। इस दस्तावेज पर यूक्रेन सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन संवैधानिक न्यायालय ने 2001 में इसके अनुमोदन को रोक दिया।

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में वर्षाजनित घटनाओं में आठ लोगों की मौत

पेशावर। उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में भारी मॉनसूनी बारिश के बीच रात भर में वर्षाजनित घटनाओं दो बच्चों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियो ने यहां बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अधिकारियों ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान, बन्नू, मानसेहरा और मोहमंद जिलो मे लगातार मूसलाधार बारिश हुई। अधिकारियो के मुताबिक बन्नू में आसमान से बिजली गिरने पर घर की छत गिर जाने से दो बहनों की मौत हो गई। डेरा इस्माइल खान जिले मे भी छत गिरने की इसी तरह की घटना मे एक महिला और उसके नाबालिग बेटे की मौत हो गई। पहाड़पुर तहसील में एक बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई।

माइक लिंच का शव जहाज के मलबे में मिला: तटरक्षक बल

पोर्टिसेलो (इटली)। ब्रिटेन के प्रौद्योगिकी कारोबारी माइक लिंच का शव सिसिली अपतटीय क्षेत्र में जहाज के मलबे से बरामद कर लिया गया। इटली के तटरक्षक बल ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी। तटरक्षक बल ने बताया कि बचाव दल ने लिंच के अलावा चार अन्य लोगों के शव भी बरामद किए है जबकि एक महिला अब भी लापता है। ब्रिटेन के झंडे वाला 56 मीटर लंबा जहाज बेयसियन सोमवार सुबह तूफान के कारण तब डूब गया जब यह समुद्र तट से लगभग एक किलोमीटर दूर खड़ा था। नागरिक सुरक्षा अधिकारियो ने बताया कि उनका मानना है कि जहाज तूफान मे फंस जाने के कारण काफी तेजी से डूबता चला गया। जहाज पर सवार 22 लोगों में से 15 लोग बच गए।

ज़ेलेंस्की ने पहली बार सीमा क्षेत्र का दौरा किया

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दो सप्ताह से अधिक समय पहले अपनी सेना के रूसी इलाके में प्रवेश करने के बाद से सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा मे बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर यूक्रेनी क्षेत्र सुमी का दौरा किया। यूक्रेन के सैन्य कमांडर के साथ एक बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बलो ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क मे एक और बस्ती पर नियंत्रण का दावा किया है तथा रूस के और अधिक सैनिको को बंदी बना लिया है। उन्होंने कहा कि बंदी बनाए गए रूसी सैनिकों को रूस द्वारा पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों की रिहाई के बदले छोड़ा जा सकता है। कुर्स्क मे यूक्रेनी सैनिकों को यह बढ़त ऐसे समय मिली है जब यूक्रेन अपने पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क में रूस से लगातार हार रहा है।

बोत्सवाना की खदान से मिला 2,492 कैरेट का विशाल हीरा

गाबोरोने (बोत्सवाना)। बोत्सवाना ने दावा किया है कि अब तक का सबसे बड़ा हीरा उसकी एक खदान से प्राप्त हुआ है और बृहस्पतिवार को इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। बोत्सवाना की सरकार का मानना है कि 2,492 कैरेट का यह विशाल रत्न देश मे खोजा गया सबसे बड़ा प्राकृतिक हीरा और किसी खदान से निकाला गया दूसरा सबसे बड़ा रत्न है।कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड कॉर्प ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने पश्चिमी बोत्सवाना में अपनी कारोवे खदान से असाधारण हीरा बरामद किया है।

यूक्रेन संघर्ष की शीघ्र, न्यायसंगत समाप्ति में अहम भूमिका निभा सकता है भारतः पोलैंड के प्रधानमंत्री

भाषा। वारसॉ

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि यूक्रेन में संघर्ष की शीघ्र और न्यायसंगत समाप्ति में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मोदी कीव की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी के साथ वार्ता के बाद अपने प्रेस वक्तव्य में टस्क ने कहा कि उन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री ने वर्तमान में पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बने मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। टस्क ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमंत्री (मोदी) ने युद्ध की शांतिपूर्ण, न्यायसंगत, शीघ्र समाप्ति के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जताई है। हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि भारत यहां (यूक्रेन में) एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। पोलिश प्रेस एजेंसी ने उन्हें उद्धृत करते हुए कहा, हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि भारत इस विषय में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम है। टस्क ने कहा कि यह घोषणापत्र विशेष महत्व रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही घंटों में कीव की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, इस यात्रा के संबंध में, हम सभी इससे सहमत हैं कि यह ऐतिहासिक महत्व का हो सकता है। वहीं, मोदी ने कहा कि भारत का दृढ़ता से मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता और यह (भारत) क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। टस्क ने कहा कि इतिहास ने दोनों राष्ट्रों को सीख दी है कि नियमों, सीमाओं, क्षेत्रीय अखंडता, देशों की संप्रभुता, कानून का शासन का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।

रूस के दक्षिणी हिस्से में स्थित सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला, लगी आग

कीव। रूस के दक्षिणी हिस्से वोल्गोग्राद क्षेत्र में स्थित एक सैन्य ठिकाने पर बृहस्पतिवार को ड्रोन से हमला किया गया जिसके बाद वहां आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर कहा कि मारिनोवका के इलाके में ड्रोन से हमला किए जाने के बाद एक सैन्य ठिकाने में आग लग गई, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बोचारोव ने यह नहीं बताया कि इस ड्रोन हमले से क्या नुकसान हुआ, लेकिन रूस के कई टेलीग्राम चैनल ने बताया कि ओक्त्यबर्स्की गांव में मारिनोवका के पास स्थित सैन्य हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया।

क्विक न्यूज

आत्मघाती हमले के बाद ट्रंप ने पहली रैली की

एशेबोरो (अमेरिका)। पिछले महीने हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना मे अपनी पहली रैली की और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया।ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना एविएशन म्यूजियम एंड हॉल ऑफ फेम में रैली को संबोधित करते हुए कहा, अब से 76 दिन बाद, हमारी जीत होगी और हम व्हाइट हाउस जीतेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर पेनसिल्वेनिया मे पिछले महीने चुनावी रैली मे एक युवक ने गोलियां चलाई थी और एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी।जिस मंच से ट्रंप संबोधित कर रहे थे, वह चारो ओर बुलेटप्रूफ ग्लास से घिरा हुआ था। कार्यक्रम स्थल की छतो पर निशानेबाजो को तैनात किया गया था। अमेरिका मे राष्ट्रपति पद के नवंबर मे प्रस्तावित चुनाव के लिए प्रचार अभियान के तहत डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में जनसभा की थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने शिकागो मे हैरिस के समर्थन मे प्रचार किया।

अमेरिका ने तिब्बतियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

वाशिंगटन। अमेरिकी सरकार की एक शीर्ष अधिकारी ने दलाई लामा से मुलाकात की और राष्ट्रपति जो. बाइडन की ओर से तिब्बतियो के मानवाधिकारों की रक्षा तथा उनके विशिष्ट ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के प्रयासो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। दलाई लामा 28 जून को घुटने की सफल रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद से न्यूयॉर्क मे स्वास्थ्य लाभ कर रहे है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता की अमेरिकी विदेश विभाग की शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक राष्ट्रपति बाइडन द्वारा एक कानून पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ महीनो बाद हुई है, जो तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाने और सुदूर हिमालय क्षेत्र की स्थिति एवं शासन संबंधी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और दलाई लामा के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की बात करता है। चीन ने फरवरी मे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा और मई मे सीनेट द्वारा पारित रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का विरोध किया था और इसे अस्थिर करने वाला बताया था।

पूरी दुनिया में छाएगी जाइस इमेजिंग की सुविधा

ग्लोबल। वीवो ने हाल ही में वी40 सीरीज़ भारत में लॉन्च की। वीवो वी40 और वी40 प्रो के साथ इसने स्मार्टफोन इनोवेशन में नया बेंचमार्क सेट किया है। पहली बार, वीवो ने प्रो और गैर-प्रो दोनों वेरिएंट पर जाइस के साथ पार्टनरशिप की है, वी सीरीज़ में शानदार कैमरा फैसिलिटी ला रहा है। अपने बेहतरीन अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, जबरदस्त प्रदर्शन और उन्नत ए आई क्षमताओं के साथ, वी40 सीरीज़ स्मार्टफोन बाजार में एक गेमचेंजर है। कैमरा एक्सीलेंस कैमरा इनोवेशन की अपनी विरासत को जारी रखते हुए, वी40 सीरीज़ अपने जाइस को-इंजीनियर्ड कैमरा सिस्टम के साथ स्मार्टफोन फोटोग्राफी को अगले लेवल तक ले जाती है। वी40 प्रो में एक वर्सिटाइल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50एमपी जाइस ओआईएस मेन कैमरा, 50एमपी अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 50एमपी टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। दूसरी ओर, वी40 में एक डुअल-कैमरा सिस्टम है जिसमें सेम 50एमपी जाइस मेन और अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा हैं। दोनों स्मार्टफोन 50एमपी जाइस ग्रुप सेल्फी कैमरा से लैस हैं, जो शानदार सेल्फी देता है। जाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड और स्टूडियो-क्वालिटी आउरा लाइट पोर्ट्रेट जैसी सुविधाएँ ओवरआल कैमरा एक्सपीरियंस को और बढ़ाती हैं।

पसंद बन रहा डिजिटल लॉक

एशिया। डिजिटल लॉक का उपयोग आपके दैनिक जीवन को आसान बनाता है जिससे आपको चाबी की चिंता किए बिना सुविधाजनक और त्वरित पहुँच मिलती है। हाफ्ले का नया आरईएएच डिजिटल लॉक आपके मुख्य दरवाजे पर आसानी से फिट हो जाता है, जो सुरक्षा और शैली का उत्कृष्ट मिश्रण है, जो सर्वोत्तम सुरक्षा के साथ प्रीमियम सौंदर्यशास्त्र प्रदान करता है। हाफ्ले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफ्ले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है। आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर औरकिचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंगए सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। हाफ्ले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन.स्टॉप.शॉप के रूप में कार्य करते हैं। इसकी आकर्षक उपस्थिति के अलावाए यह उन्नत डिजिटल लॉक कई पहुँच विकल्पों के साथ आता है।

गल्फ ऑयल ने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाई गई

गल्फ सिटी। गल्फऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड ने अपने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए ग्लोबल लीडरए सेल्सफ ोर्स को बी2बी व्यवसाय के लिए अपना नया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। सेल्सफोर्स सीआरएम का उपयोग करने का गल्फका निर्णय ग्राहक की सहभागिता और ऑपरेशनल एफिशियंसी बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के इसके उद्देश्य के अनुरूप है। अपनी व्यवसायिक प्रक्रियाओं में सेल्सफोर्स को शामिल करके गल्फका उद्देश्य ग्राहक संवादों का 360 डिग्री व्यू प्रदान करना व्यक्तिगत अनुभव सुनिश्चित करना और ग्राहक की पसंद एवं व्यवहार के आधार पर अनुकूलित मार्केटिंग संदेश प्रदान करना है। इससे गल्फबी2बी व्यवसाय में बेहतर लीड मैनेजमेंट और कस्टमर पुट की मदद से महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हो सकेगी। इस एप्लीकेशन में एडवांस्ड एनालिटिक्स और डैशबोर्ड्स संभव बनाकर निर्णय लेने की एफिशियंसी भी काफी बढ़ जाएगी। सेल्सफ ोर्स ग्राहकों के साथ बातचीत में सुधार लाने और गहरे संबंध विकसित करने के लिए डिज़ाईन किए गए अनेक टूल्स प्रदान करता है। सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म द्वारा गल्फडेटा पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत मार्केटिंग रणनीतियाँ बनाने में समर्थ हो सकेगा। रवि चावला एमडी एवं सीईओ गल्फऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड ने कहा कि हम ग्राहकों पर केंद्रित केवल मूल्य के लिए नहीं बल्कि अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रहते हैं।

ईयू मिशन के तहत फ्रांसीसी पोत ने लाल सागर में क्षतिग्रस्त तेल टैंकर से 29 नाविकों को बचाया

दुबई। लाल सागर मे संदिग्ध हूती विद्रोहियो द्वारा किए गए सिलसिलेवार हमले मे क्षतिग्रस्त तेल टैंकर पर सवार 29 नाविको को यूरोपीय संघ मिशन के तहत एक फ्रांसीसी विध्वंसक पोत ने बचा लिया है। साथ ही इलाके मे बम ले जाने वाली एक ड्रोन नौका को भी नष्ट कर दिया। अधिकारियो ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यमन के हूती विद्रोहियो पर यूनान के इस टैंकर सोयूनियन पर हमला करने का संदेह है। यह हमला, पिछले कुछ हफ्तो मे लाल सागर मे व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर किए गए हमलो मे सबसे गंभीर हमला है। यह हमला, गाजा पट्टी मे इजराइल-हमास युद्ध के दौरान जहाजों को निशाना बनाने वाले हूती विद्रोहियो के महीनो लंबे अभियान के दौरान हुआ है। इन हमलो से यह अहम व्यापार मार्ग बाधित हुआ है। इस मार्ग से हर साल करीब 1000 अरब अमेरिकी डॉलर के माल की ढुलाई होती है। यूरोपीय संघ के अभियान संचालकों ने बताया कि सोयूनियन ने लाल सागर मे लंगर डाल दिया है और अब अनियंत्रित होकर नही बह रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नही है कि जहाज मे अब भी आग लगी हुई है या नही। जहाज पर फिलीपीन और रूस के नाविक सवार थे। सैन्य अधिकारियो ने बचाव कार्य मे शामिल फ्रांसीसी विध्वंसक पोत का नाम नही बताया।

टेक्सास में 90 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनी वहां की नई पहचान

भाषा। ह्यूस्टन

ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है जो अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया अध्याय है। यह मूर्ति टेक्सास में नवीनतम पहचान बन गई है जो बहुत दूर से दिखाई देती और यह अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है।आयोजकों ने बताया कि इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इसकी कई अन्य विशिष्टताएं भी हैं: यह भारत के बाहर हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति है, टेक्सास में सबसे ऊंची मूर्ति है, अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है और इससे ऊंची मूर्तियां केवल न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (151 फुट) और फ्लोरिडा के हैलैंडेल बीच में पेगासस एंड ड्रैगन (110 फुट) ही हैं। आयोजकों ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनियन हनुमान मूर्ति का अनावरण यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर शुगर लैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 15 से 18 अगस्त तक आयोजित भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह के दौरान किया गया। उनके अनुसार, यह मूर्ति निस्वार्थता, भक्ति और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का यह नाम - स्टैच्यू ऑफ यूनियन - भगवान राम और सीता के पुनर्मिलन में हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में रखा गया है। एक बयान में आयोजकों ने कहा, "यह विस्मयकारी संरचना पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान परम पावन श्री चिन्ना जीयर स्वामीजी के दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस परियोजना को उत्तरी अमेरिका के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा था। उत्सव 15 अगस्त को शुरू हुआ, जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य भाग 18 अगस्त को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू हुआ। बयान में कहा गया, श्री चिन्ना जीयर स्वामीजी के नेतृत्व में और वैदिक पुजारियों और विद्वानों की देखरेख में किए गए अनुष्ठान, भक्ति और आध्यात्मिकता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन थे।

संयुक्त राष्ट्र की टीम प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जांच के लिए बांग्लादेश पहुंचेगी

भाषा। ढाका

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के इस्तीफे से पहले और उसके बाद कम से कम 650 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जांच के लिए बृहस्पतिवार को बांग्लादेश पहुंचेगी। अखबार डेली स्टार ने ढाका में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के हवाले से बुधवार को कहा, संयुक्त राष्ट्र की तथ्यान्वेषण टीम के आने और (अत्याचारों की) जांच करने से पहले यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की प्राथमिक टीम है। हम जांच के लिए रूपरेखा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की टीम एक जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुईं मानवाधिकार उल्लंघन की सभी घटनाओं की जांच के लिए विस्तृत नियम और शर्तों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल कम से कम एक सप्ताह तक यहां रहेगा और नागरिक समाज समूहों, मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित लोगों से मुलाकात करेगा। हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच वह पांच अगस्त को भारत भाग गईं। इससे पहले, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जुलाई के मध्य से 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने आठ अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की 16 अगस्त को प्रकाशित एक प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन और अवामी लीग सरकार के पतन के बाद हुईं घटनाओं में बांग्लादेश में लगभग 650 लोग मारे गए थे। इनमें से लगभग 400 मौतें 16 जुलाई से चार अगस्त के बीच हुईं। कहा जाता है कि अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से हटने के बाद 5 और 6 अगस्त को लगभग 250 लोग मारे गए।

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री हसीना व उनके सहयोगियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज

ढाका। बांग्लादेश में हाल ही में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में एक फेरीवाले की हत्या के संबंध में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 46 अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया। इस नए मामले के साथ ही उनके पद से हटने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 45 हो गई है।सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद अशुलिया पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।खबर में कहा गया कि पीड़ित शॉन के रिश्तेदार मोहम्मद मोजिबुल हुसैन ने ढाका की वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट राबेया सुल्ताना की अदालत में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद अशुलिया पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मामले को प्राथमिकी के रूप में स्वीकार करने को कहा। मामले के दस्तावेज के अनुसार, शॉन चार जुलाई को भेदभाव विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुआ था, जिस दौरान उसे गोली मार दी गई और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई।इस मामले के साथ, हसीना पर अब 45 मामले दर्ज हो गए हैं, जिनमें 28 हत्या के, चार मानवता विरोधी अपराध और नरसंहार के तथा एक अपहरण का मामला शामिल है। इसके अलावा, उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में सात अन्य मामले भी दर्ज हैं। हसीना छात्रों के अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा देकर पांच अगस्त को भारत चली गई थीं। हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के दौरान कुल मौतों का आंकड़ा 600 पर पहुंच गया था।

कब्ज से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है-अध्ययन

भाषा। सिडनी

अगर आप गूगल पर "कब्ज" और "दिल का दौरा" जैसे शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो एल्विस प्रेस्ली का नाम सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एल्विस को लंबे समय से पुरानी कब्ज की शिकायत थी और ऐसा माना जाता है कि वह मलत्याग करने के लिए बहुत जोर लगा रहा था, जिसके बाद उसे घातक दिल का दौरा पड़ा। हम नहीं जानते कि 1977 में तथाकथित किंग ऑफ रॉक एन रोल के साथ वास्तव में क्या हुआ था। उनकी मृत्यु में संभवत: कई योगदान कारक थे, और यह सिद्धांत कई में से एक है। लेकिन इस प्रसिद्ध मामले के बाद शोधकर्ताओं ने कब्ज और दिल के दौरे के जोखिम के बीच संबंध में गहरी दिलचस्पी ली। इसमें ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक हालिया अध्ययन शामिल है जिसमें हजारों लोगों का डेटा लिया गया है।क्या कब्ज और दिल का दौरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ?बड़ी आबादी के अध्ययन से पता चलता है कि कब्ज दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है।उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया के एक अध्ययन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 540,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें पाया गया कि कब्ज वाले मरीजों में उसी उम्र के गैर-कब्ज वाले मरीजों की तुलना में उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा अधिक था।अस्पतालों और अस्पताल के आउट पेशेंट क्लीनिकों के 900,000 से अधिक लोगों पर किए गए एक डेनिश अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लोगों को कब्ज था, उनमें दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या कब्ज और दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम के बीच यह संबंध अस्पताल के बाहर स्वस्थ लोगों के लिए सही होगा।इन ऑस्ट्रेलियाई और डेनिश अध्ययनों में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के प्रभावों को भी शामिल नहीं किया गया।

28 मिलियन कपल्स में फर्टिलिटी समस्याएं

भारत में 28 मिलियन कपल्स ऐसे हैं जो फर्टिलिटी समस्याओं से जूझ रहे हैं,और1प्रतिशत से भी कम लोग लेते हैंडॉक्टरी सलाह लेते हैं, यही वजह है कि हम इस बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ का आईवीएफ साइकिल्स का संयुक्त अनुभव का आंकड़ा 120,000 है और अब तक 230,000 पेशेंट्स का उपचार किया जा चुका है। सी.के.बिरला ग्रुप(3 बिलियन डॉलर) की कंपनी और भारत के तीसरे सबसे बड़े आई.वी.एफ (नेटवर्क बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने बेबीसाइंस आईवीएफ क्लीनिक्स का अधिग्रहण कर कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपनी पकड़मज़बूत की है। यह अधिग्रहण बिरला फर्टिलिटी और आईवीएफ की रणनीतिक विस्तार, जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश योजना के अंतर्गतएक प्रमुख कदम है।बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ नेकेरल में एआरएमसी आईवीएफ चेन का अधिग्रहण करने के तीन माह के अंदर यह कदम उठाया है। इस मौके पर, अवंति बिरला, संस्थापक, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने कहा, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ मेंहम कॉनसेप्शन के विज्ञान के साथ देखभाल (केयर) का मेल कराते हैं। मैं खुद अधिकाधिक दंपत्तियों (कपल्स) और महिलाओं के लिए इन सुविधाओं को सुलभ बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हूं। इस अवसर पर, अभिषेक अग्रवाल, चीफ बिजनेस ऑफिसर,बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ,ने कहा, कि अपनी वैश्विक विशेषज्ञता और अत्याधुनिक टेक्नॉलजी का लाभ उठाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली उत्कृष्ट प्रेग्नेंसी दर प्रदान करने के लिए, हमने भारत भर में विस्तार किया है। डॉ मंजूनाथ सीएस, फाउंडर, बेबीसाइंस् ने कहा,हम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना चुके इस ब्रैंड के साथ जुड़कर बहुत उत्साहित हैं, इससे हमारे पेशेंट्स को इंडस्ट्री में सर्वोत्तम विज्ञान का लाभ मिलेगा।इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, अक्षत सेठ, वाइस चेयरमैन, सी.के. बिरला हैल्थकेयर ने कहा, इस कदम के साथ, बिरला फर्टिलिटी और आईवीएफ, दक्षिण भारत में जागरूकता बढ़ाने और भरोसेमंदफर्टिलिटीट्रीटमेंट प्रदान करने के लक्ष्य के साथअपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा।

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट की मेजबानी

भारत के इंग्लैंड दौरे पर लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, ओवल करेंगे टेस्ट मैचों की मेजबानी

लंदन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के अपने अगले चक्र का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला के साथ करेगी, जिसका शुरुआती मुकाबला 20 जून को तेज गेंदबाजों अनुकूल हेडिंग्ले में होगा। अगला डब्ल्यूटीसी चक्र 2025 से 2027 तक चलेगा और यह वर्तमान चक्र के फाइनल के ठीक बाद शुरू होगा। मौजूदा डब्ल्यूटीसी फाइनल भी इंग्लैंड में खेला जाएगा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने रणनीतिक रूप से उन स्थानों पर मैच रखे है जहां इंग्लैंड के स्विंग गेंदबाजों को विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा टेस्ट दो से छह जुलाई तक बर्मिंघम के एजबेस्टन में होगा।तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई के बीच लॉर्ड्स मैदान पर होगा, जबकि मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड 23 से 27 जुलाई के बीच चौथे टेस्ट की मेजबानी करेगा। यह दौरा 31 जुलाई से चार अगस्त तक ओवल में अंतिम टेस्ट के साथ समाप्त होगा।श्रृंखला के पहले और दूसरे टेस्ट मे एक सप्ताह जबकि तीसरे और चौथे टेस्ट के बीच आठ दिनो का अंतराल है ताकि खिलाड़ियों को तरोताजा होने का पूरा मौका मिल सके।

लंदन। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को घोषणा की कि ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले महिला टेस्ट की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब यह मैदान इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। ईसीबी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि जुलाई 2025 में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम 2026 में एकमात्र टेस्ट के लिए वापस आएगी। भारतीय टीम अगले साल 28 जून से 12 जुलाई के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी। टीम इसके बाद क्रमशः 16 (साउथम्पटन), 19 (लंदन) और 22 जुलाई (चेस्टर ली स्ट्रीट) को तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेलेगी। ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गौल्ड ने कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारतीय महिला टीम 2026 में लॉर्ड्स में पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड की महिला टीम से भिड़ने के लिए वापसी करेगी। यह वास्तव में एक विशेष अवसर होगा। भारतीय टीम 2026 में लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच के लिए वापस आएगी। इस मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला यह पहला टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड की महिलाओं ने पिछले तीन वर्षों से लॉर्ड्स में सफेद गेंद वाले मैच खेले हैं, अगले साल एक और मैच निर्धारित है, लेकिन यह पहली बार होगा जब मैदान महिला टेस्ट मैच में भारत की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम ने अपनी सरजमीं पर पिछले साल दिसंबर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल जून–जुलाई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी सरजमीं पर खेले गए टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है।

कृष्णा का पेरिस पैरालंपिक में धैर्य और सकारात्मक खेल से स्वर्ण पदक का बचाव करने पर ध्यान

भाषा। नई दिल्ली

कृष्णा नागर को जिंदगी ने लगातार चुनौतियां पेश की हैं लेकिन इस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को अच्छे से उससे निपटना आता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अनुकूल कर लेते हैं। कृष्णा को बचपन में उनके छोटे कद के कारण चिढ़ाया जाता था लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों से इसका जवाब दिया। कृष्णा ने अपने छोटे कद को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। उन्हें पता था कि उनके लिए द्वेष रखने वालों से निपटने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था। अपने शुरुआती वर्षों में वित्तीय संघर्षों के बावजूद उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद और स्प्रिंट सहित विभिन्न खेलों में रुचि दिखाई। बैडमिंटन में उनका सफर 2017 के अंत में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से शुरू हुआ। उन्होंने तोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। इस पदक ने उनके वैश्विक खेलों की शुरुआत को यादगार बना दिया।

क्लब थ्रोअर सूरमा की नजर पैरालंपिक में पदक जीतने पर

नई दिल्ली। ऐसा अक्सर नही होता है कि जीवन बदल देने वाली दुर्घटना से अपाहिज हुआ कोई व्यक्ति उस त्रासदी को अपने लिए वरदान बना दे लेकिन जल्द ही पैरालिंपियन बनने वाले प्रणव सूरमा ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। वह तब 16 साल के थे जब 2011 में उनके घर की छत उनके ऊपर गिर गई। उनकी जिंदगी व्हील चेयर तक सिमट गई थी लेकिन उन्होने हौसला बनाए रखा और अब वह 28 अगस्त से पेरिस मे होने वाले पैरालंपिक खेलो में पदक जीतने की तैयारी में लगे हुए है। पेशे से बैंकर सूरमा ने पीटीआई से कहा, मेरी शुरू से खेलों में रुचि रही है लेकिन मैंने कभी खेल को करियर विकल्प के रूप मे नही लिया लेकिन मै हमेशा अपने जीवन मे कुछ अच्छा करना चाहता था और विडंबना यह है कि मुझे यह तब मिला जब मै लकवाग्रस्त हो गया।

मोहन बागान व ईस्ट बंगाल के बीच जोरदार मुकाबले का गवाह बनेगा लखनऊ

बाबू स्टेडियम मे खेला जाएगा मुकाबला, तैयारी

लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ पहली बार दो परम्परागत प्रतिद्वंद्वी फुटबॉल टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच जोरदार मुकाबले का गवाह बनेगा। यह मुकाबला आगामी दो सितंबर को राजधानी के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रदेश के खेल निदेशक आर. पी. सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच दो सितंबर को होने वाले इस मुकाबले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुकाबला देखने आएंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ में पहली बार देश की दो बड़ी फुटबॉल टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसमें 10 हजार दर्शकों के जुटने की सम्भावना है। मुकाबले की तैयारियों के तहत स्टेडियम में हाल ही में लगी फ्लड लाइट का परीक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम तथा अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने पिछले दिनों लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में फुटबॉल के विकास की अच्छी सम्भावनाएं बताते हुए, राज्य में इस खेल को बढ़ावा देने की जरूरत जताई थी। इस दौरान उन्होंने राजधानी में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच मुकाबला कराने का प्रस्ताव भी दिया था। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। खेल निदेशक ने बताया कि दोनों टीमें एक सितंबर को लखनऊ पहुंच जाएंगी। प्रदेश में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिहाज से यह बेहद उत्साहजनक कदम है।

इंदिरा नूई का छह साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद आईसीसी को नई महिला निदेशक की तलाश

दुबई। पेप्सिको प्रमुख इंदिरा नूई का छह साल का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को एक नई महिला स्वतंत्र निदेशक की तलाश है। मौजूद अध्यक्ष (चेयरमैन) ग्रेग बार्कले के तीसरे कार्यकाल के लिए इनकार के बाद विश्व निकाय को एक नए अध्यक्ष की भी खोज करनी होगी। नूई 2018 में ड्राफ्ट की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनीं थीं। उन्होंने अपना अधिकतम कार्यकाल पूरा कर लिया है। समझा जाता है कि आईसीसी बोर्ड ने पहले ही नूई जैसे हाई-प्रोफाइल नाम की तलाश शुरू कर दी है जो कॉर्पोरेट जगत में सबसे चर्चित चेहरों में से एक थी। आईसीसी नियमों के मुताबिक, निदेशक मंडल एक व्यक्ति का चुनाव करेगा जो एक महिला होनी चाहिए और जिसे निदेशक पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रिकेट के खेल में समानता, विविधता और समावेशिता हितों का समय-समय पर उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

नवारो मॉन्टेरी ओपन के क्वार्टर फाइनल में

मॉन्टेरी (मैक्सिको)। अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त एम्मा नवारो ने गुरुवार को यहां तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 3-6, 7-5, 7-6 (2) से हराकर मॉन्टेरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नवारो हार्ड कोर्ट पर खेली जा रही इस डब्ल्यूटीए 500 प्रतियोगिता के अंतिम आठ में पोलैंड की नौवी वरीयता प्राप्त मैग्डेलेना फ्रेच से भिड़ेंगी जिन्होंने एक अन्य मैच में लीना ग्लुशको को 6-7 (2), 6-3, 6-1 से हराया। इससे पहले बुधवार को तीसरी वरीयता प्राप्त एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने स्थानीय खिलाड़ी रेनाटा ज़राज़ुआ को 6-3, 6-4 से हराया। अलेक्जेंड्रोवा का सामना सातवी वरीयता प्राप्त चीन की यू युआन से होगा, जिन्होंने पेट्रा मार्टिच को 6-4, 6-1 से पराजित किया।

शिवानी जिला ओपन तैराकी 1 सितंबर को

लखनऊ। लखनऊ एमेच्योर तैराकी एसोसिएशन के तत्वावधान में शिवानी पब्लिक स्कूल द्वारा प्रथम शिवानी जिला ओपन तैराकी चैंपियनशिप आगामी 1 सितंबर 2024 को भारतीय खेल प्राधिकरणए क्षेत्रीय केंद्र साई लखनऊ सरोजनीनगर लखनऊ के तरणताल में आयोजित होगी। शिवानी ग्रुप के सीईओ सुधीर दुबे व लखनऊ एमेच्योर तैराकी एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन कपूर ने बताया कि इस चैंपियनशिप के दौरान कुल 40 स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें ग्रुप 1 अंडर-17, ग्रुप 2 अंडर.14 ग्रुप 3 अंडर.11ग्रुप4,अंडर-9 और ग्रुप 5 अंडर-7 वर्ग में बालक व बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

विद्याधर और कार्तिक ने वारियर्स को दिलाई जीत

बेंगलुरु। विद्याधर पाटिल और सीए कार्तिक की कसी गेंदबाजी की बदौलत मैसूर वारियर्स ने गुरुवार को यहां महाराजा ट्राफी केएससीए टी20 मे शिवामोगा लायंस पर 28 रन की आसान जीत दर्ज की। लायंस की टीम 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 151 रन पर सिमट गई जिसमे विद्याधर ने 29 रन देकर तीन और कार्तिक ने 31 रन देकर तीन विकेट झटके। मैसूर वारियर्स ने कप्तान करुण नायर के 45 रन, जे सुचित के 22 रन और मनोज भंडागे ने 23 रन की बदौलत अच्छा स्कोर खड़ा किया। कार्तिक ने भी 30 रन की पारी खेली। लायंस के तेज गेंदबाज एच एस शरत ने 29 रन देकर चार विकेट चटकाकर अच्छा स्पैल डाला लेकिन वारियर्स की टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने मे सफल रही।

इनफोक्स इंडिया पब्लिक स्कूल सुब्रतो कप सब जूनियर क्वार्टरफाइनल में

बेंगलुरु पश्चिम बंगाल के इनफोक्स इंडिया पब्लिक स्कूल ने गुरुवार को यहां मिजोरम के गवर्नमेंट चांगफिंगा मिडिल स्कूल को 2-0 से हराकर 63वें सुब्रतो कप सब जूनियर लड़कों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल मे प्रवेश किया। ग्रुप एच के इस मैच में विजेता टीम के लिए प्रीतम और राजदीप ने गोल दागे। झारखंड के जेएनवी ने ग्रुप डी मे हिमाचल प्रदेश के मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल को 2-1 से मात दी।

मीराबाई चानू और नीलकंत शर्मा सम्मानित

इंफाल। पेरिस ओलंपिक मे भाग लेने वाली भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू और हॉकी खिलाड़ी नीलकांत शर्मा को बुधवार को यहां मणिपुर पुलिस ने सम्मानित किया। यहां जारी बयान के अनुसार पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने यहां एक समारोह मे मीराबाई और नीलकांत को सम्मानित किया।

कभी कभार थोड़े से भाग्य की जरूरत होती है : द्रविड़

भाषा। मुंबई

महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ मानते हैं कि कभी कभी थोड़ी सी किस्मत भी बड़े मैच के नतीजों को प्रभावित कर सकती है जिसके लिए उन्होंने वनडे विश्व कप फाइनल में भारत को आस्ट्रेलिया से मिली दिल तोड़ने वाली हार और अपनी टीम की टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत का उदाहरण दिया। भारत पिछले साल लगातार 10 मैच में जीत के बाद वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचा था लेकिन टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम जब खिताबी मुकाबले में आस्ट्रेलिया से भिड़ी तो उसके लिए कुछ भी कारगर नहीं रहा। छह महीने बाद कप्तान रोहित शर्मा और द्रविड़ ने मिलकर अधूरी कसर पूरी की। टी20 विश्व कप फाइनल में मजबूत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस्मत ने भारतीय टीम का साथ दिया। द्रविड़ ने बुधवार को याद किया कि टीम के लिए 29 जून को बारबाडोस में हुए फाइनल में एक निश्चित प्रक्रिया पर डटे रहना और भाग्य का साथ देने की उम्मीद रखना कितना महत्वपूर्ण था। द्रविड़ को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा, मुझे इस पर विचार करने का समय मिला। मुझे उन बहुत सी चीजों को सोचने का समय मिला जो हमने की। आपको कभी कभी अहसास होता है कि आपको इनमें से बहुत सी चीजें करनी होती हैं, आपको प्रक्रिया का पालन करना होता है, आपको सब कुछ सही करना होता है। द्रविड़ ने कहा, कभी कभी आपको थोड़े भाग्य की जरूरत होती है। टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 गेंद फेंकी जानी थी और 30 रन बनाने थे। तब रोहित के बेहतरीन तरीके से रणनीति के कार्यान्वयन और संयम रखने की बात थी। उन्होंने डेविड मिलर को आउट करने के लिए सूर्यकुमार यादव के सीमा रेखा पर लपके हुए कैच का जिक्र किए बिना कहा, हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो एक निश्चित सीमा के अंदर ऐसा कर सके। कभी यह कौशल होता है।

आस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम के लिए अहम होंगे पंत : हेडन

मुंबई। महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को लगता है कि जब भारतीय टीम पांच टेस्ट की श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी तो ऋषभ पंत उसके लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे क्योंकि पिछले दौरे पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज की जीत की भूख शानदार रही थी। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच यह पांच मैच की श्रृंखला 22 नवंबर से पर्थ मे शुरू होगी। हेडन ने बुधवार को यहां सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के मौके पर पत्रकारो से कहा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के अंदर जीत की भूख है और उसकी मसल मेमरी (प्रक्रियात्मक स्मृति) शानदार है। पिछली बार जब वह वहां खेला था तो वह अहम खिलाड़ी रहा था और आस्ट्रेलिया के दर्शकों को भी उसका खेल काफी पसंद आया था। उन्होने कहा, पंत का खेल रोमांचक और बेहतरीन रहा था। फिर आपके पास अनुभवी खिलाड़ी जैसे विराट कोहली है जो फिर से अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। बल्लेबाजी को देखते हुए मै यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि भारत आस्ट्रेलियाई सरजमी पर उससे भिड़ने के लिए किस तरह की रणनीति बनाएगा।

मीनू-प्रिया ने आस्ट्रेलिया ए को दिया झटका

भारत ए ने महज 212 रन पर समेटा

भाषा। गोल्ड कोस्ट (आस्ट्रेलिया)

स्पिनर मीनू मणि के पांच और प्रिया मिश्रा के चार विकेट की मदद से भारत ए महिला टीम ने गुरुवार को यहां चार दिवसीय एकमात्र महिला अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन आस्ट्रेलिया ए को पहली पारी मे महज 212 रन पर समेट दिया। कप्तान और ऑफ स्पिनर मीनू ने 58 रन देकर पांच और लेग स्पिनर प्रिया ने 58 रन देकर चार विकेट झटके जिससे आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी इकाई ने सभी 10 विकेट गंवा दिए।भारत ए ने स्टंप तक दो विकेट गंवाकर 100 रन बना लिए जिससे वह 112 रन से पिछड़ रही है। आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय स्पिनरो के सामने संघर्ष करती नजर आई। सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (71 रन, 95 गेंद, 12 चौके) ने तेजी से रन बटोरे लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर मन्नत कश्यप का शिकार बन गईं जिसके बाद आस्ट्रेलियाई टीम ने 94 रन तक चार विकेट गंवा दिए थे। फिर निचले क्रम की बल्लेबाजी मैतलान ब्राउन (30 रन) और ग्रेस पार्सन्स (35 रन) ने मेजबानो को 200 रन के पार कराया।।

सिंकफील्ड कप: गकेश ने प्रज्ञाननंदा के खिलाफ बाजी ड्रॉ खेली

सेंट लुई (अमेरिका)। विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम टूर्नामेंट सिंकफील्ड कप के तीसरे दौर में हमवतन आर प्रज्ञाननंदा के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में होने के बावजूद बाजी ड्रॉ कराई। एक समय लग रहा था कि यह बाजी आसानी से ड्रॉ हो जाएगी लेकिन तभी गुकेश गलती कर बैठे। प्रज्ञाननंदा हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए और आखिर में दोनों भारतीय खिलाड़ी अंक बांटने पर सहमत हो गए। यह दोनों अभी समान 1.5 अंक लेकर संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञाननंदा ने 2022 के बाद क्लासिकल बाजी में गुकेश को नहीं हराया है। फ्रांस के अलीरेज़ा फ़िरोज़ा ने भी कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद हमवतन मैक्सिम वाचिएर–लाग्रेव के खिलाफ बाजी ड्रॉ कराई। फिरोजा दो अंक लेकर रूस के इयान नेपोम्नियाचची के साथ अभी शीर्ष पर बने हुए हैं। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसात्तोरोव भी अच्छी स्थिति में दिख रहे थे लेकिन उन्हें एक गलती बेहद महंगी पड़ी जिसका फायदा उठाकर फैबियानो कारूआना टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफल रहे।तीसरे दौर में दूसरे विजेता नेपोम्नियाचची थे, जिन्होंने नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ अपेक्षाकृत आसान जीत हासिल की।

किशोर ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में उम्मीदें बरकरार रखी, हरीश बाहर

माले (मालदीव)। हरीश मुथु को यहां एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के पुरुष ओपन वर्ग के क्वार्टर फाइनल में तीसरे स्थान पर रहकर निराशा का सामना करना पड़ा जबकि किशोर कुमार ने अंडर-18 वर्ग मे अंतिम आठ चरण के लिए क्वालीफाई किया। मुथु और किशोर दोनो प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण मे पहुंचने वाले पहले भारतीय है जो 2026 एशियाई खेलो के लिए क्वालीफाइंग स्पर्धा है। यहां थुलुस्धू मे आयोजित प्रतियोगिता के चार श्रेणियो मे आठ भारतीय सर्फर प्रतिस्पर्धा कर रहे है। तमिलनाडु के हरीश को क्वार्टर फाइनल मे इंडोनेशिया की जोई सतरियावान और जापान के काइसेई अडाची से कड़ी टक्कर मिली। इन दोनो ने क्रमशः पहले और दूसरे स्थान स्थान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया जबकि

आदित्य,अयान, प्रांजल व दिव्यांशु फाइनल में

सीआईएससीई-यूपी-यूकेरीजनल बाक्सिंग टूर्नामेंट

लखनऊ। लखनऊ जोन ए के आदित्य सिंह अलेरिया, मोहम्मद अयान खान, प्रांजल जोशी, दिव्यांशु बिष्ट ने सीआईएससीई यूपीयूके रीजनल बाक्सिंग टूर्नामेंट में अपने-अपने वर्गों में सेमीफ इनल मुकाबलों में जीत के साथ फाइनल में स्थान सुरक्षित किया। सेंट थॉमस मिशन हाईस्कूल, लखनऊ द्वारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाक्सिंग हाल में आयोजित तीन दिवसीय टूर्नामेंट के पहले दिन लखनऊ जोन बी के अविरल गुप्ता, उन्नत गुप्ता, यजदान ने भी सेमीफ इनल में जीत दर्ज की। टूर्नामेंट का उद्घाटन आज मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्जवलन करके किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत स्कूल के प्रबंधक फादर जयसन जोसेफ ने पुष्पगुच्छ भेंटकर किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्या डाक्टपम दुबे तथा लखनऊ के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अजय कुमार सेठी की भी गरिमामयी मौजूदगी रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने अपने आर्शीवचन में कहा कि खेल का आज जीवन में महत्व काफी बढ़ गया है। इसी के चलते अब ये कहा जाने लगा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे, तब भी बनोगे नवाब। पहले दिन खेले गए अंडर.14 आयु वर्ग के सेमीफइनल मुकाबलों में 34.36 किग्रा में कानपुर उत्तर के अक्षत सिंह ने कानपुर दक्षिण के आर्यन द्विवेदी को व लखनऊ जोन ए के आदित्य सिंह अलेरिया ने मेरठ के नुकुल को हराया। 28–30 किग्रा भार वर्ग में लखनऊ जोन बी के अविरल गुप्ता ने कानपुर दक्षिण जोन के अहद खान को व मेरठ के अमन ने कानपुर उत्तर के अर्णव मिश्रा को हराया। 30–20 किग्रा वर्ग में लखनऊ जोन बी के उन्नत गुप्ता ने कानपुर दक्षिण के अग्रज पाण्डेय को व लखनऊ जोन ए के मोहम्मद अयान खान ने कानपुर उत्तर के अंकित मिश्रा को हराया। 40.42 किग्रा में मेरठ के इंद्रजीत सिंह ने कानपुर दक्षिण के प्रथम शुक्ला को व लखनऊ जोन ए के दिव्यांशु बिष्ट ने कानपुर उत्तर के रेहान अख्तर को हराया। 48.50 किग्रा भार वर्ग में कानपुर उत्तर के शौर्य वर्द्धन ने कानपुर दक्षिण के मयंक यादव को व मेरठ के अक्षत दीक्षित ने लखनऊ जोन ए के अक्षत द्विवेदी को हराया। इसके अलावा अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में 36.38 किग्रा में लखनऊ जोन ए के प्रांजल जोशी ने कानपुर उत्तर के क्षितिज मिश्रा कोए 42.44 किग्रा में कानपुर उत्तर के वैभव कुमार शर्मा ने कानपुर दक्षिण के विनायक तिवारी कोए 44.46 किग्रा में मेरठ के अणर्व सिंह ने कानपुर दक्षिण के सूर्यांश कुमार को व 46.48 किग्रा में लखनऊ जोन बी के यजदान ने लखनऊ जोन ए के मयंक चौरसिया को हराया।

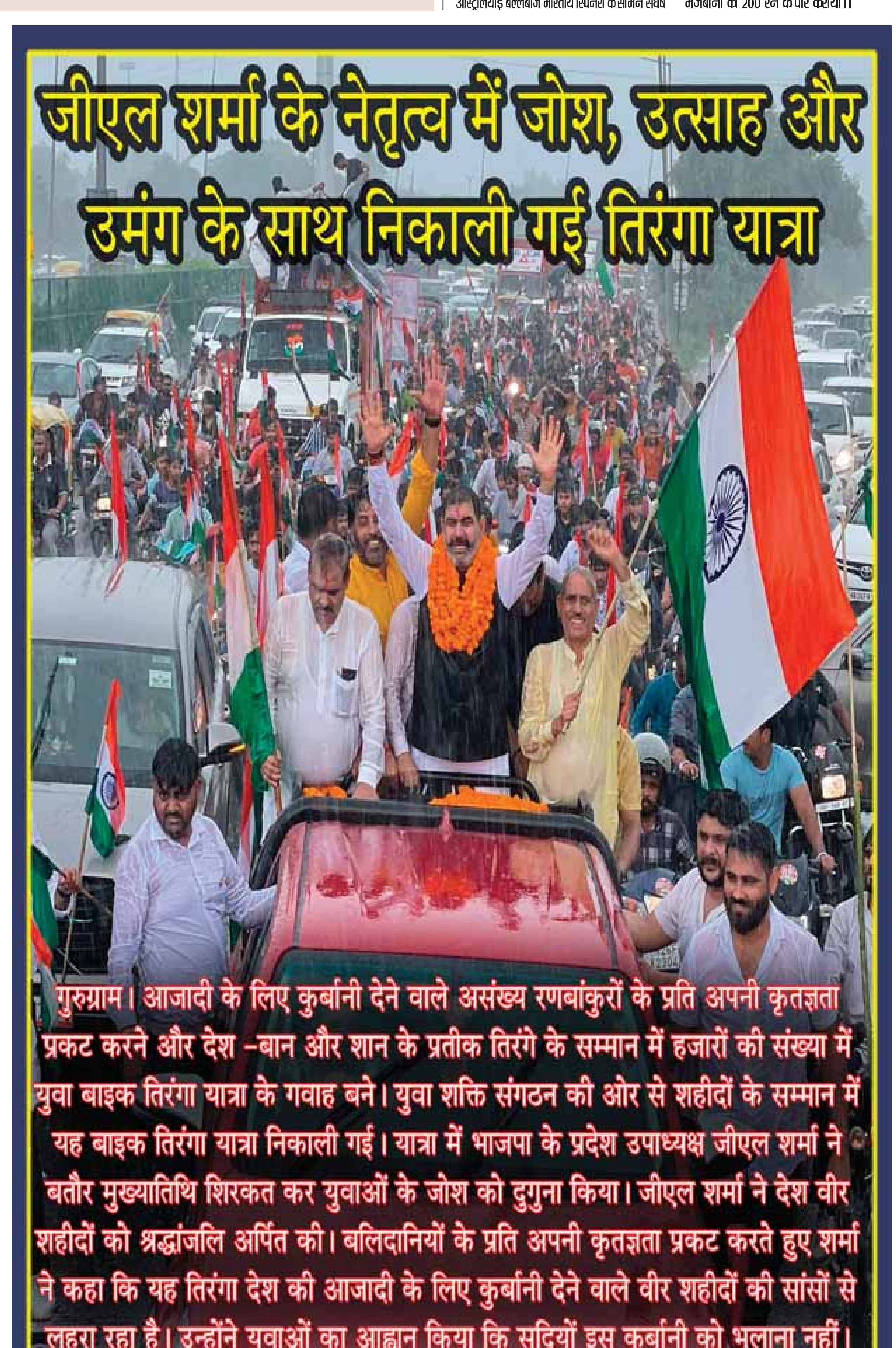

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड,ए-8, सेक्टर-7, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201301, दूरभाष-01202470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5,बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।